चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 03 मार्च–09 मार्च 2014 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

अर्थनीति तय करेगी देश की राजनीति

2 जी घोटाले में जब ए राजा पकड़े गए, तो कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दो साल तक कहते रहे कि कोई घोटाला नहीं हुआ है. कोयला घोटाले में जब मनमोहन सिंह का नाम आया, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह नीतिगत फ़ैसला है. मजेदार बात यह है कि विपक्षी पार्टियों ने भी इन मामलों को जोर-शोर से नहीं उठाया. यह तो अदालत है, जिसकी वजह से इन घोटालों के गुनहगारों को सजा मिल रही है. हकीकत यह है कि राजनीतिक दल लोगों को बरगलाने में लगे हैं. नेता सफेद झूठ बोल रहे हैं. मीडिया भ्रम फैला रहा है. विकल्प का नाटक किया जा रहा है. महंगाई, भ्रष्टाचार, भूख, बेरोज़गारी एवं किसानों की आत्महत्या का मूल कारण मनमोहन सिंह की नव-उदारवादी नीतियां हैं. सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री का बदल जाना विकल्प है? क्या एक पार्टी की सरकार हटाकर किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में बैठा देना विकल्प है? सही मायने में विकल्प का मतलब होता है वैकल्पिक नीतियां. महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी एवं भूख आदि समस्याओं से निजात पाने के लिए नव-उदारवादी नीतियों को ख़त्म करना ज़रूरी है. इसलिए 2014 के चुनाव में नेताओं और पार्टियों को नहीं, देश की जनता को आर्थिक नीति पर फ़ैसला करना होगा. नव-उदारवादी नीतियों को समाधान बताने वाली पार्टियों को सबक सिखाना होगा.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

मनीष कुमार

लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है. कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वामपंथी हों, क्षेत्रीय दल हों या फिर आम आदमी पार्टी, सबने जातीय समीकरण और हिंदू-मुस्लिम वोटों के जोड़-तोड़ को ध्यान में रखते हुए अपनी सूची तैयार कर ली है. कई उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और कई लोगों के नाम आने बाकी हैं. हर तरफ़ होड़ लगी हुई है. रैली, घोषणाएं, मीटिंग, पैसों का लेन-देन, पोस्टर, होर्डिंग, पर्चे एवं सोशल मीडिया, हर तरफ़ चुनाव का माहौल है. इस चुनाव में अरबों रुपये फूंक दिए जाएंगे, लेकिन चुनाव के इस कोलाहल में सबसे बड़ा सवाल अभी भी रहस्यमय तरीके से गुप्त है. यह सवाल लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा है. यह सवाल ग़रीबों के शोषण एवं वंचितों के विकास से जुड़ा है. यह सवाल नौज़वानों के रोज़गार से जुड़ा है. देश के जल, जंगल, जमीन के भविष्य से जुड़ा है. यह सवाल देश के प्रजातंत्र के अस्तित्व से जुड़ा है. शर्मनाक बात यह है कि इस सबसे बड़े सवाल पर हर दल ने चुप्पी साध रखी है.

इस देश की सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि राजनीतिक दलों और देश चलाने वाले नेताओं ने समस्या को ही समाधान समझ लिया है. जिन आर्थिक नीतियों की वजह से इस देश में ग़रीब और ज़्यादा ग़रीब होते जा रहे हैं और अमीर बेतहाशा अमीर, जिन नीतियों की वजह से देश के प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है, जिन नीतियों की वजह से विकास सिर्फ़ आंकड़ों में नज़र आता है, जिन नीतियों की वजह से देश के नौज़वान बेरोज़गार घूम रहे हैं, जिन नीतियों की वजह से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, जिन नीतियों की वजह से मज़दूरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, उन्हीं नव-उदारवादी नीतियों को देश के अधिकांश दलों ने एकमात्र विकल्प मान लिया है. भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या फिर नई-नई बनी आम आदमी पार्टी, इन सबकी आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये सब एक स्वर में कहते हैं कि रोज़गार या नौकरी देना सरकार का काम नहीं है. सरकार का काम व्यापार करना नहीं होता है. यह काम उद्योग जगत का है. समझने वाली बात यह है कि ये लोग देश की अर्थव्यवस्था को बाज़ार के हाथों बंधक बनाने पर तुले हैं. बाज़ारवाद की व्यवस्था का हश्र दुनिया के कई देशों में देखा जा रहा है. यह तो भारत है, जहां के किसान अपनी मेहनत से इतना अनाज पैदा कर देते हैं कि देश में खाने-पीने की किल्लत नहीं है, वरना इन बीस सालों में भारत की हालत भूख से मर रहे अफ्रीकी देशों की तरह हो गई होती.

> **राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ-साथ गांवों से पलायन रोकना भी सरकार की ज़िम्मेदारी है. आज किसान को खेती करने से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, उसे उपज की उचित क़ीमत नहीं मिलती है, उसे नुकसान हो रहा है. किसान जमीन बेचकर शहरों में नौकरी करने को मजबूर है.**

यूपीए सरकार ने घोर बाज़ारवादी व्यवस्था लागू करने की नीति पर दस साल गुजारे हैं. लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है. मीडिया भी बाज़ारवादी व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है, इसलिए वह असलियत सामने लाने में असमर्थ है. हकीकत यह है कि लोग बाज़ार और पूंजीवाद के इशारे पर नाचने वाली व्यवस्था से निजात पाना चाहते हैं, लेकिन देश के सामने कोई विकल्प नहीं है. भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का भी तर्क अजीब है. नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यूपीए इसलिए विफल हुई, क्योंकि वह बाज़ारवादी व्यवस्था को सही ढंग से लागू नहीं कर सकी. कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी वादा कर रहे हैं कि जब वह आएंगे, तो बाज़ारवादी व्यवस्था को सही ढंग से लागू करेंगे. इसका मतलब साफ़ है कि वही महंगाई, वही भ्रष्टाचार, वही बाज़ारवाद का साम्राज्य फैलेगा. बाकी दलों का जिक्र करना भी बेमानी है, क्योंकि उनकी न तो कोई नीति है और न देश के प्रति कोई ज़िम्मेदारी. समझने वाली बात यह है कि जिस आर्थिक नीति की पैरवी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कर रही हैं, वही नीति देश में महंगाई की मुख्य वजह है. सरकार हर महत्वपूर्ण वस्तुओं को

> **भारत यूरोप के देशों से काफी अलग है. भारत अफ्रीकी और अमेरिकी देशों से भी भिन्न है. यहां का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश भी भिन्न है, इसलिए आंख बंद करके दूसरे देशों की नीतियां एवं योजनाएं यहां लागू करना अच्छा फ़ैसला नहीं है. इससे नुकसान होता है.**

अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रही है. जब सरकार का अधिकार ही नहीं रहा, तो महंगाई पर नियंत्रण कौन और कैसे करेगा? मनमोहन सिंह लगातार महंगाई पर रोक लगाने की बात कहते आए, लेकिन सरकार कभी भी इसे रोक नहीं सकी. इसकी वजह भी यही है कि जब सब कुछ बाज़ार के हवाले हो जाता है, तो सिर्फ़ टीवी चैनलों की बहस में महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन असलियत यही है कि बाज़ार में क़ीमतें सिर्फ़ ऊपर की ओर जाती हैं. अगर नीति ही जनविरोधी हो, तो यह फर्क नहीं पड़ता है कि उसे लागू करने वाला कौन है. राहुल हों या मोदी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यही वजह है कि जब इन अहम मुद्दों को लेकर अन्ना हजारे ने सारी राजनीतिक पार्टियों को खत लिखा, तो किसी ने जवाब नहीं दिया.

नव-उदारवादी नीतियां न सिर्फ़ महंगाई को बेलगाम करती हैं, बल्कि वे भ्रष्टाचार की भी जननी हैं. यूपीए के 10 सालों में इतने घोटाले हुए कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा बन गया है. इस दौरान अनगिनत घोटाले इसलिए हुए, क्योंकि इसमें सरकार, नेताओं एवं अधिकारियों ने कॉरपोरेट जगत के साथ मिलकर नीतिगत फ़ैसले के जरिये प्राकृतिक संसाधनों की लूट की है. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को निजी कंपनियों के हवाले करने पर अविलंब रोक लगनी चाहिए, साथ ही विदेश में जमा कालेधन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर उसे वापस लाने की भी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए. 1991 के बाद से जिस तरह भ्रष्टाचार ने पूरी सरकारी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उससे संवैधानिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए. भ्रष्टाचार इसलिए भी मुद्दा बना, क्योंकि अन्ना हजारे ने 2011 से भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की. पूरा देश तिरंगा लेकर और मैं अन्ना हूं की गांधी टोपी पहन कर सड़क पर उतर आया. लोगों ने अन्ना का साथ इसलिए दिया, क्योंकि यूपीए शासन में भ्रष्टाचार पहली बार पंचायत और गांवों के स्तर पर जा पहुंचा. अन्ना के आंदोलन और जनतंत्र यात्रा के जरिये जनजागरण ने असर दिखाया और आख़िरकार सरकार को लोकपाल क़ानून बनाना पड़ा. वैसे अभी कई क़ानून बनने बाकी हैं. देश की जनता की बहुत ज़्यादा मांगें नहीं हैं और भ्रष्टाचार पर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

संविधान के ख़िलाफ़ है हमारी मौजूदा आर्थिक नीति 03

किसानों की दुश्मन है कांग्रेस 05

दिल्ली की डगर: कुछ इधर, कुछ उधर 06

साई की महिमा 12

अर्थनीति तय करेगी देश की राजनीति

पृष्ठ एक का शेष

काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है, अगर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, सिटीजन चार्टर बिल और व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा हेतु क़ानून पास किया जाए. साथ ही देश में चुनाव संबंधी सुधार लाने की आवश्यकता है, जैसे कि राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल. विदेश और देश की सुरक्षा के मामलों को छोड़कर सरकार के हर फ़ैसले की फाइल को 2 साल के बाद सार्वजनिक कर देने से शीर्ष स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार का खात्मा हो सकता है. लेकिन समझने वाली बात यह है कि 2014 के बाद अगर बाज़ार की पैरवी करने वाली सरकार आ गई, तो न कभी पारदर्शिता आएगी और न ही भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकेगा.

कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही पार्टियां ऐसी आर्थिक नीतियों की पैरवी करती हैं, जिनसे शहर और गांव के विकास में विषमता पैदा होती है. भारत में अभी तक इस विषमता के दुष्परिणामों को नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन अगर अब इसे टाला गया, तो देश अराजकता की ओर बढ़ सकता है. वैसे भी आज़ादी के इतने सालों बाद अब वक्त आ गया है कि प्रजातंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाया जाए. ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का वक्त आ गया है. गांवों को स्थानीय प्रशासन में स्वायत्ता देने की ज़रूरत है. इसकी शुरुआत पंचायत को ग्रामसभा के प्रति ज़िम्मेदार बनाने से हो सकती है. यह व्यवस्था वैसी हो, जिस तरह से केंद्र और राज्यों में मंत्रिमंडल लोकसभा और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है. गांवों के सशक्तिकरण सबसे सशक्त क़दम साबित हो सकता है. इससे भारत में न सिर्फ़ प्रजातंत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि सरकार का बोझ भी कम होगा.

राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ-साथ गांवों से पलायन रोकना भी सरकार की ज़िम्मेदारी है. आज किसान को खेती करने से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, उसे उपज की उचित क़ीमत नहीं मिलती है, उसे नुकसान हो रहा है. किसान जमीन बेचकर शहरों में नौकरी करने को मजबूर है. किसानों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले देश में उनकी उपजाऊ जमीनें छीनकर निजी कंपनियों को देने की नीतियों पर प्रतिबंध लगाना होगा, साथ ही कृषि का आधुनिकीकरण और उसे उद्योग से जोड़ना ज़रूरी है. किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें वक्त पर पानी नहीं मिलता है. इससे निपटने के लिए नदियों एवं जलाशयों के निजीकरण पर रोक और जल संचय की योजनाएं लागू करके शहर के साथ-साथ गांवों में पीने एवं सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना आवश्यक है. साथ ही गांव को इकाई मानकर कृषि आधारित उद्योगों की योजना लागू करना भी ज़रूरी है, ताकि गांवों में ही रोज़गार के अवसर मिल सकें. अगर देश के गांव खुशहाल हो गए, लोगों का पलायन रुक गया, तो देश की कई समस्याओं का एक ही झटके में हल हो सकता है. अफसोस इस बात का है कि गांवों को खुशहाल बनाने वाली नीतियों के बारे में राष्ट्रीय दलों के नेता झूठी दिलासा भी नहीं दे रहे हैं.

राजनीतिक दलों की मानसिकता में एक बहुत बड़ी कमी है. उन्हें लगता है कि सब्सिडी या सीधे पैसे देकर जनता को खुश किया जाना ही सबसे सही रास्ता है. राजनीतिक दल नीतियों के अभाव में एक रुपये किलो चावल, तो कभी टीवी सेट या कभी कर्ज माफी का खेल खेलते हैं. इस बार तो सीधे बैंक एकाउंट में पैसे जमा करने की नीति से लोगों को फुसलाने की कोशिश हुई है. अब इन राजनीतिक दलों को कौन समझाए कि इन पैसों का इस्तेमाल अगर अत्याधुनिक मूलभूत ढांचे को बनाने में किया गया होता, तो देश के लोग सरकार की मदद के बगैर खुद ही स्वावलंबी बन गए होते. लोक-लुभावन चुनावी नीतियों के बजाय अगर इन पैसों का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं में किया गया होता, तो देश के हर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जातीं, लेकिन सरकार की यह प्राथमिकता नहीं रही. आज हालत यह है कि देश के कई जिला मुख्यालयों में सीटी स्कैन और एक्सरे करने तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है. सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल व्यवस्था को सुधारने में होना चाहिए. जो पैसा मनरेगा जैसी योजनाओं में बर्बाद हो गया, अगर उससे हर गांव में सौर ऊर्जा के यूनिट लगा दिए गए होते, तो देश के लाखों गांव ऊर्जा के क्षेत्र में काफी हद तक स्वावलंबी हो गए होते और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता.

इन सबके अलावा, देश के दबे-कुचले वर्ग के लिए स्पेशल पैकेज बनाने की ज़रूरत है. देश में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई है. कांग्रेस पार्टी ने हर चुनाव से पहले मुसलमानों को बरगलाने के लिए नौकरी में आरक्षण का झांसा दिया और हर चुनाव के बाद उन्हें भूल गई. वैसे तो धर्म के नाम पर आरक्षण देना संवैधानिक तौर पर गलत है, लेकिन हर समुदाय के ग़रीबों एवं वंचितों की मदद करना सरकार का दायित्व है. बावजूद इसके, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इस मामले को ऐसा उलझा कर रखा है कि यह सांप्रदायिक रंग ले लेता है. सिर्फ़ अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ऐसी शिक्षा नीति की ज़रूरत है, जो सीधे रोज़गार से जुड़ती हो. पढ़-लिखकर बेरोज़गार बनाने वाली शिक्षा नीति से देश का ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है.

> **राजनीतिक दलों की मानसिकता में एक बहुत बड़ी कमी है. उन्हें लगता है कि सब्सिडी या सीधे पैसे देकर जनता को खुश किया जाना ही सबसे सही रास्ता है. राजनीतिक दल नीतियों के अभाव में एक रुपये किलो चावल, तो कभी टीवी सेट या कभी कर्ज माफी का खेल खेलते हैं. इस बार तो सीधे बैंक एकाउंट में पैसे जमा करने की नीति से लोगों को फुसलाने की कोशिश हुई है. अब इन राजनीतिक दलों को कौन समझाए कि इन पैसों का इस्तेमाल अगर अत्याधुनिक मूलभूत ढांचे को बनाने में किया गया होता, तो देश के लोग सरकार की मदद के बगैर खुद ही स्वावलंबी बन गए होते.**

प्रजातंत्र में समय-समय पर चुनाव इसलिए होते हैं, ताकि जनता इस बात का फ़ैसला कर सके कि सरकार किन नीतियों पर चले. राजनीतिक दलों के शासन का जनता अपने हिसाब से आकलन करती है. जो सरकारें जनता की समस्याओं का समाधान निकालने में सफल नहीं होतीं, उन्हें जनता खारिज कर देती है, सत्ता से बाहर कर देती है. मीडिया का रोल सच्चाई को सामने लाना होता है, ताकि पता चल सके कि सरकार ने असल में क्या-क्या काम किए हैं, लेकिन 2014 के चुनाव में मीडिया और राजनीतिक दल लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं.

भारत यूरोप के देशों से काफी अलग है. भारत अफ़्रीकी और अमेरिकी देशों से भी भिन्न है. यहां का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश भी भिन्न है, इसलिए आंख बंद करके दूसरे देशों की नीतियां एवं योजनाएं यहां लागू करना अच्छा फ़ैसला नहीं है. इससे नुकसान होता है. मनमोहन सिंह की वजह से 1991 के बाद से भारत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की नीतियों पर अंधाधुंध चल रहा है. कुछ लोगों को यह लगता है कि कई क्षेत्रों में विकास हो रहा है. विकास का यही एकमात्र रास्ता है. ऐसा आकलन गलत है. देश की समस्याएं पहले से जटिल होती जा रही है. हिंदुस्तान आर्थिक एवं सामाजिक संकटों के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है. कुछ तो सामने नज़र आ रहे हैं, कुछ कैंसर की तरह अभी छिपे हैं. 1991 के बाद से नक्सलवादी आंदोलन मजबूत हुआ है. यह 40 जिलों से बढ़कर 250 जिलों तक पहुंच चुका है. देश में युवाओं की संख्या बढ़ रही है, साथ ही बेरोज़गारी बढ़ रही है. अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान देश की मुख्य धारा से तो पहले ही अलग-थलग थे, अब वे आर्थिक रूप से भी कमजोर हो रहे हैं. महिलाओं के ख़िलाफ़ अत्याचार बढ़ रहा है. हिंसा बढ़ रही है. सरकारी तंत्र विफल हो रहा है. राजनीतिक नेताओं की साख ख़त्म हो रही है. इसकी वजह यह है कि देश की जनता की समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही हैं और देश चलाने वाले बौने साबित होते जा रहे हैं. न सोच, न विचारधारा, न नीति, न विश्वास और न दूरदर्शिता. हर सरकार एक ही नीति चला रही है. समस्याओं को ख़त्म करने की किसी नई सोच का सृजन नहीं हो रहा है. चेहरे बदलने से समस्याएं ख़त्म नहीं होतीं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बदलने से कुछ भी नहीं बदलता है, इसलिए देश की जनता को 2014 के चुनाव में आर्थिक नीतियों के आधार पर ही फ़ैसला लेना होगा. देश को अराजकता और गृहयुद्ध से बचाने का यही एकमात्र उपाय है.■

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 52
दिल्ली, 03 मार्च-09 मार्च 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

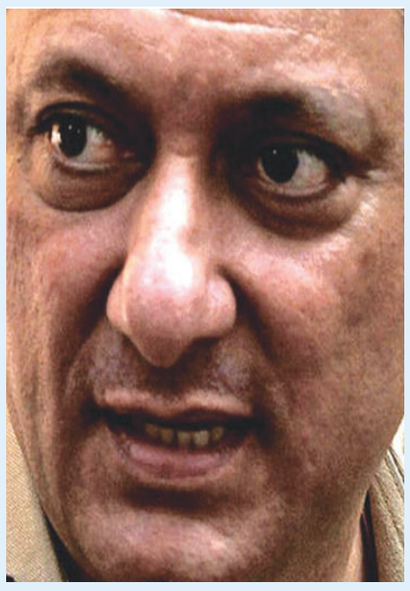

दिलीप चेरियन

नियुक्ति से नाराज़गी

महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर आर पाटिल ने राकेश मारिया की राज्य के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति किए जाने का बचाव किया है. मारिया ने सत्यपाल सिंह की जगह ली है, जिन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए त्यागपत्र दे दिया था. उनके इस निर्णय से बहुत लोगों को हैरानी भी हुई थी, क्योंकि अभी उनकी सेवानिवृत्ति में एक साल का समय बाकी था. 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी मारिया राज्य एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वायड) के प्रमुख रह चुके हैं, लेकिन उनकी इस पद पर नियुक्ति से बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं. कम से कम दो पुलिस अधिकारियों ने तो उनकी नियुक्ति पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं. विशेष आश्चर्य की बात नहीं है कि यहां पर वरिष्ठ होने का मामला ही अहम मुद्दा है. जानकारी के अनुसार, दो पुलिस अधिकारियों, विजय कांबले और अहमद जावेद ने खुद को उपेक्षित किए जाने के कारण विरोध में पद से त्यागपत्र देने की बात कही है. दोनों ही अधिकारी मारिया से वरिष्ठ हैं और उन्हें उम्मीद थी कि सत्यपाल सिंह के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उन्हें कमिश्नर बनाया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, कांबले पद की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन आख़िरी क्षणों में उन्हें मारिया के हाथों मात मिल गई. उक्त अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय राजनीतिक है. मारिया को कमिश्नर बनवाने के पीछे एनसीपी लगी हुई थी. लेकिन, असल बात यह है कि क्या उक्त दोनों अधिकारी अपना पद छोड़ देंगे? अगले अपडेट के लिए इंतजार कीजिए.■

मनचाही नियुक्ति की लड़ाई

2007 बैच एवं हिमाचल प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी ए शाइनामोल 2009 से ही अपने मनचाहे कैडर में पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार से क़ानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. उनकी प्राथमिकता केरल कैडर थी, लेकिन एक ओबीसी उम्मीदवार के रूप में उनकी योग्यता के बावजूद उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर में तैनात कर दिया गया. अब कम्पैशनेट ग्राउंड के आधार पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उनकी तैनाती तीन सालों के लिए केरल में करने को राजी हो गया है. हैरानी वाली बात तो यह है कि विभाग ने यह काम मामले पर चल रही क़ानूनी लड़ाई के दौरान किया है. इस वजह से केंद्र सरकार के लिए मुश्किल की स्थिति आ गई है, क्योंकि अदालत में सरकार का पक्ष यही है कि शाइनामोल की तैनाती नियमों के आधार पर हुई है. दूसरी तरफ़ अधिकारी को कम्पैशनेट ग्राउंड पर उसके मनचाहे कैडर में पोस्टिंग भी दे दी गई. मामले पर निगाह रख रहे लोग यह देख रहे हैं कि अब अदालत में इस निर्णय की वजह से सरकार का पक्ष कमजोर होगा या मजबूत? ■

विवादित नियुक्ति

सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति को लेकर पिछले कुछ दिनों से सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा के साथ चला आ रहा गतिरोध अभी थमा भी नहीं था कि सरकार ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है. सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद के लिए अर्चना रामासुंदरम के नाम को लेकर सरकार ने दौड़ में शामिल कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त एवं काबिल आईपीएस अधिकारी आर के पचनंदा की नियुक्ति का अप्रत्यक्ष और सफल विरोध किया है. सरकार के इस क़दम से एक नया विवाद खड़ा हो गया है. हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार के इस क़दम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी. श्रीमती रामासुंदरम का नाम कैबिनेट की चयन समिति द्वारा तय किया गया था. हालांकि सरकार ने यह फ़ैसला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार की आवश्यक अनुशंसा के बगैर लिया था. आने वाले दिनों में इस विवाद के गहराने की पूरी संभावना है. सरकार को इस विवाद को लेकर भी सफाई देनी होगी. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

नंदा और आरती निदेशक बने

2004 बैच के आईआरएस अधिकारी समर नंदा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में निदेशक (कृषि) नियुक्त किया गया है. वह 1997 बैच एवं महाराष्ट्र कैडर के भारतीय वन सेवा अधिकारी आंगसुमन डे का स्थान लेंगे. इसी प्रकार 2004 बैच की आईआरएस अधिकारी आरती सक्सेना को राजस्व विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है.

नवीन और निधि संयुक्त सचिव बनेंगे

1994 बैच एवं जम्मू-कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी को रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया जा सकता है. वह इस समय जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं. नवीन 1986 बैच एवं पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी अरुण कुमार बल का पद संभालेंगे, जिनका अक्टूबर 2013 में निधन हो गया. इसी प्रकार 1994 बैच एवं मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर बतौर संयुक्त सचिव जल्द ही रक्षा विभाग से जुड़ेंगी. वह 1983 बैच एवं महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी उपामन्यु चटर्जी का स्थान लेंगी, जिन्हें हाल में प्राकृतिक नियामक गैस बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है. चटर्जी 1978 बैच एवं आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी आर पी वटल का कार्यभार संभालेंगे.

नीरज शहरी विकास मंत्रालय जाएंगे

1993 बैच एवं मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस नीरज मंडलोई शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ सकते हैं. वह 1983 बैच एवं राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक सिंघवी का स्थान लेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संविधान के ख़िलाफ़ है हमारी मौजूदा आर्थिक नीति

मौजूदा भारतीय आर्थिक नीति को चंद पंक्तियों में समेटना हो, तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि न कोई अर्थ है, न कोई नीति है, दरअसल यह सरकार की जनता के ख़िलाफ़ एक गंदी राजनीति है. अगर कोई इन पंक्तियों से असहमत है, तो उसे भारतीय संविधान के भाग चार में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए. आइए, जानते हैं कि कैसे पिछले 24 सालों के दौरान विभिन्न सरकारों की आर्थिक नीतियों ने भारतीय संविधान के विरुद्ध काम किया है और अभी भी कोई राजनीतिक दल इससे उलट कोई आर्थिक नीति पर बात तक नहीं कर रहा है.

पिछले 24 सालों से चली आ रही आर्थिक नीति भारत जैसे देश के लिए प्रभावी साबित नहीं हुई है. न ही यह आर्थिक नीति हमारे संविधान के लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को पूरा करा सकती है. ऐसे में आज ज़रूरत है एक ऐसी आर्थिक नीति की, जिसे भले ही आक्सफोर्ड या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े किसी अर्थशास्त्री ने न बनाया हो, लेकिन जो कम से कम हमारे संविधान के लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को पूरा कर पाने में सक्षम हो.

शशि शेखर

हम भारत के लोगों से बना भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है. लोगों की बेहतरी के लिए हमारा संविधान कुछ ऐसे सूत्र बताता है, जिनके इस्तेमाल से राज्य एक ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, जहां हर एक आदमी को समान सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार मिलें, समान विकास हो. लेकिन पिछले 24 सालों की आर्थिक नीतियों की ही देन है कि एक ओर गोदामों में अनाज सड़ता रहा और दूसरी तरफ़ कालाहांडी के ग़रीब आम की गुठली खाकर मरते रहे. यह हमारी आर्थिक नीति ही है, जिसकी वजह से भारत की हालत, हंगर इंडेक्स 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी बदतर है. यह नव-विकास के लिए ज़रूरी मंत्र नव-उदारवाद की ही देन है कि अकेले 2012 में भारत के 15 लाख बच्चे (5 साल से कम उम्र के) अकाल मौत के शिकार हो गए. यह मनमोहन सिंह और एम एस अहलूवालिया की आर्थिक नीति ही है, जो यह मानती है कि 30 रुपये कमाने वाला आदमी ग़रीब नहीं है. इस सबसे अलग बेरोज़गारी, महंगाई, नक्सलवाद एवं प्राकृतिक संसाधनों की लूट आदि जैसी अनगिनत समस्याएं भी हैं. और, कहीं न कहीं इस सबकी जड़ में भी हमारी पिछले 24 सालों की आर्थिक नीति ही है.

संविधान के मुताबिक, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा, जिसमें सबको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिले. राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा. लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संक्रेंद्रण न हो. पुरुष और स्त्री, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो. लेकिन, क्या सचमुच ऐसा है? क्या यह मौजूदा आर्थिक नीति की उस ट्रिकल डाउन थ्योरी (धन के ऊपर यानी अमीर की झोली से गिरकर नीचे यानी ग़रीबों तक पहुंचने) की देन नहीं है, जिसकी वजह से देश की कुल संपदा का आधा से भी अधिक हिस्सा देश के चंद कॉरपोरेट हाउसेज के पास है और दूसरी तरफ़ देश की सत्तर फ़ीसद आबादी रोजाना 20 रुपये की कमाई पर जिंदा है.

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के मुताबिक, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो. लेकिन मौजूदा आर्थिक नीति के तहत विकास के नाम पर कॉरपोरेट हाउसेज को प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट की छूट मिली हुई है. आदिवासी क्षेत्रों में बेहिसाब जल, जंगल, ज़मीन और खदानें मल्टीनेशनल कंपनियों को आवंटित कर दी जाती हैं. स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन से बेदख़ल कर दिया जाता है. और यह सब होता है विकास के नाम पर. लेकिन किसका विकास और कितना विकास? बड़े बांधों के नाम पर मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक लाखों लोग विस्थापित होने का दंश झेल रहे हैं. लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं. सवाल है कि आख़िर उस आर्थिक नीति का क्या फ़ायदा, जिसकी वजह से इस देश की जनता को अकेले कोल ब्लाक आवंटन से ही लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाए.

हमारा संविधान कहता है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मज़दूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा. लेकिन क्या संविधान की इस बात का पिछले 24 सालों में किसी भी सरकार ने पालन किया? देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगातार गिरती गई. हां, नए-नए उद्योग ज़रूर स्थापित हुए. लेकिन क्या इन उद्योगों में मज़दूरों को उनका वाजिब हक़ तक मिला? मज़दूरों के शिष्ट जीवन स्तर की तो बात ही छोड़िए, क्यों आज भी मज़दूर अपनी न्यूनतम मज़दूरी के लिए भी संघर्ष करते हैं? क्यों मज़दूरों को रोज़गार की सुरक्षा तक नहीं है? आज निजी संस्थानों में काम करने वाले लोगों से उनके काम की दशा और अवकाश के बारे में पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा.

संविधान के मुताबिक, राज्य दुर्बल वर्गों, विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का ख्याल रखेगा. सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा. लेकिन आरक्षण के अलावा क्या किसी भी सरकार ने इस वर्ग के विकास के लिए किसी विशेष आर्थिक नीति की घोषणा की? सरकार ने मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए, जो ग्रामीण रोज़गार सृजन के साथ-साथ भ्रष्टाचार सृजन का काम भी करने लगा. किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर सरकारें यह दिखाने की कोशिश करती रहीं कि उन्हें किसानों की फिक्र है. लेकिन क्या इसका फ़ायदा कभी उन करोड़ों किसानों को मिला, जिनके पास उतनी ही जमीन है, जिस पर वे मुश्किल से दो वक्त की रोटी के लिए अनाज उगा पाते हैं?

बहरहाल, सवाल है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस लोक कल्याणकारी राज्य की बात की, क्या उसका पालन पिछले 24 सालों में किसी भी सरकार या राजनीतिक दल ने किया? 1991 में जब नरसिंहराव सरकार के वित्तमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी नई आर्थिक नीति की शुरुआत की, तो कहा गया कि अगले बीस सालों में यह देश खुशहाल बन जाएगा. पिछले दस सालों से वही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, उदारीकरण के बाद नव-उदारीकरण का दौर आ गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? 1996 से 1998 के बीच पी चिदंबरम वित्तमंत्री रहे, उन्होंने भी मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया. भाजपा की सरकार आई, तो उसने बाक़ायदा विनिवेश मंत्रालय बनाकर सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने का काम किया यानी भाजपा ने भी वही रास्ता चुना, जो मनमोहन सिंह ने बनाया था.

जाहिर है, पिछले 24 सालों से चली आ रही आर्थिक नीति भारत जैसे देश के लिए प्रभावी साबित नहीं हुई है. न ही यह आर्थिक नीति हमारे संविधान के लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को पूरा करा सकती है. ऐसे में आज ज़रूरत है एक ऐसी आर्थिक नीति की, जिसे भले ही आक्सफोर्ड या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े किसी अर्थशास्त्री ने न बनाया हो, लेकिन जो कम से कम हमारे संविधान के लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को पूरा कर पाने में सक्षम हो. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

संविधान, सरकार और लोक कल्याणकारी राज्य

- राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे.
- राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा.
- पुरुष और स्त्री, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो.
- समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो.
- आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संक्रेंद्रण न हो.
- पुरुष एवं स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोज़गारों में न जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों.
- राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए क़दम उठाएगा.
- राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मज़दूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा. और, विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा.
- राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से क़दम उठाएगा.
- राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा.

चौथी दुनिया
प्रपत्र-4
(नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशन का स्थान	नई दिल्ली
2. प्रकाशन अवधि	साप्ताहिक प्रति रविवार
3. मुद्रक का नाम	रामपाल सिंह भदौरिया
राष्ट्रीयता	
(क) क्या भारत का नागरिक है	हां
(ख) यदि विदेशी है तो मूल देश	XXX
पता	29 डीडीए फ्लैट, चित्रा विहार विकास मार्ग, दिल्ली-110092
4. प्रकाशक का नाम	रामपाल सिंह भदौरिया
(क) क्या भारत का नागरिक है	हां
(ख) यदि विदेशी है तो मूल देश	XXX
पता	29 डीडीए फ्लैट, चित्रा विहार विकास मार्ग, दिल्ली-110092
5. संपादक का नाम	**संतोष भारतीय**
राष्ट्रीयता	
(क) क्या भारत का नागरिक है	हां
(ख) यदि विदेशी है तो मूल देश	XXX
पता	अंकुश पब्लिकेशंस प्रा.लि. के-2, गेनन, दूसरी मंजिल, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हैं एवं कुल पूंजी के एक प्रतिशत से ज़्यादा के साझीदार या शेयरधारक हैं.	अंकुश पब्लिकेशंस प्रा.लि. 98, मित्तल चैम्बर्स, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021 1. गेनन डंकरली फाइनेंस लिमिटेड, न्यू एक्सेलर बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, ए. के. नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 2. एम आर होल्डिंग लिमिटेड, न्यू एक्सेलर बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, ए. के. नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 3. डेली मल्टी मीडिया लिमिटेड, 98 मित्तल चैम्बर्स, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021

मैं रामपाल सिंह भदौरिया एतदद्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं.

हस्ताक्षर
रामपाल सिंह भदौरिया
प्रकाशक

दिनांक : 02 मार्च, 2014

> ध्यान देने योग्य बात यह है कि अन्ना हजारे का ममता बनर्जी को समर्थन देना एक बड़ी राजनीतिक घटना थी लेकिन किसी भी बड़े दल की तरफ से इसे लेकर कोई विशेष प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है. यहां तक कहा जा सकता है कि इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में एक तरह का सन्नाटा भी पसरा हुआ है.

उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा यानी सपा

अजय कुमार

दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है. हालांकि, यह बात कई बार ग़लत भी साबित हुई है. वैसे उत्तर प्रदेश के नेताओं का दिल यह बात मानने को तैयार नहीं हैं. अगर ग़ौर करें, तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की संख्या सबसे अधिक है. प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बसपा प्रमुख मायावती और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के मन में प्रधानमंत्री बनने की प्रबल इच्छा है.

इस बीच भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के यूपी से चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं. राजनीति के तमाम धुरंधर इन दिनों यूपी के सहारे देश की राजनीति बदलने का दंभ भर रहे हैं. कोई कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है, तो किसी की ज़िंदगी का मक़सद ज़हरीली खेती करने वालों से देश को बचाना है. इससे इतर ऐसे नेता और गठबंधन भी पनप रहे हैं, जो कांग्रेस और भाजपा को देश के लिए बड़ा ख़तरा मानते हैं. ग़ैर कांग्रेस और ग़ैर भाजपा की राग अलापने वाले इस गठबंधन की अगुवाई तमाम राज्यों के क्षत्रपों ने संभाल रखी है. इस गठबंधन को नाम दिया गया है तीसरा मोर्चा. वैसे तो तीसरे मोर्चे में कुल 11 दल हैं, लेकिन वामपंथी पार्टियां, जनता दल यूनाइटेड, बीजू जनता दल, अन्नाद्रमुक, तेलगुदेशम पार्टी और समाजवादी पार्टी ही फ़िलहाल इस क़वायद में शामिल हैं. तीसरा मोर्चा बात तो ग़ैर भाजपा और ग़ैर कांग्रेस की कर रहा है, लेकिन इस हक़ीक़त को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि 1977 (जनता पार्टी सरकार) के अलावा कभी भी ग़ैर कांग्रेस और ग़ैर भाजपा दल के नेता बहुमत लायक आंकड़ा भी नहीं जुटा सके हैं.मोर्चे में तमाम ऐसे दल और नेता शामिल हैं, जो समय-समय पर कांग्रेस और भाजपा के साथ गलबहियां करते रहे हैं.

मौजूदा हालात पर ग़ौर किया जाए, तो ग्यारह राजनीतिक दलों के सुरमाओं में से नौ पार्टियों के सूरमा किसी भी तरह से सात रेस कोर्स (प्रधानमंत्री निवास) में दाख़िल होना चाहते हैं. इसमें सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव का है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सफलता ने मुलायम सिंह यादव के सपनों में पंख लगा दिये हैं. यही वजह है कि वह तीसरे मोर्चे के सहारे प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करना चाहते है. स्वयं को प्रधानमंत्री पद का सबसे मज़बूत दावेदार समझने वाले मुलायम की पहचान सपा प्रमुख के रूप में तो है ही. इसके अलावा, पिछले दस वर्षों से वह संप्रग एक और दो सरकार के संकटमोचक भी रहे हैं. ग़ौरतलब है कि तीसरे मोर्चे के साथ खड़े होने के बाद भी उनका यूपीए सरकार से मोह भंग नहीं हुआ है. इस बात का अहसास पिछले दिनों मीडिया से रूबरू होने के दौरान उनकी बातों से हुआ. प्रेस कांफ्रेस में जब उनसे पूछा गया कि आप यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेंगे, तो उनका जवाब था, दो महीने में सब पता चला जाएगा. वहीं विपक्षी पार्टी नेताजी की मजबूरी बताते हुए तंज कसते हैं कि मुलायम समर्थन वापस लेने की ग़लती नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सीबीआई से नेता जी का पिंड छूटा है. कहीं अंतिम बेला में यूपीए सरकार उनके लिए कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दे.

सियासी जानकारों का कहना है कि मुलायम दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं. इसलिए वह लेफ्ट-राइट की राजनीति कर रहे हैं. हालांकि, राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठेगा यह कोई नहीं जानता. मुलायम का यह कहना कि कांग्रेस की सारी ख़ामियों के बावजूद सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ वह रायबरेली से सपा उम्मीदवार नहीं उतारेंगे. हालांकि, यह बात तीसरे मोर्चे की वक़ालत करने वालों के गले नहीं उतर रहा है. मुलायम तर्क देते हैं कि सियासी नैतिकता का यह तकाज़ा है कि देश के सभी बड़े नेता जिनकी मौजूदगी से संसद का मान बढ़ता है, उनके ख़िलाफ़ उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए. उनके मुताबिक़, इस परंपरा की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी. सोनिया के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने हमारे ख़िलाफ़ प्रत्याशी नहीं उतारा, तो हमने भी नहीं कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया. इतना ही नहीं, अमेठी में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ भी सपा किसी दमदार प्रत्याशी को मैदान में उतारने के मूड में नहीं है, जबकि अमेठी लोकसभा क्षेत्र की कई विधान सभा सीटों पर फ़िलहाल सपा का क़ब्ज़ा है. दिल्ली की गद्दी के लिए सपा की बचैनी किसी से छुपी नहीं है. पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पंजाब में आयोजित प्रोग्रेसिव पंजाब एग्रीकल्चर समिट-2014 में हिस्सा लेने पहुंचे थे. अखिलेश वहां अकाली दल के नेताओं से करीबी बनाते दिखे. यह जानते हुए कि अकाली दल एनडीए का हिस्सा है. इतना ही नहीं, जिस मंच पर अखिलेश मौजूद थे उसी मंच से यह मांग उठी की अगर अकाली दल तीसरे मोर्चे के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसके नेता प्रधामनंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं. हालांकि, इस मंच पर भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद थे.

> मौजूदा हालात पर ग़ौर किया जाए, तो ग्यारह राजनीतिक दलों के सुरमाओं में से नौ पार्टियों के सूरमा किसी भी तरह से सात रेस कोर्स (प्रधानमंत्री निवास) में दाख़िल होना चाहते हैं. इसमें सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव का है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सफलता ने मुलायम सिंह यादव के सपनों में पंख लगा दिये हैं. यही वजह है कि वह तीसरे मोर्चे के सहारे प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करना चाहते है. स्वयं को प्रधानमंत्री पद का सबसे मज़बूत दावेदार समझने वाले मुलायम की पहचान सपा प्रमुख के रूप में तो है ही.

बात अगर उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की करें, तो यहां तीसरे मोर्चे का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ समाजवादी पार्टी है. जिसकी छवि लगातार गिरती जा रही है. प्रदेश में क़ानून व्यवस्था का हाल किसी से छुपा नहीं है. जातिगत आधार पर ज़रूर सपा को अल्पसंख्यकों और यादवों के वोट मिल सकते हैं. हालांकि, भाजपा का कहना है कि जो पार्टी एक प्रदेश नहीं संभाल पा रही है, वह देश को क्या संभालेंगे. वैसे भी आम धारणा तो यही है कि मुलायम की राजनैतिक विश्वसनीयता अब पहले जैसी नहीं रह गई है. वह आज भले ही तीसरे मोर्चे की वक़ालत कर रहे हों, लेकिन ग़ैर- कांग्रेस और ग़ैर- भाजपा का उनका नारा खोखला है.

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव भले ही तीसरे मोर्चे की बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार करना चाहते हों, लेकिन तीसरे मोर्चे के साथ खड़े होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उनकी परेशानियां कम होती नहीं दिख रही है. यहां उसे भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से भी चुनौती मिलेगी. उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे को लेकर सपा की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने अभी तक प्रदेश में छोटी पार्टियों से सामंजस्य बनाने का प्रयास नहीं किया. अगर समाजवादी पार्टी अपना दल, पीस पार्टी, जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया, उलेमा काउंसिल जैसे दलों को साथ लेकर चले, तो तीसरे मोर्चे का आधार मज़बूत हो सकता है. इस बीच आम आदमी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम के ख़िलाफ़ पूर्व नौकरशाह बाबा हरदेव को मैदान में उतार कर हड़कंप मचा दिया है. ग़ौरतलब है कि सरकारी सेवाकाल के दौरान बाबा हरदेव की छवि एक ईमानदार और सख्त अधिकारियों में हुआ करती थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

समर्थन पर राजनीतिक दलों की चुप्पी

अरुण तिवारी

लोकपाल बिल के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समर्थन किए जाने के मामले पर अन्य दलों ने एकतरह की चुप्पी साध रखी है. अन्ना हजारे ने ममता बनर्जी का यह कहते हुए समर्थन किया कि मैं दीदी को एक व्यक्ति या नेता के रूप में समर्थन नहीं दे रहा हूं, बल्कि समाज और देश के प्रति उनके जो विचार हैं, उसको मेरा समर्थन है. मैंने अगर पहली बार देश और समाज के बारे में सोचने वाला व्यक्ति देखा तो वह दीदी हैं. इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करता हूं. वहीं ममता ने भी अन्ना की शान में कीसदे गढ़े.

अन्ना हजारे एक समाजसेवी हैं और देश के प्रति उनकी आस्था को लेकर शायद ही किसी को संदेह हो. ममता बनर्जी के साथ दिल्ली में हुई प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अन्ना हजारे ने बताया कि उन्होंने देश के बेहतर भविष्य के लिए एक सत्रह सूत्रीय कार्यक्रम सभी पार्टियों के पास भेजा था लेकिन उसका जवाब सिर्फ ममता की तृणमूल कांग्रेस ने ही दिया. ममता ने अन्ना को इस बात का विश्वास दिया कि वे उनके इस सत्रह सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करेंगी. अन्ना ने इस अवसर अपनी बात दोहराई कि वे अभी भी किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं बल्कि वे उन सत्रह सूत्रीय कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं जिन्हें लागू करने की बात ममता बनर्जी ने कही है.

ध्यान देने योग्य बात यह है कि अन्ना हजारे का ममता बनर्जी को समर्थन देना एक बड़ी राजनीतिक घटना थी लेकिन किसी भी बड़े दल की तरफ से इसे लेकर कोई विशेष प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है. यहां तक कहा जा सकता है कि इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में एक तरह का सन्नाटा भी पसरा हुआ है. इसे लेकर हमने कुछ राजनीतिक हस्तियों से प्रतिक्रियाएं लीं. मार्क्सवादी पार्टी के वरिष्ठ गुरुदास दास गुप्ता ने इस मामले में किसी भी सवाल का जवाब देने से इंकार कर दिया. बार-बार पूछे जाने पर भी कोई उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया. जब हमने इसपर कांग्रेस के नेता मोहन प्रकाश से संपर्क साधा तो उन्होंने भी कोई सीधा जवाब न देते हुए यह कहा कि इस संबंध में कोई भी टिप्पणी पार्टी के प्रवक्ता ही करेंगे. भाजपा की तरफ से हमें थोड़ी बेहतर प्रतिक्रिया मिली. अन्ना के ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के मामले पर वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए बेहतर है. अगर अन्ना हजारे ऐसा मानते हैं कि ममता बनर्जी उनकी नजर में सबसे बेहतरीन नेता हैं तो यह लोकतांत्रिक तरीका है और लोकतंत्र में सबके अपने विचार हैं. अन्ना हजारे बड़े समाजसेवी हैं और किसी भी राजनीतिक नेता का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र हैं.

इस संबंध में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहे अबनि रॉय का कहना है कि अन्ना हजारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं उनके आंदालनों का केंद्र भी दिल्ली और महाराष्ट्र ही रहे हैं, ऐसे में बंगाल में उनका असर पड़ेगा, इस बात की कम ही संभावना है. यह पूछे जाने पर कि अन्ना हजारे की लोकप्रियता देश भर में है और ऐसी अवस्था में क्या ममता बनर्जी की पार्टी को राज्य में उससे बाहर कोई फायदा हो सकता है, उन्होंने कहा कि थोड़ा-बहुत-असर पड़ सकता है लेकिन अन्ना का यह कहना कि ममता प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, गलत है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों की आवश्यकता होती है, ऐसे में ममता बनर्जी के लिए इस बात की घोषणा करना कि वे देश की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है. इसे लेकर कोलकाता में मुस्लिम एकता परिषद संस्था के अब्दुल अजीज रशीद का कहना है कि अभी चुनावों में लगभग दो महीने का समय बाकी है, और मतदाताओं का रुख अन्ना के समर्थन की वजह से ममता की तरफ और भी खिंच सकता है और इसके विपरीत अवस्था भी हो सकती है. हमें इसके लिए इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जनता अन्ना के समर्थन का कितना समर्थन करेगी.

कुछ भी कहा जाए लेकिन एक बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अन्ना के ममता बनर्जी को इस तरह से समर्थन देने और उन्हें पीएम पद का सबसे योग्य प्रत्याशी बताने की वजह से दूसरे दलों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्ना ने पहले भी यह घोषणा की है कि वे लोकसभा चुनाव में पाक-साफ छवि वाले प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे. ऐसे में इस बात के आसार काफी प्रबल हो जाते हैं कि राज्य के बाहर भी तृणमूल कांग्रेस की सीटों में इजाफा हो सकता है. उसे अन्ना के समर्थन का काफी लाभ मिल सकता है. दूसरे दलों की बात की जाए तो बंगाल में तृणमूल की मुख्य प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी पार्टी की तरफ से अन्ना के इस नए कदम के बाद कोई टिप्पणी नहीं आई. पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की. ऐसे मामले तभी देखे जाते हैं पार्टियों में किसी बात को लेकर हलचल हो. वाम दलों का इस पर कोई प्रतिक्रिया न देना या उससे बचना भी यही दर्शाता है कि वे इसे गंभीर रूप से ले तो रहे हैं लेकिन यह जताने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं.

> ध्यान देने योग्य बात यह है कि अन्ना हजारे का ममता बनर्जी को समर्थन देना राजनीतिक बड़ी राजनीतिक घटना थी लेकिन किसी भी बड़े दल की तरफ से इसे लेकर कोई विशेष प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है. यहां तक कहा जा सकता है कि इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में एक तरह का सन्नाटा भी पसरा हुआ है. इसे लेकर हमने कुछ राजनीतिक हस्तियों से प्रतिक्रियाएं लीं. मार्क्सवादी पार्टी के वरिष्ठ गुरुदास दास गुप्ता ने इस मामले में किसी भी सवाल का जवाब देने से इंकार कर दिया.

अब चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अन्ना के समर्थन से तृणमूल को कितनी सीटों का मुनाफा होगा. वैसे पिछले लोकसभा चुनावों में भी 19 सीटों के साथ तृणमूल ने राज्य फतेह किया था. उस समय कांग्रेस और तृणमूल साथ-साथ थे. इस बार की तस्वीर पहले से बेहतर हो सकती है क्योंकि यूपीए के दो शासनकालों की वजह से कांग्रेस की अवस्था तो काफी खराब चल रही है. ऐसे में कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ना तृणमूल के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है. साथ ही अब उसे अन्ना हजारे का समर्थन भी प्राप्त है जो उसे लाभ ही देगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

उल्लेखनीय है कि किसान नेता तेवतिया ने 31 जनवरी तक भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन करने की मांग केंद्र सरकार से की थी. बावजूद इसके, सरकार ने इस दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया, लिहाज़ा एक फरवरी से तेवतिया ने जंतर–मंतर पर आमरण अनशन शुरू कर दिया. उनके अनुसार, किसान हितों को नज़रअंदाज़ करने वाली सरकार के ख़िलाफ़ यह निर्णायक आंदोलन है.

किसानों की दुश्मन है कांग्रेस

भट्टा–पारसौल किसान आंदोलन के अग्रणी नेता मनवीर तेवतिया ने भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन की मांग को लेकर और किसान हितों की अनदेखी के ख़िलाफ़ पिछले दिनों जंतर–मंतर पर आमरण अनशन किया. उनके इस किसान सत्याग्रह आंदोलन को समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी समर्थन दिया. क्या मनवीर तेवतिया का यह आंदोलन देश की किसान राजनीति को संजीवनी प्रदान करेगा, इसी मसले पर प्रस्तुत है चौथी दुनिया की यह रिपोर्ट...

अभिषेक रंजन सिंह

यूं तो नई दिल्ली स्थित जंतर–मंतर देश के कई आंदोलनों का गवाह रहा है. ऐसा कोई आंदोलनकारी नहीं रहा होगा, जिसने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यहां आकर अपनी आवाज़ बुलंद न की हो. किसान नेता मनवीर तेवतिया ने भी किसानों के हित से जुड़ी कई मांगों की ख़ातिर बाईस दिनों तक आमरण अनशन किया. ग़ौरतलब है कि मनवीर तेवतिया की अगुवाई में जंतर–मंतर पर बीती एक फरवरी, 2014 से किसान सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था. इस सत्याग्रह में मनवीर तेवतिया के अलावा उत्तर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष एवं मॉट के विधायक श्याम सुंदर शर्मा, उत्तर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव सिरोही, प्रदेश महामंत्री जयप्रकाश सिंह मलिक, उत्तर प्रदेश युवक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ललित भारद्वाज, राधा तेवतिया, रवींद्र शर्मा, काले सिंह, विक्रम सिंह अत्री एवं हरीश कुमार भी अनशन पर बैठे.

चौथी दुनिया से ख़ास बातचीत में मनवीर तेवतिया ने कहा कि किसान सत्याग्रह आंदोलन को समाजसेवी अन्ना हजारे का समर्थन मिलने से किसानों में काफ़ी हर्ष है. उनके मुताबिक़, अन्ना का समर्थन मिलने के बाद जंतर–मंतर पर किसानों की पंचायत हुई, जिसमें किसान आंदोलन को देश भर में मज़बूत करने का निर्णय लिया गया. केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तेवतिया ने कहा कि कांग्रेस किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है, जबकि राहुल गांधी जैसे नेता स्वयं को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी क़रार देते हैं. देश की मौजूदा किसान राजनीति कितनी प्रखर है, यह पूछे जाने पर उन्होंने अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए कहा कि ज़्यादातर किसान नेताओं ने किसानों के हितों की अनदेखी की है. कल तक जो किसान नेता साइकिल से चलते थे, आज वही लोग महंगी गाड़ियों पर घूम रहे हैं. हमारे बीच अन्ना हजारे जैसे समाजसेवी भी हैं, जो आज भी साधारण जीवन व्यतीत करते हैं. इसलिए किसानों को नकली किसान नेताओं से सावधान रहना चाहिए.

मुख्य मांगें

- देश में विकास योजनाओं के लिए किसानों के संपूर्ण भूमि क्षेत्र का आधा भाग ही अधिग्रहीत किया जाए.
- नई नीति को वर्ष 2000 से लागू किया जाए और जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण 1960 से 2000 तक किया गया है, उन्हें 25 प्रतिशत भूमि विकसित करके नि:शुल्क वापस की जाए.
- संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के दौरान दायर मुक़दमे वापस लिए जाएं.
- किसानों को उनकी भूमि का मुआवज़ा विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा विक्रय के लिए निर्धारित दरों के औसत का 60 फ़ीसद दिया जाए.
- बिहार के ढाढर और दुर्गावती जलाशय परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जाए.
- किसानों के प्रत्येक प्रकार के वाहन टोलमुक्त किए जाएं.
- गांवों में शराब की दुकानें बंद की जाएं.
- खेतों में हाईटेंशन बिजली लाइनों पर किसानों को बाज़ार भाव का 30 फ़ीसद मुआवज़ा मिले.
- दिल्ली के यमुना खादर क्षेत्र में बायो डायवर्सिटी पार्क बनाने के नाम पर किसानों से ली गई ज़मीन वापस की जाए.
- किसानों को यमुना खादर क्षेत्र में पक्के मकान बनाने की अनुमति दी जाए.
- मांस निर्यात पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए.

तेवतिया के मुताबिक़, चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के बाद किसानों की सोच बदली है. चौधरी चरण सिंह का कहना था कि किसानों को एक नज़र अपने खेतों पर और दूसरी नज़र राजनीति पर रखनी चाहिए. वहीं किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का कहना था कि किसानों को राजनीति से दूर रहना चाहिए. बकौल मनवीर तेवतिया, देश में किसानों की बात तभी सुनी जाएगी, जब मौजूदा राजनीति में किसानों का दख़ल बढ़ेगा. हालांकि, यह तभी संभव है, जब किसान प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आएंगे, क्योंकि किसानों के मुद्दों को मौजूदा राजनीति में कोई भी पार्टी अपने घोषणापत्र में शामिल नहीं करती है. अरविंद केजरीवाल को राजनीति का आसाराम बताने वाले किसान नेता मनवीर तेवतिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश में अराजकता फैलाने की राजनीति करती है. उनके अनुसार, अरविंद केजरीवाल सभी नेताओं को भ्रष्ट और बेईमान क़रार देते हैं, जबकि वह कितने सच्चे हैं, लोग यह जानने लगे हैं. अगर केजरीवाल में साहस है, तो किसानों के सवाल पर वह देश के बुद्धिजीवियों से वार्ता करें. केजरीवाल जो कहे वही क़ानून है, यह उनकी अधिनायकवादी मानसिकता का परिचायक है. देश भर में किसानों की दुर्दशा का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के बीच आपसी एकता न होने का फ़ायदा राजनीतिक दलों ने उठाया है. दरअसल, किसानों को बांटने का काम किसान नेताओं ने ही किया है. आज गन्ना, आलू और धान उत्पादक किसानों की अलग–अलग यूनियनें हैं. आख़िर ऐसा क्यों है? किसान तो किसान हैं, चाहे वह गन्ना उगाए या आलू.

मांस निर्यात पर अविलंब रोक लगाने की मांग करते हुए तेवतिया ने कहा कि कृषि और पशुपालन एक–दूसरे के पूरक हैं. हाल के वर्षों में गाय और भैंस की क़ीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है. इसकी वजह यह है कि दुधारू पशुओं को बूचड़ख़ानों में काटा जा रहा है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का काफ़ी महत्व है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह मांस उद्योग को बढ़ावा देने के बजाय पशुपालन को प्रोत्साहन दे. ग़ौरतलब है कि भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन की मांग और इसे लेकर सरकार के रवैये नाराज़ किसान नेता मनवीर तेवतिया ने एक फरवरी से जंतर–मंतर पर किसान सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी. देश के कई राज्यों से आए किसानों ने भी इस किसान सत्याग्रह में उनका समर्थन किया.

उल्लेखनीय है कि किसान नेता तेवतिया ने 31 जनवरी तक भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन करने की मांग केंद्र सरकार से की थी. बावजूद इसके, सरकार ने इस दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया, लिहाज़ा एक फरवरी से तेवतिया ने जंतर–मंतर पर आमरण अनशन शुरू कर दिया. उनके अनुसार, किसान हितों को नज़रअंदाज़ करने वाली सरकार के ख़िलाफ़ यह निर्णायक आंदोलन है. ■

arsingh@chauthiduniya.com

जरुर लिखें अपना पैन

आप अपने बड़े लेन–देन को बिल्कुल नहीं छिपा सकते।

40,72,829 व्यक्तियों ने कुल 10 लाख रु. या उससे अधिक की नकद राशि अपने बचत बैंक खाते में जमा की है।

समझदार बनें
अपने बड़े लेन–देन को बताएं।

बताएं एवं फाइल करें:
- स्वेच्छा से अपनी सही आय घोषित करें और उसके अनुसार कर का भुगतान करें।
- आयकर विभाग द्वारा कठोर दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अपने आय की सही रिटर्न फाइल करें।

आयकर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रतीक्षा न करें। तुरंत रिटर्न फाइल करें।
सही आय की घोषणा न करने पर छुपाए गए कर का 300% तक जुर्माना वसूला जा सकता है और अभियोग भी चलाया जा सकता है।

हमें अन्य उच्च मूल्य पाने वाले लेन–देन के बारे में भी जानकारी है, जिनमें शामिल हैं:
- 15,55,220 व्यक्ति, जिन्होंने 30 लाख रु. या उससे अधिक लागत वाली अचल सम्पति का क्रय या विक्रय किया है।
- 20,61,443 व्यक्ति, जिन्होंने एक वर्ष में 2 लाख रु. या उससे अधिक के अपने क्रेडिक कार्ड बिलों का भुगतान किया है।
- 40,40,396 व्यक्ति, जिन्होंने 2 लाख रु. या उससे अधिक के म्यूचुअल फंड यूनिट्स, 5 लाख रु. या उससे अधिक के बॉन्ड या डिबेंचर, 1 लाख रु. या उससे अधिक के कंपनी द्वारा जारी शेयर या 5 लाख रु. या उससे अधिक के आरबीआई द्वारा जारी बॉन्ड खरीदे हैं।
- ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सहकारी बैंकों सहित, बैंकों से 50,000 रु. या उससे अधिक की ब्याज आय के रुप में प्राप्त की है।
- ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने 5 लाख रु. या उससे अधिक के सोना–चांदी या आभूषण खरीदे हैं।

आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई:
- नॉन–फाइलर्स को 12 लाख से अधिक पत्र* जारी किए गए।
- शेष मामलों में विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

*ऊपर उल्लेखित पत्र की प्रतिक्रिया में काफी अधिक संख्या में नॉन फाइलर्स ने अपने आय की रिटर्न फाइल की है।

आयकर विभाग
www.incometaxindia.gov.in

DAVP 15401/13/0092/1314

लालू प्रसाद अभी अपने राजनीतिक करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. पार्टी को एकजुट रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना जैसा कठिन टॉस्क लालू प्रसाद के सामने आकर खड़ा हो गया है. लालू प्रसाद को अब तक राजनीति का बड़ा और चतुर खिलाड़ी माना जाता रहा है. यह बात साबित करने की कठिन घड़ी लालू प्रसाद के सामने आ चुकी है. देखना है, लालू इस परीक्षा में पास होते हैं या फिर फेल.

दिल्ली की डगर कुछ इधर कुछ उधर

सरोज सिंह

सवाल चूंकि दिल्ली की सत्ता का है, इसलिए बिहार में इस समय पाला बदल कर टिकट पाने की होड़ मची हुई है. जिसका जहां जुगाड़ फिट हो रहा है, वह फिट करने में तनिक भी समय बर्बाद नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं, कब कोई दूसरा उससे पहले मैदान मार ले. बड़े नेताओं की आमद इन दिनों भाजपा में ज़्यादा है. इसके बाद जदयू का नंबर आता है. राजद एवं लोजपा के ठिकाने भी जल्द ही गुलजार होने के आसार हैं. यहां यह बताते हुए आगे बढ़ें कि इस सियासी उलट-पुलट के पार्ट-2 की पटकथा भी सत्ता के गलियारे में साथ-साथ ही लिखी जा रही है. जैसे ही बड़ी पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगी, उसी समय इस सियासी भागमभाग का दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा, जो पार्ट वन से ज़्यादा दिलचस्प और चुनावी राजनीति को प्रभावित करने वाला होगा.

बिहार की राजनीति में इसके अलावा, पार्टी में रहकर ही दबाव बनाकर मनचाहा टिकट पाने की कवायद में भी कुछ नेता लगे हुए हैं. पहले बात सियासी भागमभाग की करते हैं. पाठकों को हम पहले ही बता चुके हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर नेता अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने की तैयारी कर रहे हैं. यह सिलसिला अब शुरू हो गया और तेजी पकड़ रहा है. बांका की सांसद पुतुल सिंह और सीवान के सांसद ओम प्रकाश यादव तो पहले ही भाजपा में आ चुके हैं. माना जा रहा है कि इन दोनों को अपनी सीट पर ही पार्टी का टिकट दे दिया जाएगा. टिकट पाने के लिए जो बड़े नाम भाजपा में आना चाहते हैं, उनमें खगड़िया से रणबीर यादव, पाटलिपुत्र से नवल यादव, मुंगेर से महाचंद्र सिंह, सासाराम से छेदी पासवान, औरंगाबाद से सुशील सिंह, गोपालगंज से पंचम लाल और महाराजगंज से तारकेश्वर सिंह शामिल हैं. वैसे भाजपा महाराजगंज से एक मजबूत भूमिहार नेता पर भी डोरे डाल रही है. देवेशचंद्र ठाकुर का भी जदयू से मोहभंग हो चुका है और बताया जा रहा है कि वह भी भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं.

शरद यादव के ख़िलाफ़ भाजपा सहरसा से एक मजबूत ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने की कोशिश में जुटी हुई है. इसी क्रम में निशिकांत ठाकुर को पार्टी में लाया जा चुका है. पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से तालमेल का काम पूरा कर लिया है और तीन सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं. उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, ताकि पूरे बिहार के कुशवाहा वोटरों के बीच एक मजबूत संदेश पहुंच सके. इस तरह भाजपा की पूरी कोशिश यह है कि सूबे की सभी चालीस सीटों पर सोशल इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण पेशकर दमदार प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए, ताकि बेहतर चुनाव परिणाम सामने आएं और दिल्ली की सत्ता पर नरेंद्र मोदी को काबिज कराने में बिहार का अहम योगदान किया जा सके.

इसी तरह जदयू भी क्षतिपूर्ति के तौर पर कई नेताओं को शामिल कराने की जुगत कर रहा है. भाजपा के कुछ नेता उसके निशाने पर हैं, जिनमें दरभंगा के लिए विजय कुमार मिश्रा, मोतिहारी के लिए अवनीश सिंह और वैशाली के लिए राणा गंगेश्वर शामिल हैं. इसी तरह राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी को मधुबनी के लिए, सम्राट चौधरी को खगड़िया के लिए, अख्तारुल इमाम को किशनगंज के लिए पार्टी में लाने की कोशिश हो रही है. झंझारपुर सीट के लिए देवेंद्र यादव जदयू का दामन थाम सकते हैं. इस दिशा में बात काफी आगे भी बढ़ चुकी है. इसी तरह राजद के टिकट के लिए मंगनी लाल मंडल और पूर्णमासी राम जदयू का दामन छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं. आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद लोजपा के टिकट पर शिवहर या फिर सहरसा से चुनाव लड़ सकती हैं. पप्पू यादव राजद एवं कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में टिकट के लिए संपर्क बनाए हुए हैं. लगता है, कांग्रेस में उनकी दाल गल जाएगी.

यह तो थी बात उनकी, जो किसी न किसी दल से टिकट लेकर चुनावी अखाड़े में उतरना चाहते हैं. अब हम बात करेंगे उन नेताओं की, जो अपनी ही पार्टी में दबाव बनाकर अपने लिए मनचाहा टिकट पाने की फिराक में लगे हुए हैं. इनमें पहला नाम गिरिराज सिंह का है. दरअसल, वह बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर पार्टी उन्हें मुंगेर से चुनाव लड़ाना चाहती है. यह बात गिरिराज सिंह को पच नहीं रही है, इसलिए वह प्रदेश इकाई पर दबाव बना रहे हैं. सूत्र बताते हैं कि इसी के तहत उन्होंने यह बयान दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर शाहनवाज हुसैन को पेश किया जाए. गिरिराज सिंह के इस बयान की कड़ी आलोचना हुई. शाहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री मैटेरियल बताए जाने पर भड़के भाजपा नेताओं ने पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया. विधायक विक्रम कुंवर और प्रदेश महामंत्री सुधीर शर्मा ने उन्हें भ्रमित व्यक्ति बताते हुए उन पर हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत गाने का आरोप लगाया. विक्रम कुंवर ने कहा कि भाजपा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में लगी है और गिरिराज अलग ही राग अलाप रहे हैं. इससे पार्टी में भ्रम पैदा हो सकता है.

पार्टी महामंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि गिरिराज को अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए. वह न तो पार्टी के घोषित प्रवक्ता हैं और न संसदीय बोर्ड के सदस्य. उनके ख़िलाफ़ प्रदेश अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए. विक्रम कुंवर ने कहा कि इस तरह के बयानों से पार्टी को नुकसान पहुंचता है. अभी पूरी पार्टी का ध्यान लोकसभा चुनाव पर है और ऐसे महत्वपूर्ण समय में इस तरह की बेतुकी बातें कहने का कोई मतलब नहीं है. यह तो शुक्र मनाइए सुशील मोदी का, जिन्होंने साफ़ कह दिया कि यह मामला जहां है, इसे वहीं रोक दिया जाए और कोई बयानबाजी न की जाए. अगर मोदी आगे नहीं आते, तो यह बात काफी आगे बढ़ जाती.

इसी तरह अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं सम्राट चौधरी भी लगातार अपने आलाकमान पर मधुबनी और खगड़िया सीट के लिए दबाव बनाए हुए हैं. इन सीटों से टिकट न मिलने पर वे किसी भी हद तक जा सकते हैं. इसी तरह की पीड़ा जदयू के रमई राम की है. वह तो खुलेआम हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, जबकि वहां से मौजूदा सांसद रामसुंदर दास ने अभी तक चुनाव न लड़ने का ऐलान नहीं किया है. रमई राम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कान में मुझे हाजीपुर से तैयारी करने के लिए कहा है. मैं तो बस नीतीश कुमार के आदेश का पालन कर रहा हूं. इस तरह देखा जाए, तो हर दल से नेता जा रहे हैं और आ रहे हैं. टिकट पाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. जनता बस इसे देख रही है और मजे ले रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

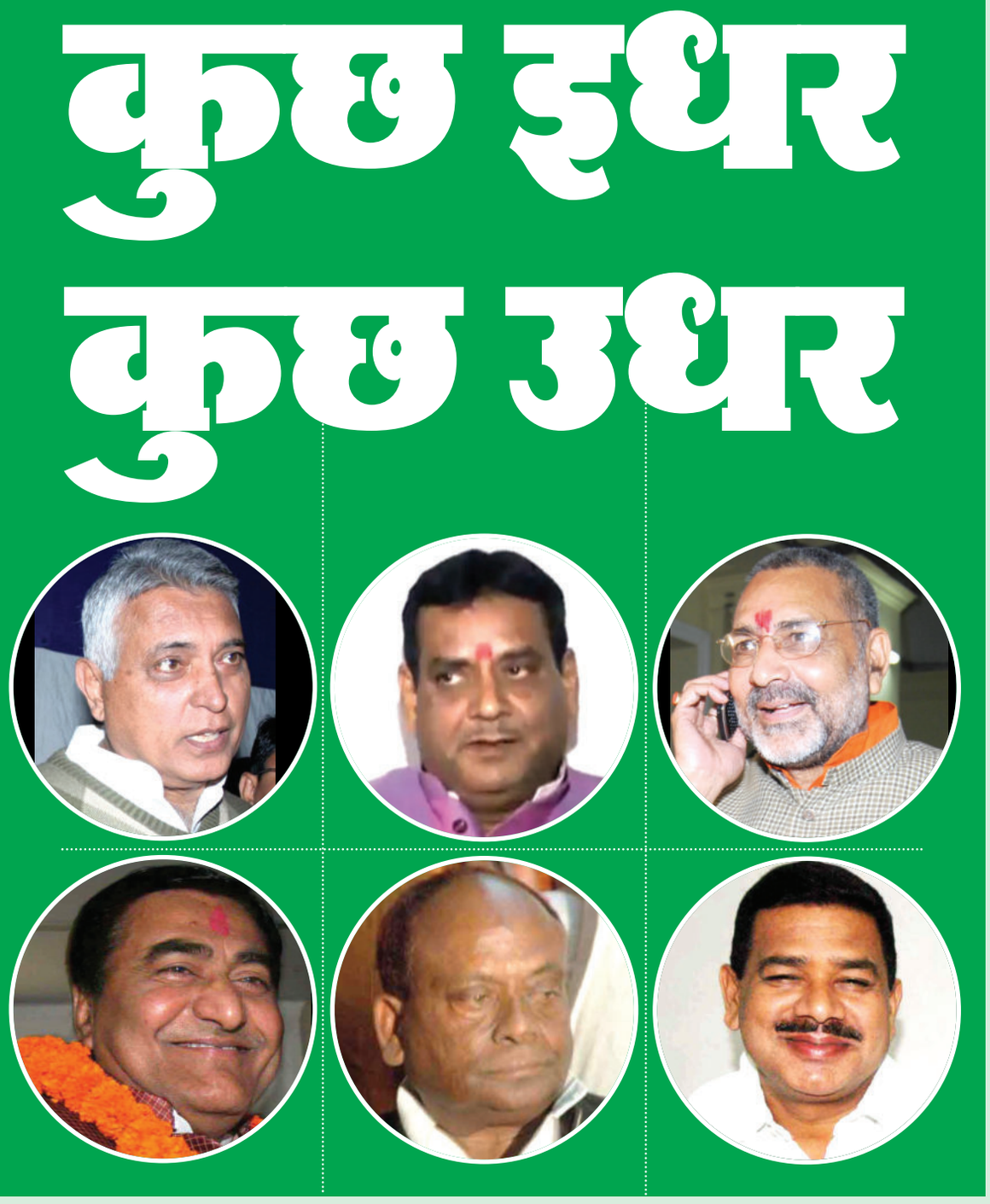

अभी पूरी पार्टी का ध्यान लोकसभा चुनाव पर है और ऐसे महत्वपूर्ण समय में इस तरह की बेतुकी बातें कहने का कोई मतलब नहीं है. यह तो शुक्र मनाइए सुशील मोदी का, जिन्होंने साफ़ कह दिया कि यह मामला जहां है, इसे वहीं रोक दिया जाए और कोई बयानबाजी न की जाए. अगर मोदी आगे नहीं आते, तो यह बात काफी आगे बढ़ जाती.

राजद में सब ठीकठाक नहीं

लालू प्रसाद राजद की सेहत को जितना ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वह उतनी ही बिगड़ती जा रही है. हद तो तब हो गई, जब विधायक दल की बैठक में छह विधायक पहुंचे ही नहीं. बैठक में न जाने वालों में पार्टी के मुख्य सचेतक सम्राट चौधरी, अब्दुल गफूर, केदार सिंह, जावेद एवं राघवेंद्र सिंह शामिल हैं. बाद में बताया गया कि ये सभी अलग-अलग कारणों से बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन बात इतनी हल्की भी नहीं है. सूत्र बताते हैं कि सम्राट चौधरी का कहना था कि वह पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, जब उन्होंने बैठक की सूचना विधायकों को दी ही नहीं, तो फिर बैठक में जाने का सवाल कहां पैदा होता है. बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी इन दिनों खासे नाराज़ हैं, क्योंकि खगड़िया सीट को लेकर लालू प्रसाद कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे

हैं. सम्राट चौधरी का कहना है, मैंने पार्टी अध्यक्ष को साफ़ कह दिया कि खगड़िया और मधुबनी सीट गठबंधन में दूसरे दल को न दी जाए. यहां से राजद चुनाव लड़े, भले ही उम्मीदवार कोई भी हो.

सम्राट चौधरी कहते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन दो सीटों से कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इन दो सीटों से राजद का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे. इसी तरह वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं कि मधुबनी अगर राजद के खाते में नहीं आई, तो उन्हें दुःख होगा. सिद्दीकी की पीड़ा इस बात को लेकर है कि अगर कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा, तो फिर जनता के सामने क्या चेहरा लेकर जाएंगे. मधुबनी में राजद कार्यकर्ताओं ने रात-दिन पसीना बहाकर पार्टी के लिए मजबूत बुनियाद रखी है. पिछले चुनाव में राजद का प्रदर्शन इसकी गवाही देता है. ऐसे में अगर यह सीट गठबंधन के तहत किसी दूसरे दल को दे दी जाएगी, तो फिर कार्यकर्ताओं का दिल टूटना लाजिमी है. हालांकि सिद्दीकी आशा जताते हैं कि पार्टी आलाकमान कोई ऐसा फ़ैसला नहीं लेगा, जिससे गलत संदेश जाए.

सिद्दीकी कहते हैं कि उनके पार्टी बदलने की अटकलें दो साल से लगाई जा रही हैं, लेकिन अटकलबाजों को निराशा ही हाथ लगेगी. यह सही है कि पार्टी में कुछ कमियां हैं, पर हम मिल-जुल कर उनका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे. लेकिन, सूत्र बताते हैं कि बात केवल विधायक दल की नहीं है, पर वैसे वरिष्ठ नेता जिनका टिकट संभावित गठबंधन को लेकर पक्का नहीं है, वे तो आर-पार के मूड में बैठे हैं. लालू प्रसाद की मजबूरी यह है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में वह गठबंधन अपनी शर्तों पर करने की पहले वाली स्थिति में नहीं हैं. उदाहरण के तौर पर लालू प्रसाद लोजपा को तीन या चार सीटें देने के मूड में थे, लेकिन अब बात सात या आठ तक पहुंच गई है. इसी तरह लालू प्रसाद उपेंद्र कुशवाहा को भी इस गठबंधन में शामिल करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई.

वक्त की बात कहिए या फिर कुछ और, लालू प्रसाद अभी अपने राजनीतिक करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. पार्टी को एकजुट रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना जैसा कठिन टॉस्क लालू प्रसाद के सामने आकर खड़ा हो गया है. लालू प्रसाद को अब तक राजनीति का बड़ा और चतुर खिलाड़ी माना जाता रहा है. यह बात साबित करने की कठिन घड़ी लालू प्रसाद के सामने आ चुकी है. देखना है, लालू इस परीक्षा में पास होते हैं या फिर फेल. ■

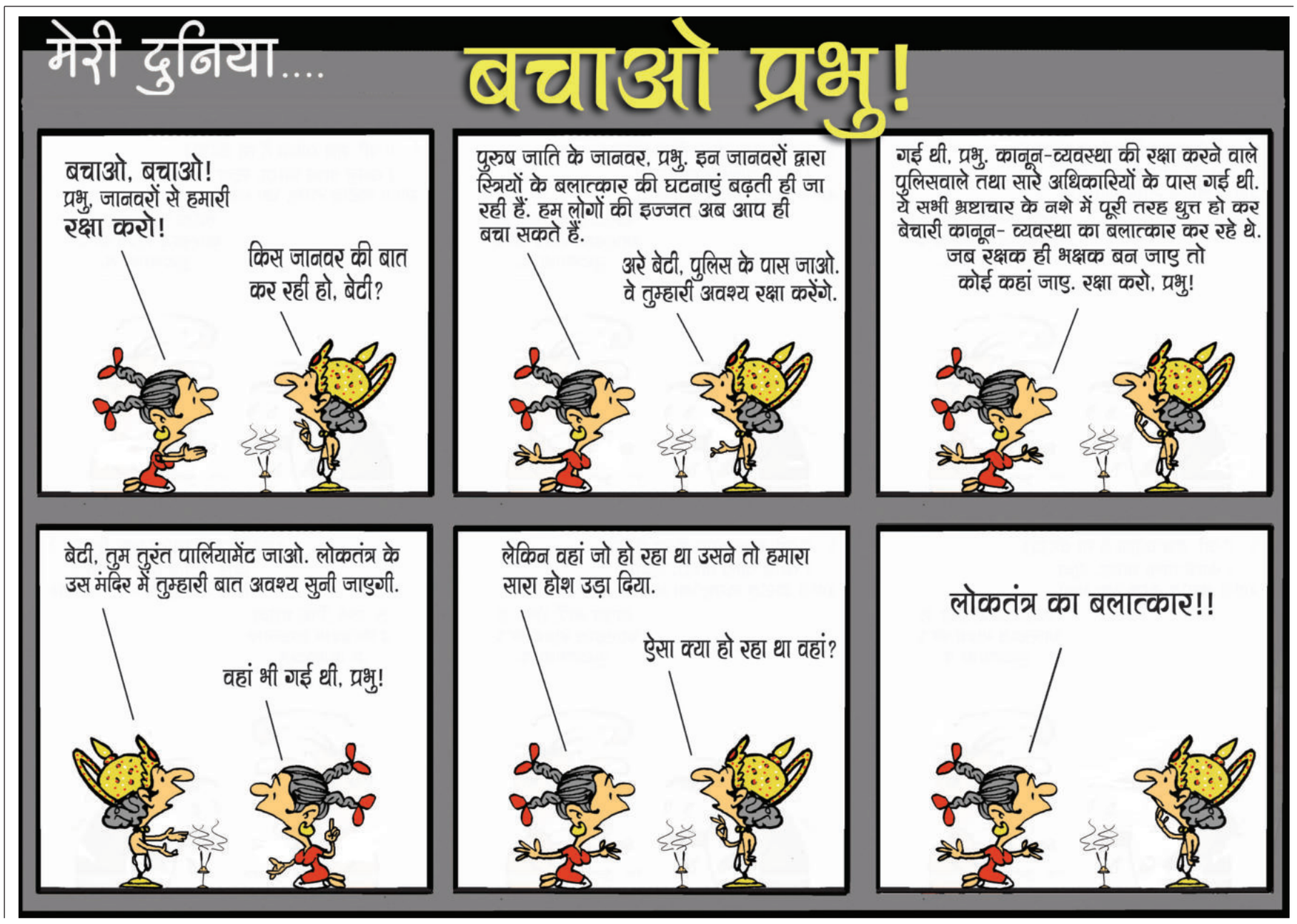

स्वतंत्रता सेनानी और उनके उत्तराधिकारी

उपेक्षा के शिकार

प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़ने वाले अपने वफ़ादार सिपाहियों को अंग्रेज जंगी इनाम दे गए, वह भी तीन पीढ़ियों तक. दूसरी तरफ़, आज़ाद भारत को अपने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों की कोई फिक्र तक नहीं है. इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लिखे गए पत्र भी राज्य सरकारों के लिए बेमानी हैं. क्या है पूरा मामला, पढ़िए चौथी दुनिया की इस ख़ास रिपोर्ट में...

अभिषेक रंजन सिंह

फोटो-*सुनील मल्होत्रा*

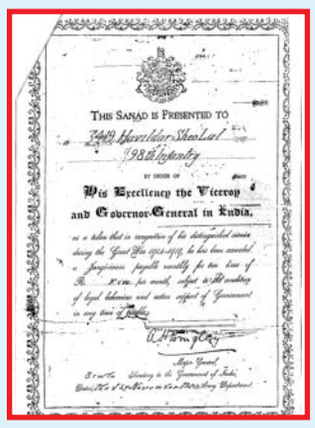

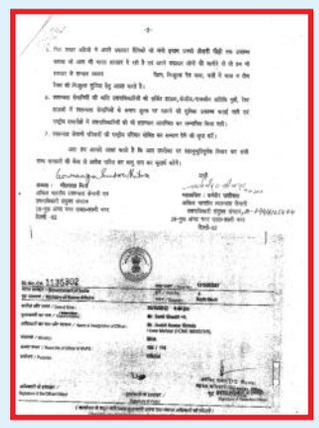

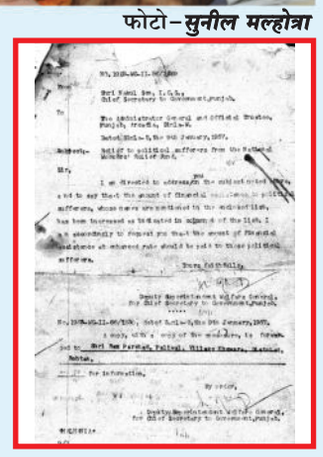

भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों के कल्याण हेतु वर्ष 1988 में एक पत्र सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा था. इस पत्र में स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों के लिए सरकारी नौकरियों एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही गई थी. हालांकि, गृह मंत्रालय के इस ख़त का जवाब किसी राज्य सरकार ने नहीं दिया. आठ वर्षों के बाद गृह मंत्रालय की नींद एक बार फिर खुली और उसने वर्ष 1996 में एक और पत्र सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों के लिए पहले की तरह सरकारी नौकरियों में आरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं समेत कई मांगें की गई थीं. गृह मंत्रालय के इस ख़त का जवाब भी किसी राज्य सरकार ने नहीं दिया.

धर्मवीर पालीवाल हरियाणा स्थित सोनीपत ज़िले के रहने वाले हैं और देश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए सतत संघर्षरत हैं. धर्मवीर पालीवाल ने चौथी दुनिया से ख़ास बातचीत में बताया कि भारत सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों के प्रति गंभीर नहीं है. एक सच्चाई का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में भारत विभाजन के साथ पंजाब की तकदीर भी बंट गई. उनके अनुसार, पंजाब से अलग होकर जब हरियाणा बना, तो एकीकृत पंजाब के दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हरियाणा सरकार ने अपनी सूची में शामिल नहीं किए. नतीजतन, उनके उत्तराधिकारियों को पेंशन एवं अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया गया. ये वही लोग हैं, जिनके बाप-दादा ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जवानी जेलों में कुर्बान कर दी. स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में जब वे अंग्रेजों से मुक़ाबला कर रहे थे, उस वक्त उनके परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं था. ऐसे ज़्यादातर स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बच्चे शिक्षा समेत कई मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए.

धर्मवीर पालीवाल के मुताबिक़, वर्षों से लंबित अपनी मांगों को पूरा न किए जाने से नाराज़ स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों ने अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन की अगुवाई में जंतर-मंतर पर धरना देने का फ़ैसला किया. लिहाज़ा 10 जनवरी, 2014 को संगठन की ओर से जंतर-मंतर पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया. उसी दिन संगठन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय को भी एक ज्ञापन सौंपा गया. उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी, 2014 (गणतंत्र दिवस) के मौक़े पर सभी सरकारी समारोहों का विरोध किया. धर्मवीर पालीवाल के मुताबिक़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड और राजस्थान आदि

स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों की समस्याएं दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने एमीनेंट फ्रीडम फाइटर कमेटी का गठन किया था, लेकिन पिछले दो वर्षों से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है. इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि भारत सरकार स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके उत्तराधिकारियों के प्रति गंभीर नहीं है.

-धर्मवीर पालीवाल,
महासचिव, अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन

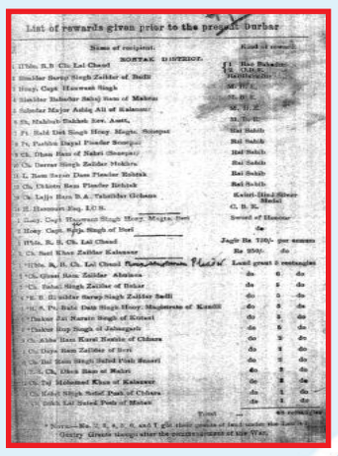

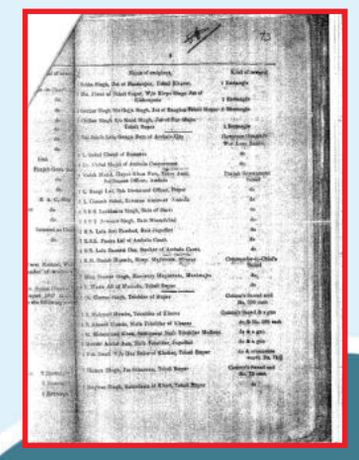

सेनानियों के उत्तराधिकारियों के लिए कुछ नहीं किया. अपनी इसी उपेक्षा से आहत होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों ने 9 अक्टूबर, 2012 को अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन बनाया. 22 जनवरी, 2013 को इसे पंजीकृत किया गया. 9 अक्टूबर, 2012 को ही अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन के संरक्षक सुनील शास्त्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाक़ात की और उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा. उल्लेखनीय है कि 18 दिसंबर, 2007 को एमीनेंट फ्रीडम फाइटर कमेटी ने गृह मंत्रालय को सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद उसके बेरोज़गार उत्तराधिकारियों को भी पेंशन दी जाए. इसके अलावा, सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण की सुविधा, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी का कोटा भी देने की सिफ़ारिश की गई थी, लेकिन भारत सरकार ने इन सिफ़ारिशों पर कोई ग़ौर नहीं किया.

अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन ने एमीनेंट फ्रीडम फाइटर कमेटी की बैठक बुलाने के लिए गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव से कई बार अनुरोध किया. संगठन के हर आग्रह को यह कहकर टाल दिया गया कि मंत्री महोदय के पास समय नहीं है, इसलिए बैठक नहीं हो रही है. ऐसे में सवाल यह है कि अगर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के पास स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों की समस्याएं सुनने के लिए वक्त नहीं है, तो फिर एमीनेंट फ्रीडम फाइटर कमेटी के गठन का औचित्य क्या है? अगर गृह मंत्रालय को इससे कोई सरोकार नहीं रह गया है, तो इसके नाम पर हर साल लाखों रुपये क्यों ख़र्च किए जा रहे हैं?■

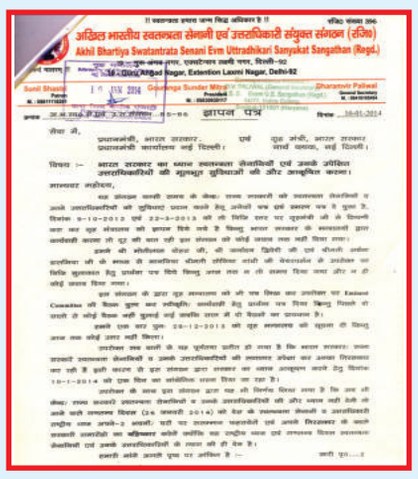

राज्यों के क़रीब 1500 स्वतंत्रता सेनानी परिवारों ने इस बाबत पहले ही आगाह कर दिया था कि दस दिनों के भीतर अगर उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे 26 जनवरी के सरकारी समारोहों का बहिष्कार करेंगे.

ग़ौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों के हितों के नाम पर गठित स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जबकि सत्यानंद याजी इसके महासचिव हैं. सच्चाई यह है कि इस संगठन ने आज तक स्वतंत्रता

arsingh@chauthiduniya.com

ख़त, तारीख़ और टूटती उम्मीदें

10 अक्टूबर, 2012 को अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन के महासचिव धर्मवीर पालीवाल और अध्यक्ष गौरंग सुंदर मित्रा गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मिले और उन्हें पुन: एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को वर्ष 1988 और 1996 में स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों के कल्याण हेतु पत्र भेजे गए, बावजूद इसके राज्य सरकारों ने कोई जवाब नहीं दिया. इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से 18 अक्टूबर, 2012 को एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया, जिसमें 1988 और 1996 के पत्रों का हवाला दिया गया. गृह मंत्रालय ने अपने इस पत्र का जवाब देने का निर्देश भी दिया, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी राज्य सरकारों ने गृह मंत्रालय को कोई जवाब नहीं दिया. राज्य सरकारों की ओर से कोई जवाब न मिलने से आहत अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन के महासचिव धर्मवीर पालीवाल ने 3 दिसंबर, 2012 को गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मुलाक़ात की और उनसे राज्यों की लापरवाही के बारे में बातचीत की. इसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक रिमाइंडर नोट भेजा गया. हालांकि, उसके बाद भी किसी राज्य सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया. 28 जनवरी, 2013 को धर्मवीर पालीवाल ने एक बार फिर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव से वार्ता की. उसी दिन गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी राज्य सरकारों ने इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई.

क्या है एमीनेंट फ्रीडम फाइटर कमेटी?

भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके उत्तराधिकारियों के कल्याण के लिए एमीनेंट फ्रीडम फाइटर कमेटी का गठन किया है. समय-समय पर होने वाली इसकी बैठकों में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों की समस्याओं पर चर्चा होती है, जिसकी सिफ़ारिश गृह मंत्रालय को भेजी जाती है. हालांकि, पिछले दो वर्षों से एमीनेंट फ्रीडम फाइटर कमेटी की बैठक नहीं हुई है, जबकि साल में दो बार इसकी बैठक कराने का प्रावधान है. उल्लेखनीय है कि एमीनेंट फ्रीडम फाइटर कमेटी की अंतिम बैठक जून, 2012 में देहरादून में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने की थी. इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों या उनके आश्रितों के लिए पेंशन एवं अन्य सुविधाओं की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई क़दम उठाए गए. बैठक के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन और अन्य कल्याणकारी उपायों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई. राज्य स्तर पर जाने-माने स्वतंत्रता सेनानियों की समिति गठित करना, स्वतंत्रता सेनानियों को दुरंतो, ग़रीब रथ और मेट्रो ट्रेन में कॉम्पलीमेंट्री पास देना, पारिवारिक पेंशन में योग्य आश्रितों के तौर पर विधवा-तलाकशुदा बेटियों को शामिल करना जिनकी अधिकतम संख्या तीन से ज़्यादा न हो, मूल सम्मान पेंशन में महंगाई भत्ते के एक भाग को मिलाना आदि बातें शामिल थीं.

अंग्रेजों से सीखें सैनिक सम्मान की भावना

स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों के लिए सम्मान और सुविधाओं की चर्चा होने पर यहां ब्रिटिश सरकार का ज़िक्र करना लाज़िमी है. अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध (1914) के अपने सिपाहियों की वफ़ादारी से खुश होकर उनकी अगली तीन पीढ़ियों के लिए जंगी इनाम की घोषणा की थी. भारत सरकार आज भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल सैनिकों के उत्तराधिकारियों को पेंशन दे रही है. इतना ही नहीं, अंग्रेज सरकार ने जाते-जाते अपने कई वफ़ादार सैनिकों को बड़ी-बड़ी जागीरों का मालिक भी बना दिया, जिसका लाभ आज भी उनके उत्तराधिकारियों को मिल रहा है. अफ़सोस! भारत सरकार अपने स्वतंत्रता सेनानियों की अगली एक पीढ़ी को भी पेंशन और अन्य सुविधाएं देने के लिए तैयार नहीं है. सरकार की इस संवेदनहीनता से देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानी निराश हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी ख़ुशियां न्यौछावर कर दी थीं.

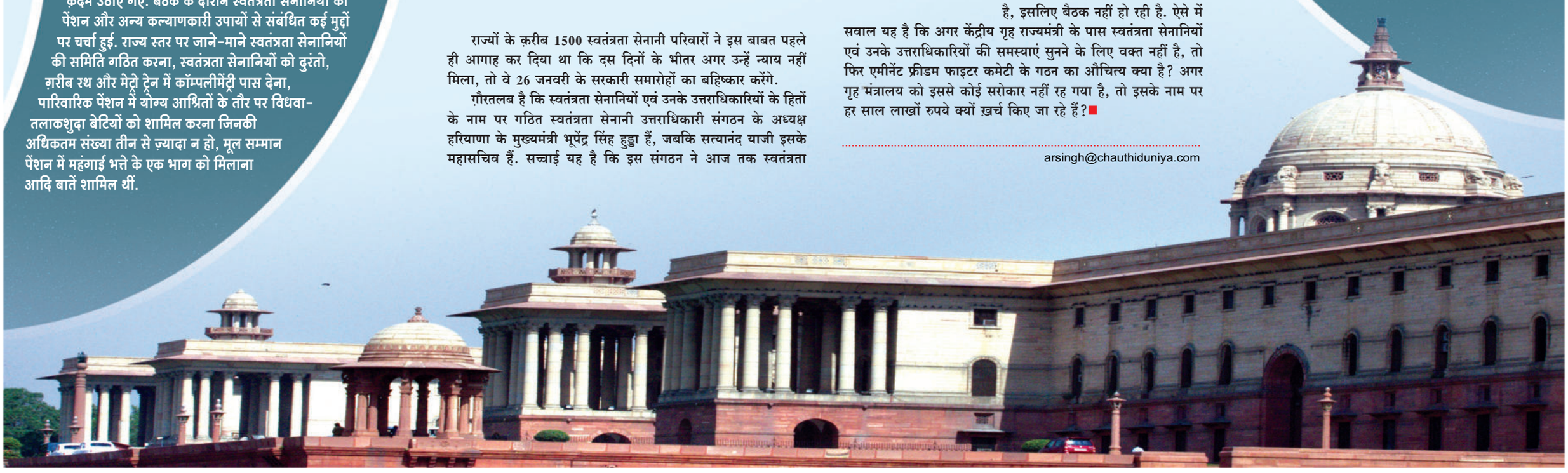

www.kamalmorarka.com

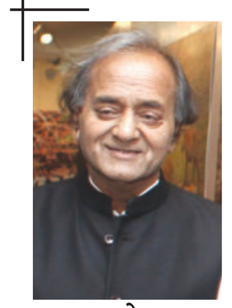

कमल मोरारका

लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत

संसद के इस सत्र में तेलंगाना राज्य को मंजूरी दी गई. हालांकि जिस तरीके से यह हुआ, बिना राज्य विधानसभा की मंजूरी लिए, वह भारत के संघीय ढांचे के ख़िलाफ़ है. अगर राज्यों के पुनर्गठन का निर्णय लिया जाना था, तो उसे अखिल भारतीय स्तर पर किया जाना चाहिए था. तेलंगाना एक मजबूत मामला है. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तेलंगाना नहीं बनना चाहिए था, लेकिन यह जिस तरीके से किया गया, वह लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत हानिकारक था. कांग्रेस के खुद के मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया. यह हमारे लोकतांत्रिक चेहरे की एक फूहड़ तस्वीर है.

इस लोकसभा का अंतिम सत्र समाप्त हो गया. इसके साथ ही यूपीए–1 और 2 के भी अंतिम सत्र का अंत हो गया है. चुनाव कौन जीतता है, यह एक खुला सवाल है. किसी भी सरकार के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए दस सालों का समय काफी है. पीछे मुड़कर पिछले दस सालों को देखें. मैं सरकार को आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ने के लिए ज़्यादा ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहता, जैसा कि कई लोग करते हैं. अमेरिका संकट में है, यूरोप संकट में है, अपेक्षाकृत भारत कम संकट में है. वित्तमंत्री पर दोष लगाने का क्या अर्थ है? उन्होंने वह नहीं किया, जो करना चाहिए था. उन्होंने जो किया, वह हमें कहीं नहीं ले जाता. अर्थशास्त्र का गंभीर छात्र भी सरकार के छोटे दोषों के बारे में बता सकता है, लेकिन कोई बड़ा दोष नहीं हो सकता. मुद्रास्फीति नियंत्रण में नहीं है और वह लोगों के बीच गुस्से का एक कारण है. मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आसान नहीं है. हालांकि, असली समस्या दस सालों के दौरान अन्य सभी मोर्चों से जुड़ी है, जो किसी आपदा से कम नहीं है.

सबसे पहले संसदीय मानदंडों, प्रक्रियाओं, सरकार के कामकाज, उसके मानक और प्रक्रियाओं को देखें. स्वतंत्र भारत के इतिहास में यूपीए–1 एवं 2 के दौरान इन सबकी जो अनदेखी हुई, उपेक्षा हुई, वह शायद कभी देखने को नहीं मिली थी. यूपीए–1 ने जो किया था, उसी का असर यूपीए–2 में देखने को मिला. एक विशेष तिथि के बाद एक निविदा जारी की गई, एक विशेष तिथि से पहले निविदा बंद कर दी गई. अपने लोगों को ठेके, खदान और स्पेक्ट्रम दे दिए गए. ऐसा जानबूझ कर पहले कभी नहीं किया गया. पिछले दस वर्षों में क्या हुआ, मैं यह देखने के बाद आश्चर्यचकित हूं. यहां तक कि नौकरशाही को भी यह समझना चाहिए कि अगर यही सब कुछ आगे भी होने जा रहा है, तो वह दिन दूर नहीं, जब इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा.

आख़िर क्यों सेना पाकिस्तान में सत्ता पर काबिज हो जाती है? वह देखती है कि राजनीतिज्ञ केवल अपनी जेब भर रहे हैं और वे आम लोगों के बारे में चिंतित नहीं हैं. ये नेता वह काम नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए जनता ने उन्हें सत्ता के लिए चुना था. वे जनादेश के बारे में चिंतित नहीं हैं. एक सीमा होती है. सीमा एक बार पार हो जाए, तब फिर सेना हस्तक्षेप करती है. मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी कोई तारीख भारत के इतिहास में कभी नहीं आएगी. लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन दस सालों में सत्ता में बैठे लोगों ने हस्तक्षेप करने के लिए सेना को भड़काने की अपनी अधिकतम कोशिश की. यह हमारा सौभाग्य है कि भारतीय सेना अपने कार्य के लिए समर्पित है और वह इस तरफ़ देखती भी नहीं.

संसद के इस सत्र में तेलंगाना राज्य को मंजूरी दी गई. हालांकि जिस तरीके से यह हुआ, बिना राज्य विधानसभा की मंजूरी लिए, वह भारत के संघीय ढांचे के ख़िलाफ़ है. अगर राज्यों के पुनर्गठन का निर्णय लिया जाना था, तो उसे अखिल भारतीय स्तर पर किया जाना चाहिए था. तेलंगाना एक मजबूत मामला है. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तेलंगाना नहीं बनना चाहिए था, लेकिन यह जिस तरीके से किया गया, वह लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत हानिकारक था. कांग्रेस के खुद के मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया. यह हमारे लोकतांत्रिक चेहरे की एक फूहड़ तस्वीर है. मैं नहीं समझता कि किसी भी सरकार ने इससे पहले इस तरीके से ऐसा सब कुछ किया हो.

संसदीय कार्यवाही को पूरी दुनिया देख रही थी. कागज छीने जा रहे थे. उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो कुछ हुआ, वह वहां पहले भी हुआ था, लेकिन ऐसा कभी लोकसभा और राज्यसभा में नहीं देखा गया था. आख़िर हम कहां जा रहे हैं? क्या हम लोकसभा और राज्यसभा के काम को बंद करना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पुलिस रखवाली में हो? क्या बचा है? मैं शर्मिंदा हूं. मैं राज्यसभा का सदस्य रहा हूं. मैंने लोकसभा की कार्यवाही को देखा है. अधिक से अधिक यही होता था कि कोई सदस्य एक–आध असंसदीय शब्द का इस्तेमाल कर लेता था, उसे भी रिकॉर्ड से हटा दिया जाता था. बस, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं.

अब हम कहां तक आ गए हैं! सदस्य महासचिव के साथ लड़ रहे हैं. लोग एक–दूसरे को पकड़ रहे हैं. इस सबके लिए कौन ज़िम्मेदार है? किसकी ज़िम्मेदारी इस सबको ठीक करने की है? जाहिर है, प्रधानमंत्री. वह सरकार के नेता हैं. सोनिया गांधी, जिन्हें मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का जनादेश मिला. मुझे लगता है कि वे अपने कर्तव्यों को भूल गए, आगामी चुनाव की जल्दी में. ऐसा कहने के लिए माफी चाहता हूं. वैसे कोई जल्दी नहीं थी. इतनी जल्दी दिखाने की जगह तेलंगाना का मुद्दा नई आने वाली सरकार के लिए छोड़ा जा सकता था.

उन्हें लगा कि वे तेलंगाना बना रहे हैं, कुछ सीटें मिल जाएंगी, लेकिन इससे उन्हें सत्ता नहीं मिलने जा रही है. भाजपा ने भी इसी डर से समर्थन दिया. वह पहले समर्थन का वादा भी कर चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से यह काम किया गया, उससे केवल ग़ैर–राजनीतिक बलों को ही ताकत मिलेगी. ऐसे लोग, जिन्हें हमेशा से लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता रहा है, उन्हें फिर से संसदीय लोकतंत्र के ख़िलाफ़ बोलने का अवसर मिलेगा. यही चीज ये सभी सांसद एक साथ मिलकर हासिल कर रहे हैं. क्या हम चाहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र ख़त्म हो जाए?

दो महीने बचे हैं संसदीय चुनाव के और अब संसद का कोई सत्र भी नहीं बचा है, इसलिए यह सब सुधारा नहीं जा सकता है. लेकिन, मैं सोचता हूं कि सभी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस और भाजपा की ओर से इस चुनाव में स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि नई लोकसभा में उचित नियमों का पालन किया जाएगा. अध्यक्ष सख्त होगा. एक और बात, जिसके बारे में मैंने सुना कि कांग्रेस पार्टी को सुबह से ही यह बात पता थी कि काली मिर्च का स्प्रे किया जाना है. सब कुछ सुनियोजित था. बावजूद इसके, उन लोगों ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया. यह शर्मनाक है. वे शासन करने के लायक नहीं हैं. अब हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि नई संसद ही हमें रास्ता दिखाएगी और समृद्धि, विकास एवं लोकतांत्रिक कामकाज की ओर भारत को वापस ले जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

दो महीने बचे हैं संसदीय चुनाव के और अब संसद का कोई सत्र भी नहीं बचा है, इसलिए यह सब सुधारा नहीं जा सकता है. लेकिन, मैं सोचता हूं कि सभी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस और भाजपा की ओर से इस चुनाव में स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि नई लोकसभा में उचित नियमों का पालन किया जाएगा. अध्यक्ष सख्त होगा. एक और बात, जिसके बारे में मैंने सुना कि कांग्रेस पार्टी को सुबह से ही यह बात पता थी कि काली मिर्च का स्प्रे किया जाना है. सब कुछ सुनियोजित था. बावजूद इसके, उन लोगों ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया. यह शर्मनाक है. वे शासन करने के लायक नहीं हैं.

राजनीति नहीं, लोकनीति चाहिए

आचार्य राममूर्ति

प्रश्न–लोक उम्मीदवार कितने क्षेत्रों में खड़े होंगे?

उत्तर–देश भर में अधिक से अधिक जितने क्षेत्रों में खड़े हो सकें. जनता आज की राजनीति से ऊब गई है. उसने बारी–बारी से सभी दलों का शासन देख लिया है. अब वह विकल्प चाहती है. कुछ महीने पहले उसने ऐसे नेता को जिताया, जो कभी राजनीति में नहीं था, क्योंकि उसने सोचा कि यह नेता कुछ अच्छा और नया काम करेगा. इसलिए हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को सोचना चाहिए कि उम्मीदवार के चयन का काम वे किसी दूसरे पर न छोड़कर अपने हाथ में लें, ताकि प्रतिनिधियों पर उनका अंकुश रहे और वे सही ढंग से सरकार चला सकें. एक बार लोक उम्मीदवार की हवा बह जाए, तो काम कठिन नहीं होगा.

प्रश्न–लोकनीति क्या है?

उत्तर–लोक यानी जनता, लोकतंत्र यानी जनता का राज. कहा जाता है कि देश में लोकतंत्र है, लेकिन क्या सचमुच जनता का राज है? जनता से 5 साल में एक बार या उससे पहले वोट देने को कहा जाता है. उम्मीदवार तय करते समय उससे नहीं पूछा जाता. हर दल अपने उम्मीदवार तय करता है और जनता से वोट की मांग करता है. कुछ लोग स्वतंत्र खड़े हो जाते हैं और जनता से वोट देने की अपील करते हैं. उम्मीदवार मतदाताओं को पसंद हो या नहीं, लेकिन उन्हें किसी न किसी उम्मीदवार को वोट देना है. यह क्या है? पहले जमाने में स्वयंवर होता था, जिसमें कन्या को स्वयंवर में आए हुए युवकों में से किसी एक के गले में जयमाल डालनी पड़ती थी. क्या चुनाव आज के जमाने का राजनीतिक स्वयंवर है, जो लोकतंत्र के नाम से रचा जा रहा है? कोई समय था, जब राजाओं का शासन होता था. राजा के बाद उसका बेटा राजा होता था, लेकिन जागृति बढ़ी, तो जनता ने संघर्ष किया और यह सिलसिला समाप्त हुआ. तब जनता अपने प्रतिनिधि चुनने लगी और उन्हीं प्रतिनिधियों के हाथ में शासन की बागडोर सौंपी गई. अपने देश में राजाओं का राज था, जिनकी जगह पर अंग्रेजों ने अपना राज कायम किया. 1947 में अंग्रेजी राज का अंत हुआ. जिन नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई में अगुवाई की थी, उन्हीं के हाथ में जनता ने राज–पाट सौंपा. लेकिन क्या हुआ? पिछले 35–36 वर्षों में कई सरकारें बदलीं, किंतु शासन दिनोंदिन अधिक से अधिक भ्रष्ट एवं निकम्मा होता गया और प्रतिनिधि निरंकुश एवं जनविरोधी बनते गए. प्रभुता के मद ने सबको घेर लिया. सारी सत्ता सरकार के हाथ में केंद्रित हो गई और जनता मोहताज एवं असहाय. अब जनता छटपटा रही है.

इस स्थिति से निकलने का उपाय है:

1–जनता संगठित होकर अपने दैनंदिन जीवन को अपने हाथ में लेने को तैयार हो.

2–सरकार में अपने प्रतिनिधि भेजे और उन पर अंकुश रखे. अगर लोकतंत्र में लोक मालिक है, तो उसे अपना राज–काज चलाने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी और अपने प्रतिनिधियों को कठोर अंकुश में रखना पड़ेगा. कोई दूसरा हमारा काम कर दे, सुराज ला दे, यह कहने से अब काम नहीं चलेगा.

व्यवहार में यह होगा कि हर गांव एवं टोला संगठित होगा और उसमें रहने वाले बालिग स्त्री–पुरुषों को मिलाकर ग्रामसभा बनेगी. ग्रामसभा गांव की व्यवस्था चलाएगी. शांति, विकास, सामान्य न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, रोज़गार एवं मज़दूरी आदि सब काम गांव के भीतर ग्रामसभा ही करेगी. ग्रामसभा ज़रूरत के अनुसार सरकार से सहायता लेगी, लेकिन गांव के दैनंदिन जीवन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होने देगी. ग्रामसभा स्वायत्त होगी, क़ानून एवं संविधान में उसके अधिकार सुरक्षित किए जाएंगे. हर गांव कम से कम भोजन और वस्त्र के मामले में स्वावलंबी होगा. उसकी अर्थनीति खेती, पशुपालन एवं उद्योग के आधार पर चलेगी.

अगर देश के लाखों गांवों और शहरों को स्वायत्त इकाइयों के रूप में विकसित करना हो, तो अनिवार्य है कि सरकार में ऐसे प्रतिनिधि जाएं, जो इस बात को कहें और इसके लिए लड़ें. आज दलों द्वारा जो प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं, उनसे यह काम नहीं हो सकता. गांव से जाने वाले प्रतिनिधि भी राजधानी में जाकर राजधानी के हो जाते हैं, क्योंकि उन पर कोई अंकुश नहीं रहता और गांव के पास कोई अधिकार एवं साधन न रहने के कारण वे असहाय हो जाते हैं. आज की राजनीति राजधानियों की राजनीति है, जहां स्वार्थों का बोलबाला है. हर अधिकार राजधानी में है और छोटी से छोटी चीज का उत्पादन गांवों से निकाल कर शहरों एवं बड़े केंद्रों में पहुंचा दिया गया है. सत्ता और संपत्ति के केंद्रीकरण पर यह राजनीति पल रही है और जनता दमन एवं शोषण की चक्की में पिस रही है.

इस स्थिति को बदलना है. केंद्रीकरण के विष को निकालने के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक है. विकेंद्रीकरण हर चीज का हो यानी अधिकार का, उत्पादन का, व्यवस्था आदि सबका. यह लोकनीति की दिशा है. लोक उम्मीदवार उस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण क़दम है. पहुंचना है हमें ग्राम–स्वराज्य तक. वही हमारा ध्रुवतारा है. गांव में हर व्यक्ति ईमान की रोटी खाए और इज्जत की ज़िंदगी जिए. किसी की छाती पर कोई सवार न हो. व्यवस्था लाठी–गोली से नहीं, आपस के प्रेम और सहकार से चले. सरकार उतनी हो, जितनी ज़रूरी हो. इतना हो जाए, तब समझिए कि गांव–गांव में स्वराज का सुख आ गया. गांधी जी कहते थे कि हमारे देश में गणतंत्र है, तो हर गांव एक छोटा गणतंत्र क्यों न बने? हम सब अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानें और सही दिशा में क़दम बढ़ाएं, तो वह दिन शीघ्र आएगा, आकर रहेगा. उसके लिए राजनीति नहीं, लोकनीति चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

व्यवहार में यह होगा कि हर गांव एवं टोला संगठित होगा और उसमें रहने वाले बालिग स्त्री-पुरुषों को मिलाकर ग्रामसभा बनेगी. ग्रामसभा गांव की व्यवस्था चलाएगी. शांति, विकास, सामान्य न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, रोज़गार एवं मज़दूरी आदि सब काम गांव के भीतर ग्रामसभा ही करेगी. ग्रामसभा ज़रूरत के अनुसार सरकार से सहायता लेगी, लेकिन गांव के दैनंदिन जीवन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होने देगी. ग्रामसभा स्वायत्त होगी, क़ानून एवं संविधान में उसके अधिकार सुरक्षित किए जाएंगे.

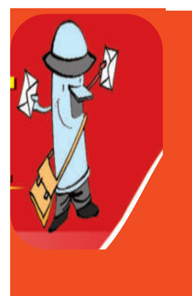

पाठकों की दुनिया

अस्तित्व के संकट में कांग्रेस

बीते 10 दिसंबर को अन्ना हजारे के अनशन पर बैठते ही केंद्र सरकार को ठंडे बस्ते में पड़ा लोकपाल विधेयक का याद आना और उसे पारित कराने पर जोर देने की सबसे बड़ी वजह दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत है और अन्ना द्वारा अनशन पर बैठना भी. चार दशकों से लंबित यह विधेयक संसद के इसी सत्र में क़ानून का रूप लेगा, यह यक्ष प्रश्न है. कांग्रेस अस्तित्व के संकट से जूझ रही है. ऐसा ही संकट कांग्रेस पर आपातकाल के बाद हुए चुनाव में आया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे उबार लिया था. इस समय कांग्रेस के सामने भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसने अपने नेता एवं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस राहुल गांधी को मोदी के मुकाबले खड़ा करने का साहस नहीं दिखा सकी. उसकी हताशा साफ़ नज़र आ रही है. कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण और प्रायश्चित की आवश्यकता है, लेकिन वह कोई सबक लेने को तैयार नहीं है.

–**गौरव निर्मोही, *दरभंगा, बिहार.***

कांग्रेस की दुविधा

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में विजन–2014 पेश करके उन तमाम टिप्पणीकारों एवं समीक्षकों की बोलती पर विराम लगा दिया, जो अक्सर कहते थे कि कांग्रेस पर लांछन लगाने के बजाय मोदी देश को बताएं कि उनकी सरकार बनने पर वह क्या करने वाले हैं और उनका विजन क्या है? उनके धुर विरोधी एवं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अभी पार्टी संगठन की कील–कांटे कसने में व्यस्त हैं. कांग्रेस यह तक नहीं सोच पाई कि वह राहुल को आगे करे या नहीं. कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में हार के डर से राहुल को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया. राहुल को पीएम उम्मीदवार घोषित करने पर दो राय थी. एक धड़ा चाहता था कि आम चुनाव से पहले राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, जबकि दूसरा इसके ख़िलाफ़ था, ताकि अगर कांग्रेस चुनाव हार जाए, तो राहुल को उसकी ज़िम्मेदारी से बचाया जा सके.

–**आभा शुक्ला, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.***

अन्ना की जीत

यह एक आम आदमी की ताकत का नतीजा है कि राजनीति ने भ्रष्ट होने की तरफ़ तेजी से जा रहे क़दम रोकने का संदेश समझा है. अन्ना हजारे का आंदोलन देश के लोकतांत्रिक ढांचे का नया आयाम है. पिछले दिनों एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी स्वीकार किया कि अन्ना के आंदोलन ने लोकतांत्रिक राजनीति की वह पुरानी सोच बदल दी है, जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होता है. इस दौरान सरकार के कामकाज की समीक्षा होती थी. एक दशक पूर्व कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ग़ैर–सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता न सिर्फ़ अवाम के हित में अपनी सोच के अनुसार एक खास क़ानून बनाने की मांग करेंगे, बल्कि अपना मॉडल लागू करने के लिए अड़ भी जाएंगे. पूर्व में मंत्रिमंडलीय समूह के प्रमुख के रूप में प्रणब मुखर्जी ने ही लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार किया था, जिसे संशोधनों के साथ पारित किया गया. अब राष्ट्रपति के रूप में उन्हीं के हस्ताक्षर से यह क़ानून बनेगा. लोकपाल विधेयक पारित होना एक स्वागतयोग्य क़दम है. अन्ना हजारे के संघर्ष और प्रतिबद्धता को सही सम्मान आख़िरकार केंद्र सरकार को देना पड़ा. यह सभी देशवासियों की जीत है.

–**अशोक निर्मोही, *दरभंगा, बिहार.***

केजरीवाल का सत्ता प्रेम

17–23 फरवरी का अंक मिला. कवर स्टोरी–चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में मनीष कुमार ने अरविंद केजरीवाल के बारे में जो लिखा है, उससे साफ़ पता चलता है कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को किस तरह सपने दिखाए और 28 सीटें जीतने में कामयाब रहे. केजरीवाल ने लोगों को केवल बेवकूफ बनाया. चुनाव से पहले उन्होंने जो वादे किए थे, उनसे वह भागते नज़र आए. जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने चुनाव लड़ा, उसी से गठबंधन कर सरकार बनाई. फिर अपनी साख गिरते देखकर सोचा कि अब कैसे त्यागपत्र दिया जाए. इसके लिए उन्होंने बहाना ढूंढा जनलोकपाल बिल का और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देकर भाग निकले.

–**तरुणा सिंह, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.***

प्रशंसनीय क़दम

अपने प्रकाशन की शुरुआत से ही चौथी दुनिया ने अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के उत्थान एवं विकास का झूठा दावा करने वाली पार्टियों को बेनकाब किया. यह एक प्रशंसनीय क़दम है. मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाकर चौथी दुनिया ने यह सिद्ध कर दिया कि यह एक बेबाक समाचारपत्र है, जिसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है. देश का मुसलमान उम्मीद करता है कि यह समाचारपत्र उनके पिछड़ेपन से जुड़े मुद्दे उठाकर सरकार का ध्यान उनकी तरफ़ आकर्षित करेगा, साथ ही मुसलमानों की दशा सुधारने का तरीका भी बताएगा.

–**जावेद अंसारी, *देवरिया, उत्तर प्रदेश.***

पैसे कहां उगते हैं?

नीरज सिंह का आलेख–देश के नेताओं से सीखिए पेड़ पर पैसा उगाने की कला (अंक:17–23 फरवरी) पढ़ा. यह जानकर हैरानी होती है कि सरकारी वकील ही सरकार को चूना लगाने का कार्य कर रहे हैं. एलआईसी, जो भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, वह सरकार को कैसे चूना लगा रही है. यह कंपनी आयकर डिफाल्टरों की सूची में है. इससे साफ़ पता चलता है कि सरकारी तंत्र में किस प्रकार भ्रष्टाचार फैला हुआ है. यह है सच कि पैसा कहां से आता है और कहां चला जाता है.

–**भूपेंद्र सिंह, *सतना, मध्य प्रदेश.***

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

आज़ादी का संघर्ष चलता रहेगा

अब लोकसभा का कोई सत्र नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा का आख़िरी सत्र समाप्त हो गया और अब नई लोकसभा के चुनाव यानी 2014 के आम चुनाव की तैयारियों में सब लोग जुट गए हैं. इस महान लोकसभा के ऊपर साधारण आदमी कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम टिप्पणी करेंगे, तो यह माना जाएगा कि हम लोकसभा की अवमानना कर रहे हैं. यद्यपि यही वह लोकसभा है, जिसने घोटाले उजागर होने का रिकॉर्ड बनाया और किसी भी घोटाले की कोई जांच नहीं की. इस अपराध में सिर्फ़ सरकार नहीं शामिल है, इस अपराध में पूरी लोकसभा शामिल है, लोकसभा में बैठी हर पार्टी शामिल है.

आर्थिक अपराधों की, आर्थिक घोटालों की अगर सूची बनाएं, तो लगभग हर दूसरा हफ्ता एक घोटाले के खुलासे का गवाह बना. बहुत सारे घोटालों पर तो संसद ने संज्ञान ही नहीं लिया. संसद लोगों के सवालों पर सोच ही नहीं पाई. पूरे पांच साल में महंगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोज़गारी जैसे ब्लड कैंसर पर इस संसद ने कोई ध्यान ही नहीं दिया. वे त्योहार जैसे दिन रहे होंगे, जब इनका जिक्र इस संसद में हुआ होगा. जाहिर है, ये विषय सांसदों को शायद परेशानी पैदा करते रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने इनके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं की. यह संसद हंगामे की वजह से कामकाज न करने के रिकॉर्ड बनाने में लगी रही. सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में समझौता करके जाता था कि संसद को नहीं चलने देना है. इससे सत्ता पक्ष का और विपक्ष का भी मिला–जुला हित सधता था. यह संसद लोगों की आशाओं की हत्या करने का एक अड्डा भी बनी रही.

अगर संसद की अवमानना न मानें, तो कहना चाहेंगे कि इस संसद ने राजनीतिक शालीनता की मर्यादाएं समाप्त कर दीं. इस संसद ने सही मायनों में ऐसा दृश्य देश को दिखाया, जिसे देखकर पूरे देश के लोग शर्मिंदा हो गए. उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद आपस में लड़े, गाली–गलौच की, मारपीट की, धक्का–मुक्की की और पराकाष्ठा तब हुई, जब मिर्च वाले स्प्रे को एक सांसद ने सदन में स्प्रे किया. एक सांसद ने चाकू निकाला और बता दिया कि सांसद असामाजिक तत्व जैसी हरकतें कर सकते हैं. अगर आप संसद में चाकू ले जा सकते हैं, तो कल आप संसद में रिवॉल्वर और बम भी ले जा सकते हैं और संसद को आपराधिक तौर पर अगवा कर सकते हैं, बंधक बना सकते हैं. शायद यह संसद अपने सदस्यों का वह अधिकार छिनने का आधार बना गई, जिसके तहत उनकी तलाशी नहीं ली जाती. संभव है कि अब अगर कोई सांसद संसद में आए, तो उसकी तलाशी ली जाए.

सांसद की यह पात्रता होती है कि वह प्रधानमंत्री भी बन सकता है, इसलिए किसी सांसद की तलाशी नहीं होती. हालांकि कुछ सांसदों की तलाशी गलती से जब हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा जांच के समय होती है, तो वे बहुत नाराज़ होते हैं, लेकिन संसद में जिस शर्मनाक दृश्य को लोगों ने देखा, उससे संभव है कि अब शायद हर सांसद की तलाशी हो. राजनीतिक दल जब अपराधियों को टिकट देंगे, तो संसद में ऐसा दृश्य आम तौर पर दिखाई ही देगा. हालांकि जो सज्जन इन दोनों घटनाओं में शामिल थे, वे करोड़पति सांसद हैं. इसका मतलब यह है कि पैसा अपराध की जहनियत नहीं बदलता.

सवाल सिर्फ़ इतना है कि इस संसद ने देश का पैसा खुली आंखों से जागते हुए लुटने दिया. सबसे बड़ा घोटाला कोयला घोटाला हुआ, जिसमें 26 लाख करोड़ रुपये का आकलन संसद की खुद की समिति ने किया. सीएजी ने इस घोटाले को एक लाख, 76 हज़ार करोड़ रुपये का बताया, जिसे चौथी दुनिया ने चुनौती दी, क्योंकि इस कोयला घोटाले की ख़बर सबसे पहले हमने अपने अख़बार में छापी थी. हमारी इस ख़बर का और हमारी इस चुनौती का संसद ने कोई जवाब नहीं दिया. दरअसल, संसद ने भ्रष्टाचार से जुड़े किसी सवाल का कहीं कोई जवाब दिया ही नहीं और राजनीतिक मख़ौल यह कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ने का वादा करते हुए आस्तीन चढ़ाते दिखाई दिए. उन्होंने एक शब्द भी बड़े घोटालों पर कहा ही नहीं. बड़े घोटाले से मेरा मतलब है, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और कोयला घोटाला. कल्पना से परे पैसे की लूट के ये कुछ नाम हैं. राहुल गांधी भ्रष्टाचार के इन तमगों पर इस तरह बोलते दिखाई दिए, जैसे किसी और सरकार ने ये घोटाले किए हों और कोई और सरकार हो, जो इन घोटालों की जांच न करा रही हो.

दूसरी तरफ़ भारतीय जनता पार्टी किसी भी बहस से बचती दिखाई दी. भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का रोल सही ढंग से निभाया ही नहीं. उसने किसी भी सवाल पर न संसद के अंदर बहस की, न उसने संसद के बाहर सड़कों पर लोगों को जगाने का काम किया. उसने साल में कुछ दिन चुने और उन दिनों में उसने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ कुछ प्रदर्शन किए, कुछ बड़े नेता भीड़ के सामने भाषण दे आए और भारतीय जनता पार्टी ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं निश्चित कर लिया और इसके दावे भी करने लगी. ठीक ऐसे दावे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद 2004 में श्री आडवाणी जी को लेकर भी किए गए थे, लेकिन आशाएं पालना अच्छी बात है और देश के लोगों को बुद्धिहीन मानना बिल्कुल दूसरी बात.

नरेंद्र मोदी देश के लोगों को हाजिर–नाजिर कर सत्ता में आने का और विकास के रास्ते पर सरपट चलने का वादा करते हैं, लेकिन विकास कौन सा, आर्थिक नीतियां कौन सी? क्योंकि, अरुण जेटली ने इसे बिल्कुल साफ़ किया और नरेंद्र मोदी के शब्दों को उन्होंने सच साबित किया कि आर्थिक नीतियां यही रहेंगी. चूंकि कांग्रेस ने इनका सही ढंग से पालन नहीं किया, वह इनका सही ढंग से पालन करेंगे. भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अब अरविंद केजरीवाल खुली बाज़ार व्यवस्था और नव–उदारवादी आर्थिक नीति के पूरी तरह से पोषक दिखाई दे रहे हैं, जिस नीति ने इस देश के लोगों की थाली से रोटी, हाथ से काम और ज़िंदगी से ईमानदारी छीन ली है.

संसद में भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजहीन दिखाई दिए, क्योंकि शायद संसद के बाहर नरेंद्र मोदी का दिल्ली की तरफ़ बढ़ना उनके लिए किसी दु:स्वप्न से कम नहीं है. हमेशा ऐसा होता है कि सवाल दूर चले जाते हैं, जवाब कहीं होते नहीं और बीच में तमाशे हो जाते हैं तथा इस देश का साधारण आदमी उन तमाशों में उलझ कर रह जाता है.

इस संसद ने जनता के दबाव पर देश से वादा किया और उस वादे को तब तक नहीं निभाया, जब तक दोबारा अन्ना हजारे ने अपना जीवन दांव पर नहीं लगा दिया. लोकपाल बिल पास तो हुआ, लेकिन लोकपाल क़ानून यह संसद और संसद का कार्यकाल लागू कर नहीं पाए. क़ानून शायद अगली संसद यानी आम चुनाव के बाद लागू हो. देश को अभी दु:ख भरी पगडंडियों से गुजरना पड़ेगा.

इस संसद ने लोकतंत्र की तौहीन की, लोकतंत्र के ऊपर से भरोसा ख़त्म किया और देश से प्यार करने वाले लोगों को यह बताया कि गांधी जी ने जो लड़ाई शुरू की थी, वह अभी ख़त्म नहीं हुई है. देश को आज़ादी दिलाने का संघर्ष चलता रहेगा. पीढ़ियां कुर्बान हो गईं, शायद पीढ़ियां कुर्बान होंगी. ■

editor@chauthiduniya.com

अगर संसद की अवमानना न मानें, तो कहना चाहेंगे कि इस संसद ने राजनीतिक शालीनता की मर्यादाएं समाप्त कर दीं. इस संसद ने सही मायनों में ऐसा दृश्य देश को दिखाया, जिसे देखकर पूरे देश के लोग शर्मिंदा हो गए. उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद आपस में लड़े, गाली-गलौच की, मारपीट की, धक्का-मुक्की की और पराकाष्ठा तब हुई, जब मिर्च वाले स्प्रे को एक सांसद ने सदन में स्प्रे किया. एक सांसद ने चाकू निकाला और बता दिया कि सांसद असामाजिक तत्व जैसी हरकतें कर सकते हैं. अगर आप संसद में चाकू ले जा सकते हैं, तो कल आप संसद में रिवॉल्वर और बम भी ले जा सकते हैं और संसद को आपराधिक तौर पर अगवा कर सकते हैं, बंधक बना सकते हैं.

मेघनाद देसाई

कैसी होगी अगली लोकसभा

केजरीवाल का लक्ष्य लोकसभा है. बकौल योगेंद्र यादव, लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बड़ी सफलता हासिल होगी और केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं. लिहाजा, केजरीवाल दिल्ली को शहादत के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि वह राष्ट्रीय नेता बन सकें. लेकिन, यह तभी मुमकिन होगा, जब कांग्रेस या भाजपा उन्हें ऐसा करने देगी. राजनीतिक माहौल हालात के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा धुंधला हो रहा है. पिछले कुछ दशकों से पीढ़ियों और विचारों के प्रसार पर नियंत्रण रखने वाला अधिपति वर्ग भाजपा के प्रधानमंत्री प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से झटके में आ गया है.

परपीड़क स्वपीड़क के प्रति सहानुभूति का भाव रखता है. अरविंद केजरीवाल की किसी भी क़ीमत पर इस्तीफ़ा देने की तीव्र इच्छा को रौंदना भाजपा और कांग्रेस के लिए क्रूरता जैसा क़दम होगा. बतौर आंदोलनकारी, दुर्भाग्यवश खुद को अराजक नेता बता देने वाले केजरीवाल को हर दिन एक नई लड़ाई के बारे में सोचना होता है, ताकि उनके चाहने वाले और समर्थक यह न सोचने लगें कि वह बिक गए हैं. पुराने वामदल से टूटकर अलग हुए कई समूहों की तरह आम आदमी पार्टी को भी हर दिन कुछ नया करना पड़ता है. साथ ही कुछ नई घोषणाएं करनी होती हैं. उन्हें स्थायी क्रांति का वादा करना पड़ता है और हर वक्त शहादत के रास्ते तलाशते रहना होता है. हालांकि, केजरीवाल एक चतुर रणनीतिकार हैं. ख़बरों में बने रहना, बातचीत करते रहना, देश भर में पार्टी के लिए अपील करते रहना बहुत ही शानदार और तर्कशील योजना है. दिल्ली उनके लिए अभ्यास का मैदान था, लेकिन इसने इतना दे दिया कि उन्हें अब इसकी ज़रूरत ही नहीं रह गई.

केजरीवाल का लक्ष्य लोकसभा है. बकौल योगेंद्र यादव, लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बड़ी सफलता हासिल होगी और केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं. लिहाजा, केजरीवाल दिल्ली को शहादत के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि वह राष्ट्रीय नेता बन सकें. लेकिन, यह तभी मुमकिन होगा, जब कांग्रेस या भाजपा उन्हें ऐसा करने देगी. राजनीतिक माहौल हालात के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा धुंधला हो रहा है. पिछले कुछ दशकों से पीढ़ियों और विचारों के प्रसार पर नियंत्रण रखने वाला अधिपति वर्ग भाजपा के प्रधानमंत्री प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से झटके में आ गया है. उन्होंने ऐसे किसी झटके की उम्मीद भी नहीं की थी. वे कहते हैं कि निश्चित तौर पर यह कॉरपोरेट घरानों की ताकत का असर है या कोई षड्यंत्र है. वे बार–बार विचार और उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा. वहीं, तीसरे मोर्चे की गतिविधियां भी इस अधिपति वर्ग की चिंता का सबब बन रही हैं. तेजी से बदलते हुए राजनीतिक माहौल ने भाजपा को नकारने के लिए एक नए गठबंधन का प्रादुर्भाव किया. तीसरे मोर्चे को भी लगता है कि उसके पास सरकार बनाने का मौक़ा है.

तमिलनाडु में एक अम्मा हैं, जिन्हें राज्य में 35 संसदीय सीटों पर जीत मिलने पर अपने लिए बड़ी उम्मीद है. लिहाजा, जयललिता ने माकपा और भाकपा को साथ मिला लिया. दोनों ही ईसाई दुल्हन की उस सहेली की तरह साथ आ गए, जिसे उम्मीद होती है कि एक दिन वह भी दुल्हन का फेंका हुआ गुलदस्ता लपकने में कामयाब होगी. उनके बाद दीदी हैं. वह भी ग़ैर–कांग्रेस, ग़ैर–भाजपा और ग़ैर–वामदल के तीसरे मोर्चे की नेता के तौर पर अपनी उम्मीदें पाले बैठी हैं. ममता बनर्जी को भी पश्चिम बंगाल में 35 सीटें जीतने की उम्मीद है. इसके सहारे वह भी तीसरे मोर्चे की पीएम प्रत्याशी का दावा कर रही हैं. उनके बाद हैं बहन जी. वह 15 अगस्त, 2014 को लालकिले की प्राचीर से तिरंगा फहराना चाहती हैं. अगर मायावती सपा के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से फायदा उठा पाईं, तो उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 40 सीटें जीत सकती है. दरअसल, सपा ने हिंदू वोट बैंक के लिए अपना परंपरागत मुस्लिम मतदाता गंवा दिया है. राजनीति में हो रहा हर तेज बदलाव आपके सामने पीएम बनने की उम्मीदों से लबरेज एक नया नेता पेश कर देता है. उन्हीं में एक हैं केजरीवाल, जो 30–40 सीटें जीतने की आस लगाए बैठे हैं.

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव भी अर्से से पीएम बनने का सपना संजोए बैठे हैं. शरद पवार, नवीन पटनायक एवं नीतीश कुमार के सपने भी कुछ अलग नहीं हैं. ये चारों नेता अपने क्षेत्रों में 20 सीटें ही जीत सकते हैं. इनकी अपेक्षाएं तेजी से बदलती राजनीति के नाटकीय मोड़ पर निर्भर हैं. समस्या यह है कि इन सपनों के साथ ये सभी तीसरा मोर्चा बनाने के लिए संगठित होना चाहते हैं, जो संभव नहीं है.

वर्ष 1999 और 2004 में कांग्रेस और भाजपा मिलकर 300 सीटें हासिल करने में नाकाम रहीं. वर्ष 2009 में कांग्रेस ने सभी को चौंकाते हुए 200 से ज़्यादा सीटें जीतीं और दोनों बड़े दल मिलकर 300 का आंकड़ा पार गए. इस बार कांग्रेस को 100 सीटें मिलने की भी उम्मीद नहीं है. उम्मीद है कि यह पार्टी 80 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी. हालांकि, भाजपा 230 से ज़्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है. इसके ख़िलाफ़ दलील दी जा सकती है कि देश के कई हिस्सों में भाजपा की मौजूदगी ही नहीं है. लिहाजा, कहा जा सकता है कि उन इलाकों में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी. पिछली बार विशेषज्ञों ने मतगणना की सुबह यही दलील देते हुए कहा था कि कांग्रेस 175 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, जबकि कांग्रेस ने 200 से ज़्यादा सीटें जीती थीं. इस बार फिर मुझे लग रहा है कि एक स्पष्ट विजेता सामने आएगा. मुझे अम्मा, बहन जी और दीदी के लिए दु:ख है. ■

feedback@chauthiduniya.com

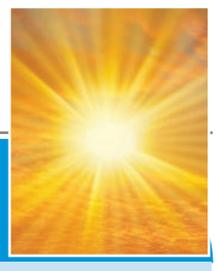

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

बीपीएल चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे आएगी?

चौथी दुनिया ब्यूरो

इस अंक में हम एक ऐसी समस्या पर बात कर रहे हैं, जो सीधे-सीधे ग़रीबों के अधिकारों और विकास से जुड़ी हुई है, यानी बीपीएल सूची, जिसके आधार पर ग़रीबों को बहुत-सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, मसलन सस्ता राशन, इंदिरा आवास या फिर पेंशन. जिस देश की अधिकांश आबादी ग़रीब हो, वहां यह ज़रूरी हो जाता है कि ग़रीबों से जुड़ी योजनाएं ईमानदारी से लागू की जाएं. लेकिन व्यवहार में अब तक यही देखने को मिला है कि ग़रीबों के विकास के लिए बनाई गईं लगभग सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, चाहे वह मनरेगा हो या इंदिरा आवास योजना. इसीलिए इन योजनाओं का फ़ायदा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जो इसके हक़दार होते हैं या जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. ग़रीबों के लिए बनी योजनाओं में घोटाले की ख़बरें आएदिन आती रहती हैं.

ज़ाहिर है, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे लोग किसी भी प्रकार से अपना नाम बीपीएल सूची में शामिल करा लेते हैं, नतीजतन, जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जिन्हें वाक़ई सरकारी मदद की ज़रूरत होती है, वे इससे वंचित रह जाते हैं. कई राज्यों में तो बीपीएल सूची में एपीएल श्रेणी के लोग भी अपना नाम दर्ज करा लेते हैं. ज़ाहिर है, ऐसा सरकारी अधिकारियों एवं स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों (पंचायत प्रतिनिधियों) की मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं है. इस अंक में ऐसा ही एक आवेदन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से आप बीपीएल सूची में पारदर्शिता लाने का दबाव डाल सकते हैं और साथ ही सूची तैयार करते समय उसमें होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ या उनका ख़ुलासा कर सकते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस आवेदन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(बीपीएल के चयन के लिए हुए सर्वे का विवरण)

सेवा में, दिनांक.....
लोक सूचना अधिकारी
विभाग का नाम.....
विभाग का पता.....

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन.

महोदय,
.....ग्राम में ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सर्वे के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करें:-

1. उपरोक्त गांव में ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्डधारक कितने हैं? उनकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:-
   क. कार्डधारक का नाम.
   ख. पिता का नाम.
   ग. कार्ड संख्या.
   घ. कार्ड पर सदस्यों की संख्या (यूनिट).
2. उपरोक्त कार्डधारकों का ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) का कार्ड किस आधार पर बनाया गया? इस संबंध में कार्डधारक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
3. उपरोक्त गांव में ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) केपरिवारों का सर्वे पिछली बार कब हुआ था? उस सर्वे रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं, साथ ही सर्वे करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं पद बताएं.
4. ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के सर्वे के समय चयन के लिए क्या मापदंड/मानक बनाए गए हैं? इस संबंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
5. उपरोक्त सर्वे के उपरांत क्या कोई पुन:निरीक्षण (रिव्यू) किया गया? यदि हां, तो समस्त दस्तावेज़ों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
6. पुन:निरीक्षण (रिव्यू) के संबंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
7. सर्वे के दौरान क्या किसी अनियमितता का मामला सामने आया है? यदि हां, तो शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई? विवरण दें.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नं.....

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301, ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
कोई भी कार्य सावधानीपूर्वक करें. शत्रुओं से सावधान रहें. पैसों का आना-जाना लगा रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
आप कार्य के दौरान रोमांचित एवं उत्साहित रहेंगे. आपने जिसकी कल्पना तक नहीं की होगी, वैसी सफलता से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. घर-परिवार में सुखद माहौल बनेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है. किसी ख़ास योजना का क्रियान्वयन होगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
जीवनशैली सुधारने और विकास के लिए कार्य विस्तार की योजना बनाएंगे. दांपत्य जीवन में नाराजगी हो सकती है. जमीन-जायदाद खरीदने की योजना बना सकते हैं, लेकिन दस्तावेजों की जांच-पड़ताल अवश्य कर लें. यात्रा पर जा सकते हैं. व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
आय के नए स्रोत बनेंगे. आपको कुछ नया करने के लिए मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. नौकरी पेशा एवं व्यापारी, दोनों अपने कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि रहेगी.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
कार्यों में आपकी कुशलता से गतिशीलता आएगी. कार्यस्थल पर सहयोगियों का साथ प्राप्त होगा. परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है. जमीन-जायदाद खरीदने की योजना बनाएंगे. दांपत्य जीवन सुखी रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें. अपनी सोच सकारात्मक रखें, तनाव से बचेंगे. कार्यस्थल पर कुछ बदलाव होगा. सप्ताह के मध्य में भाग्य साथ देगा और धन लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ खुशी के पल गुजारेंगे.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
कठिन परिस्थिति में भी आप कार्य करेंगे. अपनी मेहनत से अधिक धन अर्जित करेंगे. परिवार में ज़िम्मेदारियां बढ़ेंगी. दांपत्य जीवन में तनाव न आने दें. अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार धन खर्च करें. कोई निर्णय लेने से पहले विचार अवश्य कर लें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
जमीन-जायदाद से संबंधित योजना बनाने में परिवार की सलाह ज़रूर लें. किसी भी घटना से विचलित न हों, मेहनत से कार्य करें. आने वाले समय में आपको फायदा होगा. सोचने की क्षमता में विस्तार होगा. नौकरीपेशा और व्यापारी, दोनों के लिए समय अच्छा रहेगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
अपने कार्य में कड़ी मेहनत की आवश्कता है. भाग्य के भरोसे न रहें. नए कार्यक्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे. कुछ नया सीखने को मिलेगा. दांपत्य जीवन सुखी रहेगा. व्यापारी वर्ग को उनके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य को लेकर चिंता दूर होगी.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
आपको कार्य में सुधार का अवसर मिलेगा. कार्य का दबाव बढ़ेगा, चिंतित न हों. अचानक धन मिलने का योग है. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. सामाजिक पहचान बढ़ेगी. व्यापारियों के लिए निवेश का अच्छा समय है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आपकी समस्या सुलझाने में परिवार के लोग मदद करेंगे. कुछ कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन आपको उनमें भी काम करना होगा. छोटी-मोटी रुकावटों को नज़रअंदाज करें. आर्थिक स्थिति सुधरेगी. दांपत्य जीवन में मतभेद हो सकता है. स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा. नए लोगों से संपर्क होगा, जिसका लाभ मिलेगा. पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी. किसी मेहमान का आगमन हो सकता है. खर्च बढ़ेगा. नौकरी में पसंदीदा बदलाव हो सकता है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

सोशल मीडिया विंडो

लाइक इट

राहुल कुमार

जन-रैली में मेधा पाटेकर ने नारा दिया, हिंदू-मुस्लिम-ईसाई...लोगों (महिलाएं और पुरुष) ने जवाब दिया, हम सब हैं भाई-भाई. मेधा ने उसी वक्त भीड़ को टोका, भाई-भाई, हम सब हैं बहन-भाई. और फिर उन्होंने यह नारा कई-कई बार लगवाया. स्त्रियों को महत्व देने की कवायद अच्छे इंसानों से ही शुरू हो सकती है. जो सारे वर्गीय भेदों पर बात करते हुए स्त्री वर्ग का भी ध्यान रखे. आइए, राजनीति में अच्छे इंसानों को उतारने की परंपरा शुरू करें.

आशुतोष कुमार

एक कहता है, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे सारे दुःख दूर कर दूंगा. दूसरा कहता है, मुझे वोट दो, मेरी मम्मी तुम्हारे सारे दुःख दूर कर देंगी. इनमें से आप किसको वोट देंगे?
सोचकर जवाब दीजिएगा. आपके जवाब पर आपका, मेरा और देश का भविष्य निर्भर है.

कार्टून क्लास

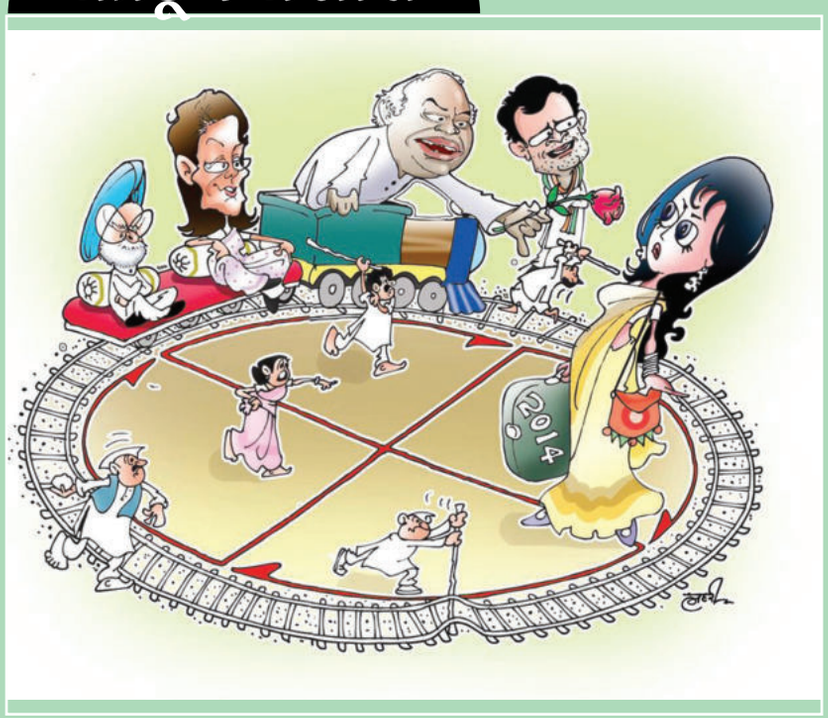

इसमाइल लहरी के फेसबुक वॉल से साभार.

स्वीट-ट्वीट

बाइ द वे. राजीव गांधी इकलौते आदमी नहीं थे, जो उस आतंकी हमले में मारे गए थे, उनके अलावा 14 और लोगों की भी मौत हुई थी.

विक्रम चंद्र

श्री श्री रविशंकर

तेलंगाना बिल अलोकतांत्रिक तरीके से पास किया गया. इसके लिए भाजपा और कांग्रेस ने जो रुख अपनाया, वह दुःखदायी है.

गॉसिप गैलरी

अमेठी में कोई भी पत्रकार गांव में जाकर काम करने के ख़िलाफ़ है. सबको दफ्तर में बैठे-बैठे जानकारी चाहिए होती है फोन पर. शक होता है कि पत्रकारिता में अब कोई धार बची भी है या नहीं. पश्चिम द्वारा जैसे गांव में दो-दो साल तक ट्रांसफार्मर खराब रहता है और स्थानीय पत्रकार सांसद से सवाल तक नहीं पूछते. वैसे जानकारी के लिए बता दें कि अमेठी आदतन आलसी शहर है. सुबह 9 बजे से पहले यहां कोई काम ढंग से शुरू नहीं होता. शाम के 7 बजते-बजते इंसान फिर आराम की मुद्रा में आने लगता है.

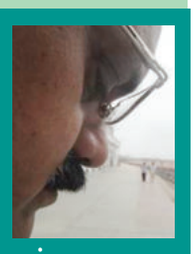

पंकज शुक्ला

पृथक बटोही

समस्या रिलायंस में नहीं, आपके दिमाग में है. इस देश में अगर बड़ी गाड़ी वाला टक्कर मारे, तो दोषी बड़ी गाड़ी वाला होता है. छोटी गाड़ी वाले को मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार दे, तो दोषी छोटी गाड़ी वाला और ऐसे ही मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को टक्कर मारे, तो गलती मोटर साइकिल वाले की. दरअसल, यह एक साइकोलॉजिकल समस्या है.

भारत के लिए बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने अजहर मसूद को पनाह क्यों दी? इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि संसद पर हमले के बाद मसूद पाकिस्तान में छिपा था और वहां की सरकार ने उसे भारत को सौंपने से इंकार कर दिया था. अगर पाक सरकार यह कहती है कि अजहर मसूद को नहीं सौंपा जा सकता, तो भारत सरकार का उसके इस बयान पर क्या रुख है?

आतंकी अजहर मसूद ने उगला ज़हर

भारत पर हमले की धमकी

आतंकवादी अजहर मसूद ने भारत के ख़िलाफ़ जेहाद छेड़ने की धमकी दी है. मसूद की यह धमकी निश्चित रूप से आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ने में भारत सरकार की नाकामी को जाहिर करती है. एक तरफ़ भारत पाकिस्तान से बेहतर संबंधों की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ़ पाकिस्तान की सरपरस्ती में कई दहशतगर्द आतंकी अभियान चला रहे हैं. लिहाजा, यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में आतंकवाद का विस्तार हो रहा है और अजहर मसूद जैसे दहशतगर्दों का मनोबल बढ़ रहा है. आख़िर आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ने में सरकार की कैसी रणनीति होनी चाहिए? इसी मसले पर प्रस्तुत है चौथी दुनिया की यह रिपोर्ट...

राजीव रंजन

आतंक की नर्सरी बन चुके पाकिस्तान में फिर से जैश-ए-मुहम्मद के आतंकी खुलेआम भारत के ख़िलाफ़ आतंकी कारनामों को अंजाम देने के लिए एकजुट हुए हैं. भारत के ख़िलाफ़ हमले को अंजाम देने की साजिश का मुख्य सरगना है अजहर मसूद. आतंकवादियों की इस घोषणा से न सिर्फ़ पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को पनाह देने पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है, बल्कि भारत का पाकिस्तान द्वारा आतंकी गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप भी सही साबित हो रहा है. पिछले दिनों जैश-ए-मुहम्मद के प्रमुख अजहर मसूद ने गुलाम कश्मीर में एक रैली की, जिसमें उसने भारत के ख़िलाफ़ जमकर ज़हर उगला. इस रैली में अजहर ने कहा कि भारत के ख़िलाफ़ जेहाद फिर शुरू करने का वक्त आ गया है. खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक, आतंकी सरगना मसूद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल में एक आतंकी रैली की थी. रैली में मसूद ने दावा किया था कि उसके पास फिदायीन बम्बर की एक पूरी फौज तैयार है, जो उसका इशारा मिलते ही भारत पर हमला करेगी.

भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख एवं दक्षिण एशिया में आतंकवादी संगठनों के विशेषज्ञ ए के डोवाल बताते हैं कि कश्मीर पर कब्जे को लेकर जैश-ए-मोहम्मद भारत के ख़िलाफ़ पागलपन की हद तक दुश्मनी रखता है. मसूद अजहर का अचानक सक्रिय हो उठना वाकई चिंता का विषय है. यह रैली भारत की संसद पर हमले के लिए फांसी पर लटकाए जा चुके अफजल गुरु द्वारा लिखी गई किताब के विमोचन के लिए बुलाई गई थी. पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस रैली को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उसने कहा है कि आख़िर पाक सरकार की आतंकवाद को लेकर कोई नीति है भी या नहीं? इस रैली से आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे मापदंड की कलई खुल जाती है. 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के मास्टर माइंड मसूद अजहर की यह रैली पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में उसी दिन हुई थी, जिस दिन भारत गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था. पाकिस्तान के जाने-माने अख़बार डॉन का कहना है कि प्रतिबंधित संगठन के नेता का वर्षों बाद ऐसी किसी रैली में दिखना सरकार की आतंकवाद के ख़िलाफ़ नीति पर सवाल खड़े करता है. सवाल यह है कि प्रतिबंधित संगठन का नेता कैसे फिर से सक्रिय हो गया? यह सब अचानक तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि यह रैली पूरी तैयारी के साथ आयोजित की गई थी. कहा तो यहां तक जाता है कि रैली में शामिल होने के लिए लोग बसों से ढोकर लाए गए थे. इस रैली में कथित तौर पर अजहर ने कहा कि भारत के ख़िलाफ़ जेहाद फिर शुरू करने का वक्त आ गया है. मुजफ्फराबाद में मसूद के भाषण को फोन पर सुनने के लिए क़रीब 313 फिदायीन जुटे. इसमें अजहर ने अज्ञात जगह से समर्थकों को संबोधित किया. आख़िर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस रैली की ख़बर स्थानीय प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसियों को न रही हो. शंका इस बात की तरफ़ भी है कि पाक सरकार के इशारे पर ही इस रैली को अंजाम दिया गया. भारत में चुनाव का माहौल है और ऐसे में पाक के फिरकापरस्ती तत्व एक बेहतर मौक़ा देख रहे हैं भारत में उपद्रव फैलाने के लिए.

अख़बार डॉन का तर्क है कि पाक सेना और पाकिस्तानी हुक्मरान अक्सर यह कहते हैं कि जेहादी संगठनों पर प्रतिबंध केवल पाकिस्तान में है, पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं. यह तर्क अत्यंत हास्यास्पद है, क्योंकि इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि आख़िर मसूद अजहर अब भी अपने गृह जिले बहावलपुर से क्यों काम कर रहा है? मसूद अजहर के पाकिस्तान में होने को लेकर कई बार सवाल उठता रहा है और हर बार पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जमकर झूठ भी बोला है. मसूद की पाकिस्तान में उपस्थिति को लेकर पाक का कोई अधिकारी कभी यह कहता है कि वह पाकिस्तान में नहीं है, तो दूसरे ही पल पाक का कोई मंत्री कह बैठता है कि वह पाकिस्तान में ही है. ऐसे ही घटनाक्रम में कुछ साल पहले भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर शाहिद मलिक ने कहा था कि जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में नज़रबंद नहीं है और वह कहां है, उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मलिक को उस समय शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अजहर बहावलपुर के अपने घर में नज़रबंद है, लेकिन उसे भारत को नहीं सौंपा जा सकता. सवाल यह उठता है कि आख़िर अजहर को भारत को क्यों नहीं सौंपा जा सकता?

भारत के लिए बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने मसूद अजहर को पनाह क्यों दी? इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि संसद पर हमले के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान में छिपा था और वहां की सरकार ने उसे भारत को सौंपने से इंकार कर दिया था. अगर पाक सरकार यह कहती है कि अजहर मसूद को नहीं सौंपा जा सकता, तो भारत सरकार का उसके इस बयान पर क्या रुख है? आज तक भारत सरकार ने पाक के इस बयान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के धीरे-धीरे हटने के बाद अजहर का यूं उभरना पाकिस्तान की रणनीति में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है. खुफिया सूत्रों का यह भी कहना है कि मसूद का अचानक इस तरह से सामने आना पाकिस्तानी सरकार की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत में चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाकर दुनिया का ध्यान कश्मीर मुद्दे की ओर खींचना है. कुछ प्रमुख अख़बारों का कहना है कि यह सब कुछ नवाज शरीफ की रणनीति के तहत किया जा रहा है, जिसमें भारत के ख़िलाफ़ अपरोक्ष हमले तेज करने के लिए आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

हाल में पेंटागन से रिटायर जनरल जैक कीन और रक्षा विशेषज्ञ ने अमेरिकी कांग्रेस से कहा है कि पाकिस्तान शुरू से ही भारत में आतंकवादी संगठनों के माध्यम से आतंकी कार्रवाई का समर्थक रहा है और नवाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद भी उसका यह समर्थन जारी है. यह बात दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सेना और उसका हित सबसे ऊपर है और सरकार न केवल कमजोर, बल्कि भ्रष्ट भी है. ऐसी सरकार से अधिक उम्मीद नहीं की जानी चाहिए. भारत को चाहिए कि वह अपने स्तर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी कार्रवाइयों का मुंहतोड़ जवाब दे, लेकिन देश की यह उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी, भारत सरकार के रवैये से कम से कम ऐसा ही लगता है. पाकिस्तान में जिस तरह से रोज बम विस्फोट होते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वहां के टैंकों में है. पाकिस्तान के इतिहास को देखा जाए, तो हम पाएंगे कि इस देश में सिर्फ़ गोली-बंदूक की खेती होती है. खैर मामला चाहे जो भी हो, लेकिन मसूद अजहर और अन्य आतंकियों का फिर से सक्रिय होना आतंकवाद पर पाक सरकार की दोहरी नीति की पोल खोलता है.

अजहर के इस मंसूबे से इस बात की शंका लाजिमी है कि वह भारत की चुनावी रैलियों में अंधाधुंध फिदायीन हमलों की साजिश रच रहा है. अजहर के मूवमेंट की निगरानी कर रही खुफिया एजेंसियों ने इस बात की चेतावनी दी है कि मसूद फिर से हवाई जहाज हाईजैक करने जैसी वारदातों को अंजाम दे सकता है. मसूद के इरादों से आने वाले दिनों में भारत में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट से भी इंकार नहीं किया जा सकता. अगर ऐसा है, तो इसकी रोकथाम के लिए भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा, ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों पर रोक लगाई जा सके. मसूद के हमले की धमकी को देखते हुए भारत को चाहिए कि वह अपने खुफिया तंत्र को चाक-चौबंद करे और इस बात के लिए गंभीर क़दम उठाने के लिए तत्पर रहे कि आतंकी किसी अवांछित गतिविधियों को अंजाम न दे पाएं.

अजहर मसूद के दोबारा सिर उठाने की घटना के पीछे काफी हद तक भारत भी ज़िम्मेदार है. जब कंधार हाईजैक कांड हुआ था, तो भारत को किसी भी क़ीमत पर आतंकवादियों को नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन भारत की तो यह नीति रही है कि जब-जब आतंकवादियों ने किसी का अपहरण किया, तो उनकी मांग पर भारत ने सबसे ख़तरनाक आतंकी छोड़ दिए. अजहर मसूद आतंकवादियों की उसी ब्लैकमेलिंग का परिणाम है. दूसरी जो सबसे बड़ी गलती भारत सरकार ने की, वह यह कि आतंकियों को छोड़ने के बाद कभी भी उनकी धरपकड़ के लिए पाकिस्तान सरकार पर उचित दबाव नहीं बना सकी और न ही वैश्विक मंच को इस मसले पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर सकी. भारत सरकार की इस कमजोर नीति को पाकिस्तान सरकार भलीभांति भांप चुकी है और इसीलिए भारत सरकार की मांग को सिरे से खारिज करके कह देती है कि वह अजहर मसूद को भारत के हवाले नहीं करेगी. अगर भारत किसी तरह का दबाव बनाने में कामयाब हो भी जाता है, तो पाकिस्तान का जवाब होता है कि भारत जिस आतंकवादी की बात कर रहा है, वह पाकिस्तान में है ही नहीं. जैसा कि उसने अजहर मसूद के मामले में किया. भारत को चाहिए कि वह आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से आर-पार की नीति अपनाए. अगर भारत ऐसा करता है, तो आने वाले दिन देश के लिए सुखद होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

ख़तरनाक है अजहर मसूद

अजहर मसूद ने फरवरी 2000 में जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की थी. पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में पाकिस्तान में इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन यह कभी ख़त्म नहीं हुआ. मसूद को 1994 में कश्मीर में उस वक्त धर दबोचा गया था, जब वह जाली पुर्तगाली पासपोर्ट पर सीमा पार जाने की कोशिश कर रहा था. इंडियन एयरलाइंस के विमान आईसी- 814 का जब आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था, तो अजहर को उसमें सवार यात्रियों एवं चालक दल के सदस्यों की रिहाई के बदले जम्मू की एक जेल से दिसंबर, 1999 में छोड़ा गया था. इस विमान को आतंकवादी अगवा करके अफगानिस्तान में कंधार लेकर चले गए थे. अजहर ने ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर अक्टूबर 2001 में हुआ हमला प्रायोजित किया था. उसके संगठन ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर 13 दिसंबर, 2001 को भारतीय संसद भवन पर हमले को अंजाम दिया था. मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान स्थित बहावलपुर के मॉडल टाउन इलाके में जैश के मुख्यालय से अपनी जेहादी गतिविधियां चलाता है. जैश का यह मुख्य केंद्र खुलेआम एक बड़े मजहबी मदरसे (उस्मान-ओ-अली) का संचालन करता है, जहां सैकड़ों बच्चों को इस्लाम की चरमपंथी व्याख्या पढ़ाई जाती है. ■

साई

मुंबई में बालाबुवा नामक एक संत थे, जो अपनी भक्ति, भजन एवं आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे. एक समय वह शिरडी आए. जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें चार वर्षों से जानता हूं. बालाबुवा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूं, फिर यह कैसे संभव हो सकता है.

एक बार...

ॐ साई हरि ॐ साई

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा भक्तों के कष्ट हरते हैं और सदा उन पर कृपा बनाए रखते हैं. साई बाबा का सदा प्रेमपूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वह सदैव दूसरों के कल्याणार्थ तत्पर और आत्मलीन रहते थे. उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है. साधनाओं में यह अति श्रेष्ठ एवं सरल साधना है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता. जब तक इंद्रियां बलिष्ठ हैं, क्षण-क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए. हमें सद्गुरु के पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए. वह तो हर इंसान के भाग्यविधाता और प्रेममय प्रभु हैं. जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे, वे भवसागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होंगे. जिस प्रकार हम नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर करना चाहिए. सद्गुरु तो केवल भक्तों के भक्ति-भाव की ओर ही देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं.

बाबा की कृपा

मुंबई में बालाबुवा नामक एक संत थे, जो अपनी भक्ति, भजन एवं आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे. एक समय वह शिरडी आए. जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें चार वर्षों से जानता हूं. बालाबुवा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूं, फिर यह कैसे संभव हो सकता है. गहन चिंतन करने पर उन्हें स्मरण हुआ कि चार वर्ष पूर्व उन्होंने मुंबई में बाबा के चित्र को प्रणाम किया था. उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और वह मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है. मैंने तो केवल उनके चित्र को ही प्रणाम किया था, तो भी यह घटना उन्हें ज्ञात हो गई. इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सदृश है. बाबा के एक भक्त थे अप्पा साहेब. जब वह ठाणे में थे, तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां से उन्हें एक सप्ताह में लौटना संभव न था. उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में एक विचित्र घटना हुई. दोपहर के समय अप्पा साहेब के घर पर एक फकीर आया, जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती-जुलती थी. श्रीमती कुलकर्णी एवं उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी के साई बाबा तो नहीं हैं? इस पर उत्तर मिला कि वह तो साई बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल-क्षेम पूछने यहां आए हैं. फकीर ने दक्षिणा मांगी, तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें एक रुपया भेंट किया, तब फकीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो. इतना कहकर फकीर वहां से चला गया.

उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहेब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं. जब वह कालांतर में शिरडी गए, तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया. उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वह सदैव हाथ पर बांधते थे. अब अप्पा साहेब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी. वह कुशाग्र बुद्धि के थे.

बाबा की अद्भुत लीला

भिवंडी में अप्पा साहेब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वह दौरे पर आगे नहीं जा सके और उसी शाम वह घर लौट आए. घर आने पर उन्हें पत्नी द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ. उन्हें मन में थोड़ी अशांति-सी हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया और पत्नी द्वारा केवल एक रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा नहीं लगा. वह कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता, तो 10 रुपये से कम कभी न देता. इसके बाद वह भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े. उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की, लेकिन उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई. बाबा ने कहा कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए. अप्पा साहेब को शिक्षा मिल गई. वह भोजन के उपरांत जब अपने मित्र चित्रे के साथ घूमने निकले, तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर तेजी से आता हुआ दिखाई पड़ा. अप्पा साहेब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है, जो मेरे घर पर आया था और उसकी आकृति भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है. फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी. अप्पा साहेब ने उसे एक रुपया दे दिया, तब वह और मांगने लगा. अब अप्पा साहेब ने दो रुपये दिए, तब भी उसे संतोष न हुआ. उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपये उधार लेकर दिए, फिर भी वह मांगता ही रहा. तब अप्पा साहेब ने उसे घर चलने को कहा. सब लोग घर पर आए और अप्पा साहेब ने उसे 3 रुपये और दिए अर्थात कुल 9 रुपये. फिर भी वह असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था. तब अप्पा साहेब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपये का नोट है, तो फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपये लौटाकर चला गया. अप्पा साहेब ने 10 रुपये देने को कहा था, इसलिए उनसे 10 रुपये ले लिए गए और बाबा द्वारा 9 रुपये उन्हें वापस मिल गए. बाबा ने लक्ष्मीबाई को भी अंत समय में 9 रुपये ही दिए थे.

उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहेब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं. जब वह कालांतर में शिरडी गए, तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया. उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वह सदैव हाथ पर बांधते थे. अब अप्पा साहेब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी. वह कुशाग्र बुद्धि के थे. उन्हें 40 रुपये मासिक मिलते थे, लेकिन बाबा की उदी एवं चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया था और उन्हें मान एवं यश भी मिला. इन अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी. इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी है, उन्हें स्नान करने के पश्चात उसे मस्तक पर धारण करना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

शवासन यानी मन का आसन

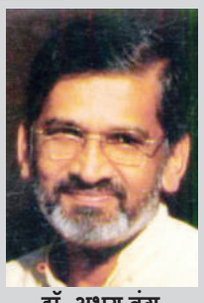

डॉ. अभय बंग

मुझे जिंदा रहना था, इसलिए मैं योग की ओर मुड़ा. आर्निश योगासन और ध्यान करने को कह रहा था. बचपन में सेवाग्राम आश्रम में कुछ योगासन सीखे थे, लेकिन नियमित रूप से कभी किए नहीं थे. योग यानी क्या, यह भी मुझे ठीकठाक ज्ञात नहीं था, लेकिन योगी अपने हृदय की गति नियंत्रित कर सकते हैं, यह सुना था. अतएव योग मार्ग से मैं अपने हृदय को निरोगी कर पाऊंगा, यह आशा थी.

गढ़चिरौली के जंगल में मुझे योग सिखाने वाला कोई नहीं था. अपने पिता जी के सुझाव पर मैंने आदरणीय विमलताई ठकार को पत्र लिखकर पूछा कि योग कहां व कैसे सीखूं? उन्होंने पूना के डॉ. फडणीस व कोल्हापुर के डॉ. धनंजय गुंडे के नाम सुझाए. इन दोनों ने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया. डॉ. भारती आमटे ने नासिक के योग विद्याधाम व मुंगेर के बिहार स्कूल ऑफ योग के पते, पुस्तकें व कुछ कैसेट्स दीं. श्री बी के एस अयंगार की लाइट ऑन योग व लाइट ऑन प्राणायाम नाम की दो किताबें मुझे एक पुस्तक की दुकान में मिल गईं. पुस्तकें व कैसेट लेकर उनमें से स्वत: प्रयोग करके मैं सीखने लगा. गुरु के मार्गदर्शन के बिना योग, प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं. गलतियां होने का ख़तरा होता है, लेकिन मेरी मजबूरी थी. जंगल में रहकर एकलव्य जैसे ही सीखने के लिए मैं विवश था.

अपने शरीर के लिए उपयुक्त ऐसे बीस आसन चुनकर, मैं उन्हें करने लगा. सुबह का चलना, सूर्य-नमस्कार और योगासन के बाद मैं शवासन करने लगा. शव शब्द के कारण इस आसन के विषय में बचपन में मेरे मन में बहुत नापसंदगी पैदा हो गई थी, लेकिन यह थी बचपन की प्रतिक्रिया. अब तो सब उलट-पलट गया था. नए सिरे से सीखना और अनुभव करना आवश्यक था. किसे पता, इसमें ही उत्तर मिल जाए. प्रश्न जीवन-मरण का होने से मैं सब कुछ करके देखने के लिए तैयार ही नहीं, अधीर था. शुरू में बेडरूम में बिस्तर पर लेटकर स्वयं के मन को निर्देश देते हुए शवासन करने लगा. लेकिन रसोई के बर्तनों की खनखनाहट, बच्चों की शैतानियां, रानी की आवाज और बातें कुछ-न-कुछ कानों पर टकराता ही रहता. शवासन एक तरफ़ रह जाता. अत: घर के तलघर में स्थित अपनी अभ्यासिका में जाकर शवासन करने लगा. वहां अच्छा एकांत था. खुद के मन को सूचना देकर शवासन करते हुए कभी नींद भी आने लगती, तो कभी मन भटकने लगता और शवासन की क्रमवार शृंखला टूट जाती. उसका भान होने पर मन चिड़चिड़ाहट से भर जाता. अत: कैसेट लगाकर उसमें से मिलने वाली सूचनाओं के अनुसार शवासन करने लगा. इस तरह से आंख लग जाना या मन का भटकना बंद हो गया. पंद्रह-बीस दिन रोज कैसेट लगाई, फिर कैसेट की आवश्कता नहीं रही. मन में ही कैसेट शुरू हो जाती.

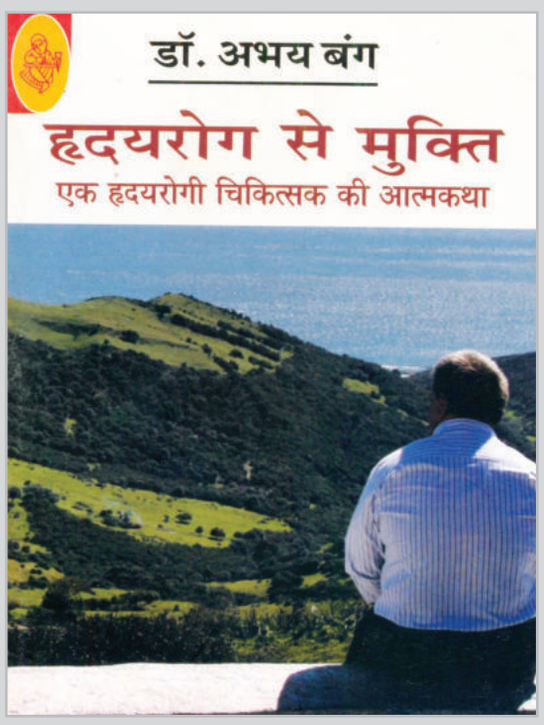

शवासन करते हुए शरीर का एक-एक स्नायु खिंचाव से मुक्त होकर शिथिल होने लगा. कितना ही शिथिल करने पर भी, अभी और शिथिल हो सकता है, ऐसा अनुभव होता. कितना असीम तनाव मैंने अपने अवयवों में इकट्ठा कर रखा है? मेरे मन में प्रश्न उठता. भौहों के बीच सिकुड़न की सिलवटें, आंखों की पलकों में छिपा दबाव, जबड़े के जकड़े स्नायु. इन सबको ढीला करते समय आज तक इस अकारण तनाव की ओर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया, इस पर आश्चर्य होता था.

शवासन करते हुए शरीर का एक-एक स्नायु खिंचाव से मुक्त होकर शिथिल होने लगा. कितना ही शिथिल करने पर भी, अभी और शिथिल हो सकता है, ऐसा अनुभव होता. कितना असीम तनाव मैंने अपने अवयवों में इकट्ठा कर रखा है? मेरे मन में प्रश्न उठता. भौहों के बीच सिकुड़न की सिलवटें, आंखों की पलकों में छिपा दबाव, जबड़े के जकड़े स्नायु. इन सबको ढीला करते समय आज तक इस अकारण तनाव की ओर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया, इस पर आश्चर्य होता था. शिथिल अवस्था में 10-15 मिनट रहने का अनुभव अनुपम आनंद का होता. शरीर को मानों नया जन्म मिलता. सुबह योगासन के बाद आख़िर में शवासन करता था. दोपहर के भोजन के बाद शवासन करके फिर 15 मिनट की लघुनिद्रा लेने से घंटे भर की नींद से ज़्यादा ताजगी महसूस होती है, यह भी समझ में आया. अमेरिका में दोपहर को लंच मीटिंग रखते हैं, ताकि खाते-खाते भी काम कर सकें. इटली और ग्रीस में दोपहर के भोजन के उपरांत बाकायदा सिअेस्टा अवर यानी निद्रा का समय होता है. अमेरिका के लोग मानसिक तनाव के कारण हृदय रोग से मरते हैं, तो विकसित जगत में सबसे कम हृदय रोग का प्रमाण इटली और ग्रीस में है. रात को बिछौने पर लेटने के बाद शवासन द्वारा तनाव रहित होने से नींद तुरंत, शांत और अधिक विश्रामदायी होती है, यह मेरे लिए नई खोज थी. बेहतर कैसे सोया जाए, यह भी मैं सीख सकता हूं. इस प्राथमिक कौशल के बिना ही पिछले 45 वर्षों से मैं सो रहा था? मैंने आश्चर्य किया.

शवासन के अलग-अलग लोगों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न कैसेट इस्तेमाल किए. कइयों ने नई उपयुक्त सूचनाएं एवं युक्तियां जोड़ी हैं. शरीर शिथिल करते समय क्रम से एक-एक अवयव पर ध्यान ले जाकर वहां की संवेदना का अनुभव करना और फिर वह भाग शिथिल करना. इसे कुछ लोगों ने अवयव ध्यान जैसा सुंदर नाम दिया था. सचमुच में प्रत्येक अवयव पर ध्यान ले जाने पर अवयव तो शिथिल होते ही हैं, मन की बेकार दौड़-भाग भी रुक जाती है और मन का उन अवयवों पर मानों ध्यान ही लग जाता है. शवासन शरीर की अपेक्षा मन का आसन ही अधिक है. वह मानों ध्यान का ही एक प्रकार है. ■

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

मूर्तिकार

एक मूर्तिकार अपने पुत्र को मूर्ति बनाने की कला में दक्ष करना चाहता था. उसका पुत्र भी लगन एवं मेहनत से कुछ समय बाद बेहद खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगा. उसकी आकर्षक मूर्तियों से लोग भी प्रभावित होने लगे, लेकिन उसका पिता उसकी बनाई मूर्तियों में कोई न कोई कमी बता देता था. उसने और कठिन अभ्यास से मूर्तियां बनानी जारी रखीं, ताकि अपने पिता की प्रशंसा पा सके. शीघ्र ही उसकी कला में और निखार आया. फिर भी उसके पिता ने किसी भी मूर्ति के बारे में प्रशंसा नहीं की. निराश युवक ने एक दिन अपनी बनाई एक आकर्षक मूर्ति अपने एक कलाकार मित्र द्वारा अपने पिता के पास भिजवाई और अपने पिता की प्रतिक्रिया जानने के लिए स्वयं ओट में छिप गया. पिता ने उस मूर्ति को देखकर कला की भूरि-भूरि प्रशंसा की और बनाने वाले मूर्तिकार को महान कलाकार भी घोषित किया.

पिता के मुंह से प्रशंसा सुनकर छिपा पुत्र बाहर आया और गर्व से बोला, पिताजी, वह मूर्तिकार मैं ही हूं. यह मूर्ति मेरी ही बनाई हुई है. इसमें आपने कोई कमी नहीं निकाली. आख़िर आज आपको मानना ही पड़ा कि मैं एक महान कलाकार हूं. पुत्र की बात पर पिता बोला, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि अभिमान व्यक्ति की प्रगति के सारे दरवाजे बंद कर देता है. आज तक मैंने तुम्हारी प्रशंसा नहीं की. इसी से तुम अपनी कला में निखार लाते रहे. अगर आज यह नाटक तुमने अपनी प्रशंसा के लिए ही रचा है, तो इससे तुम्हारी ही प्रगति में बाधा आएगी और अभिमान के कारण तुम आगे नहीं पढ़ पाओगे. पिता की बातें सुनकर पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पिता से क्षमा मांगकर अपनी कला को और अधिक निखारने का संकल्प लिया. ■

शिक्षा : प्रगति पर अभिमान नहीं करना चाहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के भगमलपुर कसबे के नगरा गांव में पैदा हुए अमरकांत जी का बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता. 17 साल की उम्र में इंटर की पढ़ाई छोड़ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कूदे. फिर किसी तरह बलिया से इंटर करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की. सुविधाजनक जीवन का लेखकीय रास्ता त्याग कर उन्होंने हिंदी के हित के लिए वह रास्ता चुना, जिसमें त्रिलोचन के शब्द उधार लेकर कहूं, तो लेखक की सांसों को आराम नहीं मिलता.

विवाद का बेवजह कोना

अनंत विजय

मशहूर अमेरिकी लेखिका एवं शिकागो विश्वविद्यालय में इतिहास और धर्म में प्रोफेसर वेंडी डोनिगर की किताब-द हिंदूज, एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री को उसके प्रकाशक पेंग्विन बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बाज़ार से वापस लेने और छपी हुई बाकी प्रतियों को नष्ट करने का फ़ैसला लिया है. दरअसल, दिल्ली की एक संस्था को इस किताब के कुछ अंशों पर आपत्ति थी और उस संगठन से जुड़े दीनानाथ बत्रा ने 2011 में इस किताब के कुछ अंशों पर हिंदुओं की भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. किताब के ख़िलाफ़ याचिका दायर होने के तीन साल बाद आउट ऑफ द कोर्ट एक समझौता हुआ, जिसके तहत किताब को वापस लेने का फ़ैसला हुआ. यह मामला सामने आने के बाद कई लोग इस बात पर छाती कूटने लगे कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है. कई लोग इसे हिंदू संगठनों की कथित फासीवादी मानसिकता करार दे रहे हैं. सेक्युलरिज्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों को हिंदू संगठनों पर हमला करने का एक बहाना चाहिए होता है. प्रकाशक के इस फ़ैसले में उन्हें संभावना नज़र आई और वे फासीवाद-फासीवाद चिल्लाने लगे. सवाल यह उठता है कि वर्ष 2009 में किताब छपी, उसके पांच साल बाद इस किताब को वापस लेने का फ़ैसला प्रकाशक ने लिया. इसमें फासीवाद कहां से आ गया? क्या अब इस देश में किसी को भी अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार नहीं है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से कोई विरोध नहीं जताया जा सकता है? क्या अहिंसक तरीके से विरोध करना फासीवाद है?

इस तरह के मामले तो पूरे विश्व में होते रहे हैं. अगर किसी को किसी किताब या उसके किसी अंश पर आपत्ति है, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाता है. इस किताब के ख़िलाफ़ याचिकाकर्ता ने भी भारतीय संविधान के तहत मिले अपने नागरिक अधिकारों का उपयोग करते हुए कोर्ट में केस किया. अदालत में मुकदमा चल ही रहा था कि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया. इसमें फासीवाद और हिंदू संगठनों की मनमानी कहां से आ गए? यह तो किताब के प्रकाशक की कमजोरी है, जो अदालती कार्रवाई के झमेले में नहीं पड़ना चाहता है. विश्व के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक, जिसके पास न तो पैसे की

कमी है और न संसाधनों की, उसने अदालती कार्रवाई के झंझट से मुक्त होने के लिए समझौता किया. वैसे भी इंटरनेट के इस युग में किसी भी कृति पर पाबंदी संभव ही नहीं है. इस मामले में तो अगर लेखक चाहे, तो वह इसे छापने का अधिकार पेंग्विन से लेकर किसी अन्य प्रकाशक को दे सकता है. वह इसे छापने के लिए स्वतंत्र होगा, क्योंकि अदालत ने इस किताब के भारत में प्रकाशन और वितरण पर पाबंदी नहीं लगाई है. इस किताब की लेखिका ने भी इसके बाद ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई. वेंडी डोनिगर के मुताबिक, भारतीय क़ानून इसके लिए ज़िम्मेदार है. अब यह तो हर देश के नागरिक को हक है कि वह अपने देश के क़ानून के मुताबिक काम कर सके, लेकिन छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों की न तो क़ानून में आस्था है और न अदालत में. कई बार यह उचित ही प्रतीत होता है कि प्रगतिशीलता का परचम लहराने वाले बगैर किसी बात के बतंगड़ बनाने में जुट जाते हैं. इस समझौते का विरोध करने वाले कई लोगों ने तो इस किताब को पढ़ा भी नहीं है और बगैर पढ़े ही उसके बारे में अपनी राय बना बैठे हैं.

ये तो बातें हुईं छद्म प्रगतिवादियों की, जो बेवजह का वितंडा खड़ा कर रहे हैं. अब बात की जाए इस किताब और इसकी लेखिका की. भारत के धर्म और उसका धार्मिक इतिहास वेंडी डोनिगर की रुचि के केंद्र में रहे हैं. वह संस्कृत और इंडियन स्टडीज में पीएचडी कर चुकी हैं. संस्कृत में लिखे गए कई मशहूर ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया है. ऋग्वेद, मनुस्मृति और कामसूत्र का अनुवाद वह कर चुकी हैं. इसके अलावा शिवा, द इरोटिक एसेटिक, द ओरिजन ऑफ एविल इन हिंदू मायथोलॉजी जैसी विचारोत्तेजक कृतियां वेंडी डोनिगर ने लिखी हैं. अपनी इस किताब-द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री की भूमिका में लेखिका ने स्वीकार किया है कि इस किताब को लिखने के पीछे उनका एजेंडा तय है. वह यह बताना चाहती है कि जो समूह पारंपरिक रूप से विकास और अन्य सामाजिक स्थितियों के लिए ज़िम्मेदार माने जाते हैं, दरअसल उनकी भूमिका कितनी और कैसी रही है. वेंडी डोनिगर का साफ़ तौर पर मानना है कि दलितों एवं महिलाओं ने हिंदू धर्म के फैलाव और उत्थान में बड़ा योगदान किया है. महिलाओं एवं दलितों के इस योगदान को सदियों से नज़रअंदाज किया जाता रहा है. वेंडी डोनिगर ने अपनी इस किताब में हाशिए के इन लोगों की नज़रों से इतिहास को देखने की कोशिश की है. इस किताब में उन्होंने हिंदू धर्म की अवधारणाओं एवं प्रस्थापनाओं को पश्चिमी मानकों और कसौटी पर कसा है. उनकी इन प्रस्थापनाओं को लेकर विद्वानों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सदियों की विकास यात्रा तय करते हुए हिंदू धर्म बना है और देश की सर्वोच्च अदालत तो अब भी इसे धर्म के बजाय एक जीवन दर्शन मानती है. हिंदुओं का धर्म तो सनातन धर्म है. हिंदुत्व की बात करने पर जो दो चीजें प्रमुखता से सामने आती हैं, वे हैं कर्म और धर्म. ये दोनों अवधारणाएं अलग-अलग कालखंड में हिंदुत्व के केंद्र में रही हैं.

वेंडी डोनिगर के मुताबिक, हिंदू धर्म की खूबसूरती उसकी जीवंतता और विविधता है, जो हर काल में अपने दर्शन पर डिबेट की चुनौती पेश करती है. हमारे धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक, एक आदर्श हिंदू वह है, जो लगातार सवाल खड़े करता है, जवाब को तर्कों की कसौटी पर कसता है और किसी भी चीज, अवधारणा एवं तर्क को अंतिम सत्य नहीं मानता. हिंदू धर्म के इस आधारभूत गुण को आत्मसात करते हुए वेंडी डोनिगर ने कई व्याख्याएं की हैं और कुछ असुविधाजनक सवाल खड़े किए हैं. इस किताब में कई ऐसी बातें हैं, जो संस्कृत में पहले से सुलभ हैं और उन्हें वेंडी डोनिगर ने अंग्रेजी के पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है, जैसे वह अपनी इस किताब में वैदिक काल में प्रचलित बहुदेववादी अवधारणा को एकेश्वरवाद का ही एक रूप मानती हैं. अपनी इस अवधारणा को अपने तर्कों के साथ इस तरह से पेश करती हैं कि वह जैसे कोई नई बात कह रही हों, जबकि संस्कृत में पहले से ही सर्वदेवा नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति कहा गया है.

वेंडी डोनिगर को इस बात की आशंका थी कि इस किताब को लेकर कुछ हिंदुओं को आपत्ति हो सकती है. उन्होंने इस किताब की भूमिका में इसके संकेत भी दिए. वेंडी ने लिखा है, कई हिंदू धार्मिक नेता इस किताब को समुद्र में फेंक देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें इसमें तथ्यों के साथ खिलवाड़ एवं धार्मिक प्रसंगों की गलत व्याख्या आदि दिखाई देंगे. लेखिका इतने पर ही नहीं रुकती हैं, उन्होंने अपनी इस किताब में यह भी लिखा है, हमें हिंदी धर्म में मौजूद ज्ञान और दर्शन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यहां मौजूद साहित्य उच्च कोटि का है और हिंदू धर्म सर्व को समाहित करता चलता है. इन बातों से लेखिका की मंशा और उनकी आशंका का पता चलता है. दिक्कत वहां होती है, जहां-जहां पश्चिमी देशों के विद्वान किसी भी भारतीय मिथकीय प्रसंग की व्याख्या का आधार अपने समाज की रीतियों को बना लेते हैं. दरअसल, भारतीय मिथकीय चरित्रों की व्याख्या के तर्कों का आधार भारतीय समाज में उस वक्त या वर्तमान की मान्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के विवादों से बचा जा सके. वेंडी डोनिगर की किताब एक बेहतरीन शोध का नतीजा है और एक वैकल्पिक इतिहास प्रस्तुत करती है. इस किताब को वापस लेकर पेंग्विन इंडिया ने गलती की है और भारतीय पाठकों के साथ छल भी. इस गलती को तत्काल सुधारे जाने की ज़रूरत है. ■

(लेखक आईबीएन-7 में डिप्टी एडिटर हैं)

anant.ibn@gmail.com

कविताएं

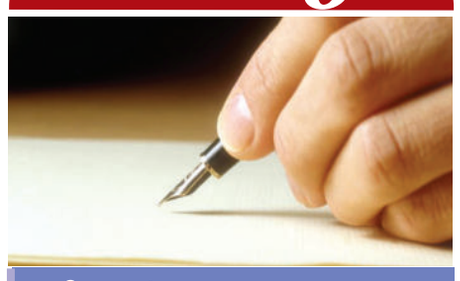

लोकतंत्र का व्याकरण

निखिल आनंद गिरि

बचपन की एक बात समझी
लगभग तीस साल की उम्र में,
एक आदमी चौबीस घंटे में
तीस लोगों की डांट खाता है,
तीन सौ लोगों की डांट से बचता है
तीन हज़ार बार सर-सर कहता है,
सर झुकाकर खच्चर की तरह
तीस हज़ार लोगों के साथ,
रोज़ाना धक्के खाते आता-जाता है
शनीचर को तेल चढ़ाता है,
आप कहते हैं मन से नौकरी करता है
कंपनी का बड़ा वफादार है,
बीवी-बच्चों से सच्चा प्यार है
मैं तब समझा, यह अतिशयोक्ति अलंकार है!
और यह भी कि-
सभ्यताओं के इतिहास में
सिर्फ दुम छोटी होती गई,
दुम हिलाना होता गया
सभ्य होने की पक्की गारंटी.

वह डॉक्टर जो नब्ज़ पकड़ता था
और झट पकड़ लेता बीमारी भी,
एक दिन मरा लाइलाज बीमारी से.
एक बिल्ली रास्ता काटती ही थी
कि कट गई गाड़ी के नीचे आकर.
एक सरकारी अस्पताल खुलना ही था
मर गया महामारी में सारा गांव.
दो रिश्ते एक होने को ही थे
कि सरकारी योजनाओं की तरह,
टूट गए भरम के सारे पुल.
जीवन की काली कोठरी में
जब चीख़ती हैं सवालों की परछाइयां,
और कितना डूबोगे सूरज
अंधेरे के बोझ तले
कितना और..?
उम्मीद की अकेली किरण होती है-
जैसे-तैसे ली गई
एक अंधेरी, बोझिल सांस.
और तब समझ आता है
विडंबना का शाब्दिक अर्थ.
दरअसल, व्याकरण की नहीं लिखी गई किताब में
प्यार लोकतंत्र का ही पर्यायवाची शब्द है
और लोकतंत्र उस अश्लील कहकहे का,
जिसका वज़न दो रुपये की क़ीमत चुकाकर
किसी भी शाम तोला जा सके इंडिया गेट!

feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

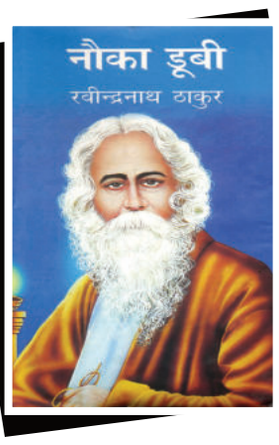

पुस्तक	लेखक
नौका डूबी	रवींद्र नाथ ठाकुर
प्रकाशक	**मूल्य**
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली	450 रुपये

रवींद्र नाथ ठाकुर के उपन्यास नौका डूबी का अनुवाद जयश्री दत्त ने किया है. भारत को आधुनिक समाज बनने के मार्ग पर बढ़ने की शक्ति प्रदान करने वाले रवींद्र नाथ ने उपन्यास नौका डूबी में व्यक्ति की मनोव्याकुलता के रहस्य उद्घाटित किए हैं. इसमें व्यक्ति के अंतर्लोक और समाज की इच्छाओं-आस्थाओं के मध्य होने वाली टकराहट से उत्पन्न त्रासद जीवन दशाओं की अभिव्यक्ति हुई है. कमला, रमेश, हेमनलिनी एवं नलिनाक्ष तेजी से और अकस्मात आकार लेती घटनाओं के जाल में निरंतर उलझते रहते हैं. गोरा की रचना के पूर्व रवींद्र नाथ भारत के समाज का जो रूप देख रहे थे और व्यक्तियों की चिंतन प्रणाली में जिस परिवर्तन की आहट सुन रहे थे, वही इस कृति में है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई-मेल: feedback@chauthiduniya.com

स्मृति

अमरकांत का न रहना

प्रेम शंकर सिंह

हमारे समय के कलम के सिपाही अमरकांत नहीं रहे. नई कहानी आंदोलन के अन्य पुरस्कर्ता अमरकांत को काल का निष्ठुर शिकार हो जाना पड़ा. जब अमरकांत नहीं रहे, तभी पता चला कि उनकी उम्र 90 साल के आसपास पहुंच गई थी. कारण, जब भी उनसे मिलने गया, उनकी आवाज़ की खनक ने कभी उनकी बढ़ती उम्र का एहसास होने ही नहीं दिया. अभी दिसंबर में जन संस्कृति मंच के कथा समूह के आयोजन में शामिल होने आए कहानीकार कैलाश वनवासी के साथ जब अमरकांत जी से मिलने गया था, तो उस समय वह आराम कर रहे थे. हम लोग लौट आए, यह सोचकर कि किसी समय आराम से मिल लेंगे. अफ़सोस! अब वे आराम के क्षण फिर नहीं मिलेंगे. अमरकांत ने हिंदी कथा साहित्य की उस यथार्थवादी एवं प्रगतिशील लेखन की परंपरा को बढ़ाया है, जिसे प्राथमिक संस्कार कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा प्राप्त हुए. घीसू-माधव, होरी-गोबर जैसे सामान्य एवं उपेक्षित जीवन को साहित्य में नायक की पदवी देकर कथाकार प्रेमचंद ने जिस परंपरा का सूत्रपात किया, उसे आगे बढ़ाते हुए ही अमरकांत ने रजुआ जैसा चरित्र हिंदी संसार को दिया, जो स्वाधीनता के बाद बने भारतीय समाज की जोंक व्यवस्था का परिणाम है. अगर यह देखना हो कि स्वाधीनता के बाद भारतीय समाज में गोबर के लिए क्या जगह बनी, तो अमरकांत की कहानी डिप्टी कलक्टरी के बेरोजगार नारायण बाबू और हत्यारे के गुमराह युवकों के जरिए उसे पहचाना जा सकता है और घीसू-माधव को रजुआ जैसे चरित्रों के माध्यम से. अपने एक लेख में आलोचक रविभूषण ने उचित ही इशारा किया है कि ज़िंदगी और जोंक का रजुआ कफन के घीसू-माधव का सगा-संबंधी दिखाई पड़ता है. रजुआ की ज़िंदगी पशु की है. स्वतंत्र भारत का वह पात्र भारत की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह है.

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के भगमलपुर कसबे के नगरा गांव में पैदा हुए अमरकांत जी का बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता. 17 साल की उम्र में इंटर की पढ़ाई छोड़ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कूदे. फिर किसी तरह बलिया से इंटर करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की. सुविधाजनक जीवन का लेखकीय रास्ता त्याग कर उन्होंने हिंदी के हित के लिए वह रास्ता चुना, जिसमें त्रिलोचन के शब्द उधार लेकर कहूं, तो लेखक की सांसों को आराम नहीं मिलता. जीवनयापन के लिए पत्रकारिता का कठिन रास्ता उन्होंने चुना और शुरुआत आगरा से हुई. 1948 से 1954 तक आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में काम किया, जहां उन्हें विश्वनाथ भटेले जैसा अग्रज सहयोगी मिला, जिनसे पत्रकारिता और साहित्य के शुरुआती सरोकार सीखने में सहूलियत हुई.

पढ़ाई के दिनों छूटा इलाहाबाद उन्हें वापस मिला अमृत पत्रिका के रूप में, लेकिन बहुत दिन नौकरी नहीं चल सकी. बेरोज़गारी के इन्हीं दिनों में कुछ दिन लखनऊ भी रहना हुआ. बेरोजगारी में भी उन्हें संभाला रचनात्मकता ने और उन्हीं दिनों उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ तीन कहानियों यथा डिप्टी कलक्टरी, ज़िंदगी और जोंक तथा दोपहर का भोजन की रचना की. फिर भैरव प्रसाद गुप्त संपर्क में आए, उनके साथ कुछ दिनों कहानी पत्रिका में भी काम किया.

अपने पत्रकारीय जीवन की सबसे लंबी पारी उन्होंने माया प्रेस से निकलने वाली पत्रिका मनोरमा में बतौर संपादक खेली. मनोरमा को स्त्रियों की पत्रिका के रूप में खड़ा करने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है. प्रसिद्ध कहानीकार अनीता गोपेश की पहली कहानी मनोरमा में ही छपी. शांती चौधरी, दमयंती रैना, आशा सेठ, मीनूरानी दुबे एवं निर्मला ठाकुर की कहानियां/लेख उन्होंने मनोरमा में छापे. उनके कई स्थाई स्तंभ जैसे सास की कचहरी में बहू, बहू की कचहरी में सास, आपके वो, नर्सरी स्कूलों पर केंद्रित मृगछौनों के उपवन में आदि खासे चर्चित हुए. आपके वो ऐसा स्तंभ था, जिसमें किसी चर्चित व्यक्तित्व की पत्नी द्वारा अपने पति के बारे में लिखा हुआ प्रकाशित किया जाता था. इसमें नरेश मेहता की पत्नी महिमा मेहता और अश्क जी पर उनकी पत्नी द्वारा लिखा गया स्तंभ काफी चर्चित हुआ था. अनीता मनोरमा से जुड़े अपने अनुभव इस तरह बयान करती हैं, वह लेखिकाओं से काम करके आने के लिए सिर्फ़ विषय तय करते थे. कैसे करना है, पूछने पर कहते, खुद सोचो, देखो कैसे कर सकती हो. कम स्तर की चीजें स्वीकार नहीं करते थे, पर इंकार इतने मामूली तरीके से करते थे कि दोबारा उस काम को करने का उत्साह कम न हो. सिर्फ़ यही कहते थे, बात अभी कुछ जंची नहीं.

बहाव जैसी पत्रिका का संपादन वह अभी कर ही रहे थे. इन सबके बावजूद पहले पत्नी की और फिर अपनी लंबी बीमारी के कारण उन्हें आर्थिक मोर्चे पर लगातार संघर्ष करना पड़ा, पर कभी उन्होंने उसे अपने स्वाभिमान और लेखन के आड़े नहीं आने दिया. प्रकाशकों द्वारा लेखकों का शोषण उन्हें नागवार गुजरता था. शायद आने वाले सुखद कल के प्रति उम्मीद के कारण ही उम्र के आख़िरी दौर में भी एक सांस्कृतिक योद्धा की तरह लेखक संगठनों और सांस्कृतिक कर्मियों को सचेत करने का अभिभावकीय दायित्व वह निभाते रहे. आगरा में सैनिक में काम करते-करते वह साहित्य के भी सैनिक बनने की राह पर चल निकले. यहीं वह प्रगतिशील लेखक संघ के संपर्क में आए और कमांडर मिला रामविलास शर्मा जैसा मजबूत योद्धा. रामविलास शर्मा आगरा में रहते थे. अक्सर उनके घर पर साहित्यिक मजमे जुटते थे. गले से सुरीले युवक अमरकांत को प्रलेसं की गोष्ठियों में गीत गुनगुनाने का आदेश होता, किंतु एक बार अमरकांत ने इंकार कर दिया और कहा, मैं गीत नहीं गाऊंगा, बल्कि कहानी पढ़ूंगा. पहली कहानी इंटरव्यू प्रगतिशील लेखक संघ की गोष्ठी में रामविलास जी के कहने पर पढ़ी, जो 1954 में इलाहाबाद से भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में निकलने वाली पत्रिका नई कहानी में छपी. यहां से कहानी लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर दोपहर का भोजन, ज़िंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, पलाश के फूल, गगन बिहारी, मूस, हत्यारे, छिपकली, असमर्थ हिलता हाथ, चक्र, हौसला, लाखो, मुक्ति, धरती के लिए एवं डिप्टी कलक्टरी सहित न जाने कितनी महत्वपूर्ण कहानियों के कुल ग्यारह संग्रह निकले.

अमरकांत का लेखकीय जीवन पारिवारिक समस्याओं और स्वास्थ्य के कारण प्रभावित होता रहा, लेकिन नई कहानी के आंदोलन के दौरान इलाहाबाद में जो तिकड़ी मार्कंडेय, अमरकांत और शेखर जोशी की बनी, वह एक शहर इलाहाबाद में रहते हुए बनी मित्रता और साझे रचनात्मक सरोकारों के कारण. इलाहाबाद में वह अकेले लेखक थे, जो हिंदी-उर्दू के साहित्यकारों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय थे. अमरकांत की पहचान एक कहानी लेखक के बतौर मुख्य रही है, पर उपन्यास भी उन्होंने कम महत्वपूर्ण नहीं लिखे. सुन्नर पांडे की पतोहू, सूखा पत्ता, काले-उजले दिन, कंटीली राह के फूल, इन्हीं हथियारों से जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों तक यह सिलसिला पहुंचा. इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत को 2007 में साहित्य अकादमी और समग्र लेखन के लिए 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया. व्यास सम्मान, पहल सम्मान, जन संस्कृति सम्मान, यशपाल पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार समेत कई सम्मान उन्हें मिले. साहित्य अकादमी ने उन पर एक डाक्यूमेंट्री का भी निर्माण किया है, जिसका निर्देशन संजय जोशी ने किया. सूखा पत्ता और सुन्नर पांडे की पतोहू जैसे प्रारंभिक उपन्यासों को छोड़ भी दें, तो इधर अमरकांत की उपन्यास लेखन की क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण इन्हीं हथियारों से जैसा बड़ा उपन्यास है, जो 1942 से लेकर 1947 तक के कालखंड को घेरता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

आज भी स्कूटर शान की सवारी बनी हुई है. युवाओं में भी स्कूटर पॉपुलर है. यही देखते हुए टू-व्हीलर्स कंपनियों ने अपना फोकस स्कूटर्स पर बढ़ाया है. कंपनियां आने वाले समय में स्कूटर्स के कई बेहतरीन मॉडल उतारने जा रही हैं.

लावा का नया स्मार्ट फोन

भारतीय कंपनी लावा ने आम ग्राहकों के लिए कम दाम में डुअल सिम स्मार्ट फोन लावा आइरिस 408ई पेश किया है. यह सिंगल कोर पावर से लैस है. इसकी क़ीमत मात्र 3 हज़ार 829 रुपये है. इसमें ऐप्स के लिए 2 एमबी स्पेस है, आप चाहें तो एसडी कार्ड लगा सकते हैं. इस फोन की मोटाई 10.3 एमएम है. इसमें 3जी और जीपीएस नहीं है.

खास बातें: एंड्रायड का ऑपरेटिंग सिस्टम 2.3 जिंजर ब्रैड.

- 1 जीएचजेड सिंगल कोर प्रॉसेसर.
- 256 एमबी रैम
- 4 इंच की टीएफटी टच स्क्रीन (रेजोल्यूशन 800 गुणा 489 पिक्सल)
- इंटरनल स्टोरेज 512 एमबी.
- 2 जी, वाई-फाई और ब्लुटूथ.
- 3 मेगापिक्सल का एलईडी फ्लैश कैमरा.
- फ्रंट पर वीजीए कैमरा, इससे वीडियो भी बना सकते हैं.
- 1500 एमएएच की बैटरी. 5 घंटे का टॉक टाइम और 89 दिनों का स्टैंडबाई टाइम.

गेम्स का मजा म्यूजिक के साथ

एंड्रॉयड स्मार्ट फोन को यूएसबी टर्मिनल से जोड़कर जीएक्स बीटी7 के जरिए म्यूजिक एवं ऑनलाइन गेम्स का मजा लिया जा सकता है या फिर मूवी देखी जा सकती है. आईओएस दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है.

आप अब जीएक्स बीटी7 वायरलेस ब्लुटूथ स्पीकर सिस्टम से गेम्स के साथ म्यूजिक का मजा भी ले सकते हैं. यह पर्सनल डिवाइस है. ब्लुटूथ म्यूजिक इसकी खासियत है. यह आईपैड, आईफोन और आईपॉड को भी सपोर्ट करता है. इसमें ब्लुटूथ ऑडियो स्ट्रीमिंग के अलावा विशेष तरीके से एनएफसी टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है. एसेसरीज के रूप में दो एनएफसी फ्री सेटिंग टैग्स दिए गए हैं. इन्हें घर में 10 मीटर के दायरे में कहीं भी फिक्स कर सकते हैं. शार्प जीएक्स बीटी7 एंड्रॉयड के ओपन एसेसरीज प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है. एंड्रॉयड स्मार्ट फोन को यूएसबी टर्मिनल से जोड़कर जीएक्स बीटी7 के जरिए म्यूजिक एवं ऑनलाइन गेम्स का मजा लिया जा सकता है या फिर मूवी देखी जा सकती है. आईओएस दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है. इसमें 64 जीबी का माइक्रो एसडी कार्ड है. ■

बच्चों के लिए किड्स टैब

इसमें 150 लर्निंग बेस्ड गेम्स हैं. इसे स्कूल के करिकुलम से लिंक किया जा सकता है. ऐडी में लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस और क्रिएटिविटी से जुड़े कंटेंट हैं.

बच्चों के लिए मेटिस लर्निंग ने भारत में पहला टैबलेट एडी लॉन्च किया है. यह टैबलेट 2-10 साल तक के बच्चों के लिए है. इस टैबलेट की खास बात यह है कि इसमें इंटरेक्टिव लर्निंग कंटेंट और किड्स-फ्रैंडली हार्डवेयर हैं. शिक्षा में टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर

हुए शोध को मिसाल बनाने के लिए इसमें लर्निंग बेस्ड गेम्स से लेकर फन एप्स जैसे फीचर्स हैं. कंपनी के अनुसार, इसमें 150 लर्निंग बेस्ड गेम्स हैं. इसे स्कूल के करिकुलम से लिंक किया जा सकता है. ऐडी में लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस और क्रिएटिविटी से जुड़े कंटेंट हैं. बच्चे इसमें किताबें और कहानियां पढ़ने के साथ-साथ दुनिया- ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसमें किड्स ऐप रिकमंडेशन इंजन भी है, जिसके जरिए पैरेंट्स बच्चों के लिए एप्लीकेशंस खोज सकते हैं. ■

ऑप्टिकल माउस

जेब्रानिक्स ने अपना नया माउस टोटेम-2 पेश किया है. यह ब्लैक कलर में है. इसमें ब्लू, रेड और ग्रे रंग की धारियां हैं. यह पकड़ने में आरामदायक है और दिखने में आकर्षक. यह आसानी से किसी भी यूजर के हाथ में फिट हो सकता है. यह न तो ज़्यादा छोटा है और न ज़्यादा बड़ा. आजकल आ रहे ऑप्टिकल माउस के मुकाबले लुक्स के मामले में इसे काफी अच्छा कहा जा सकता है. टोटेम-2 में 4 बटन हैं. इसमें एक डॉट्स प्रति इंच का स्विच भी है. यह एक स्टैंडर्ड है, जिसमें कितने पिक्सल प्रति इंच माउस चलता है, इसका लेखा-जोखा रखा जाता है. डीपीआई स्विच के कारण सेटिंग्स बदली जा सकती हैं. ऐसा करने से माउस के प्वाइंटर की स्पीड बदली जा सकती है. यह फोटो एडिटिंग और गेमिंग के दौरान काफी मददगार साबित हो सकता है. जितने ज़्यादा डीपीआई नंबर होंगे, उतनी ही ज़्यादा माउस की सेंसिटिविटी बढ़ेगी. यह वायरलेस माउस 2.4 जीएचजेड की वायरलेस तकनीक पर काम करता है. यह कंप्यूटर से 10 मीटर की दूरी से भी काम कर सकता है. इसमें डीपीआई को 800/1200/1600 तक बदला जा सकता है. यह माउस यूएसबी पोर्ट से भी आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है. यह माउस विंडोज विस्टा, एक्सपी 7 और 8 के साथ काम कर सकता है. इसके साथ कई बैटरी इस्तेमाल की जा सकती हैं. इसका दाम मात्र 425 रुपये है. ■

डीपीआई स्विच के कारण सेटिंग्स बदली जा सकती हैं. ऐसा करने से माउस के प्वाइंटर की स्पीड बदली जा सकती है. यह फोटो एडिटिंग और गेमिंग के दौरान काफी मददगार साबित हो सकता है. जितने ज़्यादा डीपीआई नंबर होंगे, उतनी ही ज़्यादा माउस की सेंसिटिविटी बढ़ेगी.

जेब्रॉनिक्स टॉवर स्पीकर

डुअल माइक समेत मल्टीपल फंक्शनैलिटी इसकी खासियत है. इसमें लो-रेंज केलिए 8 इंच ड्राइवर्स, मिड-रेंज केलिए 4 इंच ड्राइवर्स और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए 1.5 इंच डोम ट्वीटर्स लगे हुए हैं.

जानी-मानी कंपनी जेब्रॉनिक्स ने अपने साउंड मॉन्सटर रेंज का विस्तार करते हुए जेब-टी 7400आरयूसीएफ टावर स्पीकर सिस्टम उतारा है. टॉवर स्पीकर के चारों तरफ़ वुडेन वर्क है. इसमें फ्रंट पैनल, प्यानो ब्लैक और क्रोम ट्रिम जैसे फीचर्स हैं. 60 वॉट्स के स्पीकर्स की डिजाइनिंग ऐसी है, जिन्हें कमरे में कहीं भी रखा जा सकता है. डुअल माइक समेत मल्टीपल फंक्शनैलिटी इसकी खासियत है. इसमें लो-रेंज केलिए 8 इंच ड्राइवर्स, मिड-रेंज केलिए 4 इंच ड्राइवर्स और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए 1.5 इंच डोम ट्वीटर्स लगे हुए हैं. साइड वॉल्यूम कंट्रोल, वूफर्स, एलईडी डिस्प्ले के साथ फ्रंट पोर्ट्स इसमें सुपीरियर क्रोम फिनिश के साथ दिखाई देंगे. इसे स्टैंडर्ड एक्सेस केबल के जरिए फोन या मीडिया प्लेयर जैसी डिजिटल डिवाइस के साथ जोड़ा जा सकता है. मेमोरी कार्ड स्लॉट और यूएसबी पोर्ट होने से आप एसडी/एमएमसी कार्ड या यूएसबी फ्लैश ड्राइव के जरिए डायरेक्ट गाने सुन सकते हैं. बिल्ट इन एफएम रेडियो रिसीवर और फुल-फंक्शन रिमोट कंट्रोल भी इसके फीचर्स में शामिल हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

स्कूटर्स का बढ़ता क्रेज

ग्राहकों में स्कूटर का बढ़ता क्रेज देखकर आटो कंपनियों में स्कूटर लॉन्च करने की होड़ मची हुई है. हाल में होंडा की एक्टिवा की सक्सेस देखकर कंपनियों को स्कूटर्स की सवारी पर दांव लगाने में कोई गुरेज नहीं है. 2009 के दौरान बजाज के स्कूटर बिजनेस से बाहर निकल जाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि सड़कों पर सिर्फ़ बाइक ही दौड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आज भी स्कूटर शान की सवारी बनी हुई है. युवाओं में भी स्कूटर पॉपुलर है. यही देखते हुए टू-व्हीलर्स कंपनियों ने अपना फोकस स्कूटर्स पर बढ़ाया है. कंपनियां आने वाले समय में स्कूटर्स के कई बेहतरीन मॉडल उतारने जा रही हैं. कुछ माडलों पर एक नज़र:-

बजाज ब्लेड

स्कूटर का बढ़ता क्रेज देखते हुए 2009 में स्कूटर बिजनेस से क़दम खींचने के बाद बजाज एक बार फिर इसमें एंट्री मारने का प्लान बना रही है. कंपनी ब्लेड नामक ऑटोमैटिक स्कूटर लाने जा रही है. इसमें 125 सीसी एयरकूल्ड फोर स्ट्रोक इंजन होगा. यह इंजन डिस्कवर में लगा डीटीएस-आई ट्विन स्पार्क जैसा हो सकता है. इसमें किक-इलेक्ट्रिक स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल और 12 इंच एलॉय व्हील जैसे फीचर्स होंगे. इसकी क़ीमत होगी 40,000 रुपये.

टीवीएस रॉक्ज-125

टीवीएस जल्द ही अपना नया 125 सीसी ऑटोमैटिक स्कूटर रॉक्ज लॉन्च करने जा रही है. इसकी क़ीमत रखी गई है 65,000 रुपये. इसकी डिजाइन स्पोर्टी और दूसरों से अलग है. इसे इंडोनेशिया में उतारा जा चुका है. वहां उतारे गए मॉडल में 125 सीसी का इंजन लगा है, जो 9.8 बीएचपी पावर और 9.8 एनएम का टार्क देता है. इसके अन्य फीचर्स में ऑनबोर्ड एमपी3 प्लेयर, स्टोरेज, एफएम रेडियो, इंजन किल स्विच के साथ एंटी थेफ्ट लॉक सिस्टम भी शामिल हैं.

यामाहा यूनिसेक्स

यामाहा रे और रे-जेड की कामयाबी के बाद जल्द ही यूनिसेक्स स्कूटर लॉन्च करने की योजना बना रही है. इस स्कूटर की क़ीमत 45,000 रुपये होगी. कंपनी ने रे को लड़कियों और रे-जेड को लड़कों के लिए लॉन्च किया था. कंपनी ने इस स्कूटर की डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है.

हीरो का जेडआईआर

हीरो ने ऑटो एक्सपो में अपना 1500 सीसी का स्कूटर जेडआईआर लॉन्च किया है. इस स्कूटर को रणबीर कपूर और हीरो के एमडी पवन मुंजाल ने लॉन्च किया. यह दो वैरिएंट में आएगा, एक तो फ्लैट फ्लोर बोर्ड (flat floor लेरीव) मॉडल और दूसरा यूरोपियन स्टाइल स्टेप थ्रु (european style step thru) मॉडल. जेडआईआर स्कूटर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व डीवोएचसी इंजन के साथ आ रहा है, जो 10.5 केडबल्यू और 12.7 एनएम का अधिकतम पावर देता है. इसका इंजन लिक्विड कूल्ड है. जेडआईआर में 9 लीटर की तेल की टंकी है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर 110 किमी प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड तक जा सकता है. इसमें ब्लूटूथ, जीपीएस और नेविगेशन जैसे फीचर्स हैं. हीरो के दूसरे स्कूटर डैश और डेयर की तरह इसमें भी मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है. 2015-16 में इन सभी स्कूटर्स के बाज़ार में आने की संभावना है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

युवराज ने हाथ आए मौके को खाली नहीं जाने दिया. टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाते हुए करियर का शानदार आगाज किया. इसके बाद युवराज ने अपने करियर का सबसे बड़ा धमाका 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए टी-20 विश्वकप में किया.

अंडर-19 से क्लाउड 9 तक

नवीन चौहान

हिंदी में एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं. यह कहावत यूएई में खेले जा रहे आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में एक बार फिर से चरितार्थ होती दिखाई पड़ रही है. भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की तरह कई खिलाड़ी विश्वपटल पर अपनी पहचान बनाते नज़र आ रहे हैं. आज विश्व क्रिकेट में जिन खिलाड़ियों का दबदबा है या कुछ साल पहले तक जिन खिलाड़ियों का डंका बजा उनमें से अधिकांश ने अपनी काबिलियत का लोहा अंडर-19 विश्वकप में बेहतरीन प्रदर्शन करके मनवाया. वर्ष 1988 से सितारों के दुनिया में नज़र में आने का दौर आज भी बदस्तूर जारी है. हालांकि अंडर-19 विश्व कप का आयोजन नियमित तौर पर 1998 से ही हो सका. 1988 के बाद दस साल तक इस तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ नहीं तो ऐसे सितारों की संख्या और भी ज्यादा होती जो अंडर-19 विश्वकप की राह से होकर क्लाउड-9 तक पहुंचे. विश्व क्रिकेट में अपनी चमक बिखेर चुके और बिखेर रहे ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों पर एक नज़र...

navin@chauthiduniya.com

युवराज सिंह

विश्व क्रिकेट में युवराज सिंह नाम के मोहताज नहीं हैं. अपने धमाकेदार खेल के दम पर वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वहां तक पहुंचना हर क्रिकेटर का सपना होता है. युवराज सिंह ने वर्ष 2000 में श्रीलंका में हुए अंडर-19 विश्वकप में धमाकेदार प्रदर्शन किया था और टीम इंडिया को पहली बार अंडर-19 विश्वकप विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी. सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 गेंदों में 58 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. इसके बाद युवराज को केन्या में खेली जाने वाली आईसीसी चैंपियस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई. युवराज ने हाथ आए मौके को खाली नहीं जाने दिया. टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाते हुए करियर का शानदार आगाज किया. इसके बाद युवराज ने अपने करियर का सबसे बड़ा धमाका 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए टी-20 विश्वकप में किया. उन्होंने इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के लगाने का कारनामा कर दिखाया था साथ ही भारत को टी-20 विश्वकप विजेता बनाने में प्रमुख भूमिका अदा की. विश्वकप युवराज की सबसे पसंदीदा प्रतियोगिता है, इसलिए बात यहीं खत्म नहीं हुई. कैंसर से लड़ते हुए युवराज ने वर्ष 2011 में टीम इंडिया को 28 साल बाद एक बार फिर से विश्व क्रिकेट का सिरमौर बना दिया. युवराज को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से उबरने के बाद युवराज ने एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर वापसी की वह अब भी टीम में डटे हुए हैं.

विराट कोहली

टीम इंडिया के वर्तमान उपकप्तान विराट कोहली का नाम युवा पीढ़ी के सबसे होनहार क्रिकेटरों में शामिल है. वह रोज नए कीर्तिमान बना रहे हैं. सचिन और द्रविड़ जैसे क्रिकेटरों की विरासत को आगे ले जा रहे हैं. विराट ने 2008 में मलेशिया में हुए अंडर 19 विश्वकप में बतौर कप्तान भारत को विजेता बनाने में मुख्य भूमिका अदा की थी. विराट ने बतौर बल्लेबाज 6 मैचों में 47 की औसत से 235 रन बनाए थे. इसके बाद विराट को भारतीय टीम में आने का मौका मिलता रहा. उन्हें जो भी मौके मिले उन्होंने उसे खाली नहीं जाने दिया. विराट की मेहनत रंग लाई और 2011 के विश्वकप के लिए उन्हें टीम में जगह मिली बतौर बल्लेबाज विराट ने विश्वकप के पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाकर यह बता दिया था कि वह अब बड़ा हो गया है. सचिन, द्रविड़ और लक्ष्मण के संन्यास लेने के बाद वह भारतीय क्रिकेट की रीढ़ बन गया है. पांच साल के छोटे से करियर में 24 अंतराष्ट्रीय शतक लगाकर विराट ने यह बता दिया है कि वह यहीं रुकने वाला नहीं है. उसके सपने बड़े हैं और वह उन्हें पूरा किए बगैर नहीं थमने वाला है. कुछ समय बाद विराट को टीम इंडिया की कमान सौंपी जाएगी. और वह सितारों के आगे के जहान में पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे.

सनथ जयसूर्या

दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी सनथ जयसूर्या को ऑलराउंडर से ज्यादा एक तूफानी बल्लेबाज के रूप में जानते है. जयसूर्या ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत स्पिन गेंदबाज के रूप में की थी. उन्होंने 1988 में ऑस्ट्रेलिया में हुए यूथ विश्वकप में श्रीलंका के लिए बतौर ऑलराउंडर खेला था. इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय टीम में बतौर गेंदबाज जगह दी गई. लंबे समय तक जयसूर्या गेंदबाजी की कमान संभालते रहे. कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने उनकी बल्लेबाजी की क्षमता को समझा और 1996 के विश्वकप में बतौर ओपनर बल्लेबाज खिलाया. रणतुंगा की रणनीति काम कर गई और श्रीलंका विश्वकप विजेता बना जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका जयसूर्या ने निभाई. इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द सिरीज के पुरस्कार से भी नवाजा गया. इसके बाद जयसूर्या ने कभी मुड़कर नहीं देखा. उनके नाम एक दिवसीय क्रिकेट का सबसे तेज शतक, अर्धशतक और एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड हो गया. जयसूर्या श्रीलंकाई टीम का सबसे बड़ा हथियार बने. जयसूर्या श्रीलंका की ओर से टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे. जयसूर्या का नाम श्रीलंकाई और विश्व क्रिकेट में सबसे ऊंचे पायदान के खिलाड़ियों में है.

इंजमाम उल हक

पाकिस्तान के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में शुमार इंजमाम उल हक के अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज भी 1988 के यूथ विश्व कप में हुआ था. एक दुबले लंबे खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह दिला दी. इंजमाम को 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में हुए क्रिकेट विश्व कप में खेलने वाली पाकिस्तानी टीम में शामिल करवा लिया. इंजमाम ने इमरान के फैसले को ऑकलैंड में खेले गए सेमीफाइनल मैच में लक्ष्य का पीछा करते वक्त शतक लगाकर सही साबित कर दिया. पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और इंजमाम स्टार बन गए. तब से लेकर संन्यास लेने तक इंजमाम पाकिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे. इंजमाम ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में लगभग बीस हजार रन बनाए. वह एकदिवसीय क्रिकेट में दस हजार रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी थे. इंजमाम बतौर कप्तान भी सफल साबित हुए. एक कप्तान बल्लेबाज के रूप में वह औसत के मामले में सिर्फ रिकी पॉन्टिंग और महेंद्र सिंह धोनी से पीछे हैं.

ग्रीम स्मिथ

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ ने सबसे पहले दुनिया के सामने अपनी चमक वर्ष 2000 में श्रीलंका में हुए विश्वकप में दिखाई थी. हालांकि उस विश्वकप में युवराज सिंह अपने हरफनमौला प्रदर्शन की वजह से मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे. स्मिथ उस विश्वकप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे. 2003 में दक्षिण अफ्रीका में हुए विश्वकप में जॉन्टी रोड्स के घायल होने के बाद उन्हें टीम में जगह मिली थी. इसके बाद उन्हें अचानक दक्षिण अफ्रीका का कप्तान घोषित कर दिया गया. उनके कंधों पर दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों का भार आ गया. पिछले 11 सालों मे उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी टीम की कप्तानी करते हुए उसे दुनिया की नंबर एक टीम बनाया. उनकी मेहनत और नेतृत्व के कारण ही दक्षिण अफ्रीका आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में गिनी जाती है.

मुश्ताक अहमद

पाकिस्तान के सर्वकालिक बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों में शुमार मुश्ताक अहमद ने अपने करियर की शुरुआत 1988 में यूथ विश्व कप में की थी. उन्होंने वहां से फिरकी का ऐसी जादू छेड़ा कि हर कोई उनका मुरीद हो गया. बहुत जल्दी उन्हें पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम में जगह मिल गई और उन्होंने 1992 में पाकिस्तान को विश्वविजेता बनाने में भी अहम भूमिका अदा की थी. मुश्ताक अहमद को गुगली फेकने में महारथ हासिल थी, बड़े से बड़ा खिलाड़ी उनकी फिरकी के आगे घुटने टेक देता था.

ब्रायन लारा

दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार ब्रायन लारा ने पहली बार अंतराष्ट्रीय स्तर पर वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व ऑस्ट्रेलिया में हुए यूथ वर्ल्ड कप में किया था. इसके बाद उन्होंने कभी मुड़ कर नहीं देखा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी शुरुआत धमाकेदार नहीं हुई थी. अपने करियर के महज पांचवें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 277 रनों की नाबाद पारी खेल कर यह उन्होंने बता दिया था कि उनकी यह उड़ान अभी थमने वाली नहीं है. वह लंबी रेस के घोड़े हैं. 1994 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में लारा ने एक बार फिर धमाका किया. उन्होंने 375 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल हमवतन सर गैरी सॉबर्स का सालों पुराना सबसे लंबी टेस्ट पारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह रिकॉर्ड लारा के नाम सालों तक रहा. ऑस्ट्रेलियाई प्रारंभिक बल्लेबाज मैथ्यू हेडेन ने उनका यह रिकॉर्ड तोड़ दिया, लारा को यह बात चुभती रही और उन्होंने जल्दी ही टेस्ट क्रिकेट का पहला चौहरा शतक बनाने का कारनामा कर दिखाया और एक बार फिर सबसे लंबी टेस्ट पारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. लारा का नाम आज क्रिकेट की दुनिया में बेहद अदब से लिया जाता है आने वाली पीढ़ियों के लिए लारा हमेशा एक मिसाल बने रहेंगे.

क्रिस गेल

दुनिया के सबसे खौफनाक बल्लेबाजों का नाम लिया जाए तो उनमें सबसे पहला नाम क्रिस गेल का आता है. क्रिस गेल ने वर्ष 2000 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर-19 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे. उन्होंने 72.80 की औसत से कुल 364 रन बनाए थे. हालांकि गेल के अंरराष्ट्रीय करियर की शुरूआत धीमी रही थी. लेकिन समय के साथ गेल ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कोई भी बल्लेबाज उनके करीब नहीं पहुंच सका. उनके क्रिकेट खेलने का अंदाज सबसे अलग है. क्रिकेट का टी-20 संस्करण गेल जैसे बल्लेबाजों के लिए मुंह मांगी मुराद पूरी होने जैसा था. गेल ने टी-20 में ऐसी बल्लेबाजी की कि गेल नाम के तूफान का सामना कोई भी गेंदबाज नहीं करना चाहता. गेल अपने रंग में हों तो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाज की बखिया उधेड़ डालते हैं. गेल अपनी विध्वंशक बल्लेबाजी के बल पर विपक्षी टीम को दिन में तारे दिखा देते हैं. उनके नाम टी-20 मैचों में सबसे ज्यादा शतकों के साथ-साथ एक टी-20 मैच में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड दर्ज है. वह टेस्ट मैचों में तिहरा शतक बनाने का कारनामा भी दो बार कर चुके हैं.

दिल सच्चा और चेहरा झूठा

बॉलीवुड स्टार्स की खूबसूरती की दीवानी सारी दुनिया है, पर इनमें से अधिकतर स्टार्स की खूबसूरती फेक है. इन स्टार्स पर अच्छा दिखने का काफी दबाव होता है. ऐसे में खूबसूरत दिखने के लिए ये कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं.

प्रियंका प्रियम तिवारी

आपका पसंदीदा कलाकार, जिसकी खूबसूरती के आप कायल हैं, वह आम शक्लोसूरत वाला ही है. उसकी खूबसूरती प्राकृतिक नहीं है, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है. जी हां. ऐश्वर्या, करीना, बिपाशा, कटरीना, अनुष्का से लेकर हेमा, शबाना, श्रीदेवी, माधुरी और जूही सबने अपने चेहरे में प्लास्टिक सर्जरी के जरीए कुछ न कुछ बदलाव कराएं हैं. कुछ साल पहले तक हॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी का काफी क्रेज था, लेकिन हाल के दिनों में चीन और भारत जैसे देशों में भी कॉस्मेटिक सर्जरी एक बड़ा बाजार बन कर उभरा है. एलएनजेपी अस्पताल, दिल्ली के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर पीएस भंडारी कहते हैं कि इंडस्ट्री में आपकी प्रतिभा से ज्यादा आपका लुक महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में बॉलीवुड स्टार्स मनचाहा शक्ल-सूरत पाने के लिए सर्जरी का सहारा लेते हैं. किसी भी इंसान की शक्ल-सूरत पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, पर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मनमाफिक शक्लोसूरत काफी हद तक पाई जा सकती है. बॉलीवुड स्टार्स में बॉडी की सर्जरी मैमोप्लास्टी, नोज के लिए राइनोप्लास्टी, लिप्स की सर्जरी और

चीक इंप्लांट का काफी क्रेज है. श्रीदेवी, शिल्पा और प्रियंका चोपड़ा के लिए यह सर्जरी वरदान साबित हुई.

रब दे बना दे जोड़ी फेम अनुष्का भी इन दिनों चर्चा में हैं अपने लिप्स सर्जरी को लेकर. हालांकि, लोगों का कहना है कि इस सर्जरी के बाद उनकी खूबसूरती बढ़ने के बजाए बिगड़ गई है. कई मामलों में सर्जरी के जरिए खूबसूरत फीचर्स पाने की चाह रखने वालों ने अपनी प्राकृतिक खूबसूरती को भी गंवा दी है. अपने जमाने की स्टार अभिनेत्री जूही ने भी अपने नाक को शार्प करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जूही सर्जरी से पहले ज्यादा खूबसूरत दिखती थीं. वहीं मिनिषा, कोएना और प्रीति भी सर्जरी से पहले ज्यादा खूबसूरत दिखती थीं. आइटम डांसर कोएना को तो राइनोप्लास्टी के बाद भयानक दौर से गुजरना पड़ा था. उनकी सर्जरी नाकामयाब रही. उन्हें इनफेक्शन भी हो गया और उनकी नाक की शेप बिगड़ गई. वह काफी डरावनी सी दिखने लगीं. इसके बावजूद भी बॉलीवुड स्टार्स में सर्जरी का क्रेज कुछ कम नहीं हुआ है. हम आपको बता रहे हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही स्टार्स के बारे में, जिन्होंने मनमाफिक चेहरा पाने के लिए सर्जरी का सहारा लिया...

शिल्पा शेट्टी: आज की गॉर्जियस अभिनेत्री शिल्पा पहले इतनी खूबसूरत नहीं थीं. आज उनकी खूबसूरती और फिगर की मिशाल दी जाती है. यह सब सर्जरी का ही कमाल है. उन्होंने कलर ब्लीचिंग से लेकर, बट इंप्लांट, ब्रेस्ट इंप्लांट तक कराया है. नोज के लिए तो उन्होंने दो बार राइनोप्लास्टी कराई है.

काजोल: फिल्मी घराने में पैदा हुई काजोल प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. उनकी खूबसूरती से ज्यादा उनके अभिनय की तारीफ होती है, लेकिन काजोल को भी लगा कि उनके चेहरे में कुछ मिसिंग है. उन्होंने अपने होंठ और नाक की सर्जरी कराई है. इसके अलावा, वह अपने डस्की कलर से भी संतुष्ट नहीं थीं, इसलिए उन्होंने स्कीन ब्लीचिंग कराई है.

करीना-करिश्मा: करिश्मा को करियर के शुरुआती दौर में अगली डकलिंग के नाम से कोट किया जाता था. बाद में वह अपने समय की बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगीं. यह कॉस्मेटिक सर्जरी का ही कमाल था. उन्होंने अमेरिका में फेस और फिगर की सर्जरी कराई और न्यू लुक के साथ जुड़वा और हीरो नंबर वन में दिखीं. उनकी स्टाइलिश और फिगर कॉन्शस बहन करीना ने भी अपने चबी चिक्स को स्लीक करवाने के साथ ही अपने जॉ लाइन की सर्जरी कराई, जिससे अब उनकी जॉ लाइन पहले से ज्यादा शार्प नजर आती है. करीना ने अपने नोज को भी शार्प कराने के लिए राइनोप्लास्टी का सहारा लिया. यही नहीं, सेक्सी बट पाने के लिए उन्होंने सेल्यूलाइट को भी रिमूव करवाया.

कटरीना कैफ: कटरीना की खूबसूरती के सभी कायल हैं, पर वह भी अपने फिचर्स से संतुष्ट नहीं थीं. चेहरे पर उन्होंने कई सर्जरीज और ऑपरेशंस कराए हैं. होंठों के लिए उन्होंने बोटॉक्स ट्रिटमेंट लिया है. नोज की शार्पनेस के लिए राइनोप्लास्टी. चीक्स की थीकनेस के लिए भी उन्होंने सर्जरी कराई है.

बिपाशा बसु: बिपाशा ने भी सेक्सी फिगर पाने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन से लेकर चिक बोन की सर्जरी और सिलिकॉन इंप्लांट भी करवाया है.

रानी मुखर्जी: रानी मुखर्जी ने अपने नोज की सर्जरी कराई है. सर्जरी के बाद उनकी नोज पहले से ज्यादा शार्प और सीधी हो गई है.

ऐश्वर्या राय: करोड़ों दिलों पर राज करने वाली ऐश्वर्या की खूबसूरती भी फेक है. उनकी खूबसूरती कई सर्जरीज से होकर गुजरी है. ऐश ने अपने चिक बोन को इनहेंस कराने के साथ अपने जॉ लाइन की सर्जरी भी कराई है. नोज की सर्जरी के अलावा अपने टीथ लाइन में भी सुधार करवाया है.

प्रीति जिंटा : प्रीति ने क्यूट गर्ल की इमेज से छुटकारा पाने और सेक्सी लुक के लिए लाइपोसक्शन और फेस लिफ्ट कराया है. उन्होंने नोज की सर्जरी, आई ब्रो, एसेट इंप्लांट के अलावा फिलर भी करवाया है. हालांकि लोगों का मानना है कि वह सर्जरी से पहले ज्यादा खूबसूरत दिखती थीं.

प्रियंका चोपड़ा : याद कीजिए 2000 की मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा को और जरा गौर करिए आज की प्रियंका पर. दोनों में कितना फर्क है. आज की कॉन्फिडेंट प्रियंका कभी खूद को खूबसूरत नहीं मानती थीं. आज सेक्सी अभिनेत्रियों में प्रियंका की गिनती होती है. यह सर्जरी का ही कमाल है. प्रियंका ने अपने नाक, होंठ की सर्जरी के अलावा कलर लाइटनिंग ट्रिटमेंट भी लिया है.

कंगना रनावत: कंगना की पहली फिल्म गैंगस्टर में उनके हुस्न को काफी सराहा गया था, लेकिन असलियत में उनकी खूबसूरती आर्टिफिशियल है. उनकी स्किन टोन, शार्प नोज, भरे-भरे होंठ, सब कॉस्मेटिक सर्जरी का कमाल है. इतने सारे सर्जरी के बाद वह कॉस्मेटिक सर्जरी पावर हाउस लगती हैं.

ड्रीम गर्ल हेमा मलिनी: ड्रीम गर्ल ने भी ढलती उम्र में अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए सर्जरी का सहारा लिया. हेमा ने फेस लिफ्ट कराया है. यह सर्जरी का ही कमाल है कि इस उम्र में भी उनके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं है. चेहरा चमकदार और यंग दिखता है.

शबाना आजमी: शबाना ने भी झुर्रियों से निजात पाने के लिए बोटॉक्स का सहारा लिया है. उम्र के इस पड़ाव पर भी वह पहले से ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल दिखती हैं.

श्री देवी: श्री देवी ने जब बॉलीवुड में करियर शुरू किया था, तब उनकी चमकदार आखें, हंसी और खूबसूरती के लोग दीवाने थे. वह खूबसूरत तो थीं हीं, प्रतिभाशाली भी थीं. ऐसे में उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी की क्या जरूरत, पर श्री ने अपने लिप्स को शेप देने के लिए सर्जरी कराई. उन्होंने अपने नोज की राइनोप्लास्टी भी कराई, जिससे उनकी खूबसूरती और बढ़ गई. साथ ही उन्होंने स्कीन ब्लीचिंग भी कराया है.

माधुरी दीक्षित: बढ़ते उम्र के असर को छुपाने के लिए माधुरी ने अपने जॉ लाइन को टाइट कराया है. राइनोप्लास्टी के अलावा चेहरे की रिंकल्स को भी हटवाया है.

सुष्मिता सेन: मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन भी अपनी खूबसूरती से संतुष्ट नहीं थीं. उन्होंने भी सर्जरी का सहारा लिया. वे बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से हैं, जिन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने सर्जरी कराई है. सुष्मिता ने अपने फिगर को बोल्ड शेप देने के लिए इंप्लाट कराया है.

इनके अलावा आयशा टाकिया ने सिलिकॉन इंप्लांट कराया है, मल्लिका शेरावत तो प्लास्टिक सर्जरी प्रोडक्ट ही कही जाती हैं. ईशा देओल ने नोज की सर्जरी के साथ-साथ दातों को सीधा कराया है. उन्होंने आखों के आस-पास की त्वचा की सर्जरी भी कराई है. मिनिषा लांबा ने नोज की सर्जरी कराई है.

स्कीन ब्लीचिंग : बॉलीवुड में स्कीन ब्लीचिंग का भी काफी क्रेज है. सांवली रंगत को दूर करने के लिए अभिनेत्रियों ने स्कीन ब्लीचिंग का सहारा लिया हुआ है. रेखा, श्री देवी, शिल्पा, कंगना, काजोल सभी ने स्कीन ब्लीचिंग के जरिए अपने रंगत को निखारा है.

लुक्स को लेकर कॉन्शस रहने वाले अभिनेता भी भला कहां पीछे रहते. लगभग 60 साल की उम्र में अनिल कपूर, 50 के आस पास के सलमान, आमिर, शाहरुख, सैफ और अक्षय कूल ड्यूड बनकर सिल्वर स्क्रीन पर अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ रोमांस करते नजर आते हैं. कामदेव से दिखने वाले अधिकतर अभिनेताओं का लुक भी फेक है. जी हां अधिकतर अभिनेताओं ने भी प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स का सहारा लेकर अपनी उम्र को मात दिया है. याद करिए सलामान की शुरुआती फिल्म में उनका लुक. उनके सिर पर जवानी के दिनों से ज्यादा बाल तो अब हैं. उन्होंने उजड़े चमन को हेयर ट्रांसप्लांटेशन के जरिए बसा रखा है.

नए स्टार्स भी भला कहां पीछे रहते. रणबीर कपूर के बाल आगे से काफी कम थे. इसे छुपाने के लिए उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है. शाहिद कपूर ने नाक को शार्प बनाने के लिए राइनोप्लास्टी कराई है. आमिर ने उम्र के प्रभाव से बचने के लिए अमेरिका में सर्जरी कराई और बोटॉक्स का सहारा लिया. शाहरुख, सलमान, अनिल ने रिंकल्स को छुपाने के लिए बोटॉक्स का का इस्तेमाल किया है. शेफ ने फेसलिफ्ट कराने के साथ ही रिंकल्स के लिए बोटॉक्स इस्तेमाल भी किया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

KHARA SAUDA
Issey Behtar Aur Nahin
011-64000222 / 333
"SMART AND USEFUL WOMEN & MEN COMBO"

Women's Combo

Handbag Features:
- 2 Main Compartments Inside
- 1 Zip Compartment Outside
- Faux Leather
- Matte Black Smooth Finish
- Twin Grab Handles

Wrist Watch Features:
- Steel Case
- Faux Leather Strap
- SL 65 Moment
- Three Hands (Hour: Minute: Second)
- Stainless steel dial material
- Round Dial Shape
- Function: Analog

Sunglass Features:
- Lens type: Polycarbonate lens
- Frame type: Plastic full frame and plastic arms
- High bridge and fixed nose pads
- Style Note: This trendy sunglasses emit an English vibe combined with a retro inspiration. Made from high quality materials, these sunglasses make sure you stay comfortable and stylish with box packing
- UV Protected

Ladies Clutch Features:
- 2 Compartments
- Dimension: 6 x 8 x 2 cm (LxWxH)
- Faux Leather

MRP- Rs. 2999/-
Special Price Rs. 999/-

Freebie: Na
Warranty: Na

Men's Combo

Wallet Features:
- 100% Genuine Leather
- 2 Main Compartments
- 1 Coin Pocket
- 3 Slots for Credit Card
- 1 Pocket for Driving License/ PAN Card
- Dimensions: 9 x 3.5 inches

Wrist Watch Features:
- Fibre Case
- Black Seude Strap
- SL 65 Moment
- Three Hands (Hour: Minute: Second)
- Alluminium- dial material
- Round- Dial Shape
- Function: Analog

Sunglass Features:
- Lens type: Polycarbonate lens
- Frame type: Gun Metal
- High bridge
- With Box packing
- UV Protected
- 58 Cms

Belt Features:
- 100% Genuine Leather
- Fits Waist size 30 to 38
- Steel Buckle
- Smooth Finish

MRP- Rs. 2999/-
Special Price Rs. 999/-

Freebie: Na
Warranty: Na

Call/SMS : 011-64000222 & 011-64000333
PAY CASH ON HOME Delivery
Offer open till stock lasts
'Products and warranty by 3rd party vendors. Brands. Logos. Creative, trademarks, copyrights are owned by their respective vendors'
*Terms & Condition Apply

चौथी दुनिया

03 फरवरी –09 फरवरी 2014

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार – झारखंड

बिहार में बिजली

क्या है हकीकत, क्या है फसाना!

बात की शुरुआत बिहार में बिजली के गुम हो जाने के खेल से करते हैं. कुछ महीने पहले बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन के पास बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने 2011 का जो टैरिफ पेटिशन सौंपा है, उसके अनुसार 57 प्रतिशत से अधिक बिजली एयर ट्रांसमिशन एंड कॉमर्शियल लॉस हो जाती है. यानि 100 रूपये की बिजली है तो उसमें 57 रुपये बैताल खाते में जाता है. यह लॉस एक रिकॉर्ड की तरह है. देश के सभी राज्यों में यह लॉस होता है लेकिन बिहार में इस लॉस के खेल को समझेंगे तो लगेगा कि यह लॉस जितना होता नहीं, उससे ज्यादा सुनियोजित तरीके से कराया जाता है. बिजली के पेंच को समझने वाले जानकार बताते हैं कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन के मुताबिक यह लॉस 29 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और एक्सेलेरेटेड पावर रिफॉर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानदंड को मानें तो यह लॉस 15 प्रतिशत में सिमटकर रहना चाहिए था. लेकिन फिलहाल बिजली को लेकर भविष्य के तानेबाने बुनने में मगन महकमे में यह सवाल हाशिये पर है.

शशि सागर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सप्ताह में बिजली पर दो बयान दिए. दोनों बयान गौर करने लायक हैं और इन बयानों में आए फर्क पर भी गौर करने की जरूरत है. इसी से बिजली, सियासत और चुनावी राजनीति के रिश्ते का गणित बहुत हद तक साफ हो जाएगा. मुजफ्फरपुर की एक सभा में गत 18 जनवरी को मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगले चार साल में बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी. अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर पावर ग्रीड और पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है. साथ ही यह भी कहा कि अगले साल तक सूबे में चार हजार मेगावाट बिजली खपत करने का लक्ष्य है और मैं इसे लेकर प्रतिबद्ध हूं. इसके दो दिन बाद ही अपनी संकल्प रैली के दौरान गया में उन्होंने कहा कि बिजली की स्थिति नहीं सुधरी तो 2015 में वोट नहीं मांगूंगा. ये दोनों बयान तो हाल के दिनों के हैं. गत 18 नवंबर को मुजफ्फरपुर के कांटी में दिए गए उनके बयान को देखिए. इस दिन उन्होंने कहा था कि 2015 तक मेरा लक्ष्य हर गांव में बिजली पहुंचाना है. ऐसा ही एक अतिउत्साही बयान उन्होंने 15 अगस्त 2012 के दिन गांधी मैदान में दिया था. उस दिन भी उन्होंने कहा था कि मैंने वादा किया है कि बिजली की स्थिति को सुधारेंगे. आज वे इसी बात को दोहराते हैं कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाया तो 2015 में वोट नहीं मांगने जाऊंगा. बिजली पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लगातार बदलते बयान बता रहे हैं कि आनेवाले दिनों में बिहार की सियासत और चुनावी मैदान में बिजली एक बैताल की तरह उनके कंधे पर लटक सकते हैं.

बिहार में बिजली को लेकर नीतीश कुमार के बयान अगर इस तरह बदल रहे हैं या वे बार-बार बिजली को लेकर बयान दे रहे हैं तो इसकी वजह भी है. उन्हें पता है कि बिहार में बिजली एक बड़ी चुनौती है और इससे पार पा लेना उससे भी बड़ी चुनौती. बिहार में बिजली को लेकर बवाल मचता रहा है. इसी जनवरी माह में बिजली के विभिन्न सवालों को लेकर वामदलों ने बिहार बंद किया था. यह बंद वितरण कंपनियों की मनमानी, शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि और उपभोक्ताओं की प्रताड़ना के खिलाफ था. इन्हीं सब सवालों को लेकर आगामी 18 फरवरी से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं लेकिन बिहार के अलग-अलग इलाकों में घूमते हुए बिजली से जुड़े कई तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं. हकीकत से सामना होता है. बिहार में बिजली की दशा सुधारने के लिए भविष्य का जो तानाबाना बुना गया है, वह कुछ सालों बाद यदि हकीकत में बदला तो बिहार की तस्वीर और तकदीर बहुत हद तक बदलेगी लेकिन यह बातें भविष्य की है. बिहार में अतीत के रास्ते अगर वर्तमान पर एक छोटी नजर डालें तो यह खेल पता चलेगा कि यहां बिजली को निगलनेवाले खिलाड़ियों की एक फौज है और इन खिलाड़ियों को विजेता बनाने वाले रेफरी भी मैदान में अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं.

बात की शुरुआत बिहार में बिजली के गुम हो जाने के खेल से करते हैं. कुछ महीने पहले बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन के पास बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने 2011 का जो टैरिफ पेटिशन सौंपा है, उसके अनुसार 57 प्रतिशत से अधिक बिजली एयर ट्रांसमिशन एंड कॉमर्शियल लॉस हो जाती है. यानि 100 रूपये की बिजली है तो उसमें 57 रुपये बैताल खाते में जाता है. यह लॉस एक रिकॉर्ड की तरह है. देश के सभी राज्यों में यह लॉस होता है लेकिन बिहार में इस लॉस के खेल को समझेंगे तो लगेगा कि यह लॉस जितना होता नहीं, उससे ज्यादा सुनियोजित तरीके से कराया जाता है. बिजली के पेंच को समझने वाले जानकार बताते हैं कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन के मुताबिक यह लॉस 29 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और एक्सेलेरेटेड पावर रिफॉर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानदंड को मानें तो यह लॉस 15 प्रतिशत में सिमटकर रहना चाहिए था. लेकिन फिलहाल बिजली को लेकर भविष्य के तानेबाने बुनने में मगन महकमे में यह सवाल हाशिये पर है. वहीं बिजली विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि 18 प्रतिशत तो टेक्निकल लॉस होता है और वो होगा ही लेकिन बिहार में कुल लाइन लॉस 44 प्रतिशत है. इसका मतलब हुआ कि 26 प्रतिशत लॉस तो चोरी में चला जाता है. मतलब ये कि बिजली चोरी का भी मामला बिहार में गंभीर है और कहीं न कहीं यह सुनियोजित भी है. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के प्रवक्ता हरेराम पांडेय ने थोड़े दिन पहले कहा था कि यह 40 प्रतिशत के करीब ही होगा. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कई अधिकारियों से बात होती है लेकिन वे हमें लॉस के कारणों का सही-सही जवाब नहीं दे पाते हैं. नाम नहीं छापने के शर्त पर एक अधिकारी कहते हैं कि लॉस को समझना एक जाल की तरह है. हम इसी समस्या को दूर करने के लिए वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं. वे कहते हैं कि पटना में 400 मेगावाट बिजली की सप्लाई होती है, हमें 90 करोड़ के करीब इससे राजस्व चाहिए लेकिन 60-70 करोड़ से ज्यादा राजस्व का संग्रहण कभी नहीं हो पाता. लॉस के झमेले को समझने के लिए थोड़ा अतीत में झांकने की आवश्यकता है. बात 2008 की है. विद्युत निगरानी कोषांग के महानिदेशक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आनंद शंकर हुआ करते थे. महानिदेशक के निर्देश पर बिजली के बड़े खिलाड़ियों पर छापेमारी शुरू हुई. कई केस दर्ज हुए, जिसमें एक केस 67/2008 भी था जो एक स्टील कंपनी के खिलाफ था. निगरानी कोषांग को पता चला कि बिजली बोर्ड ने कई प्रतिष्ठानों से ऐसी ही चोरी को लेकर टेंपर्ड मीटर जब्त किया था और बिजली चोरी के ठोस साक्ष्य भी मिले थे लेकिन बोर्ड की ओर से बिजली के इन चोरों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया जा सका था. जब दादीजी स्टील पर मामला दर्ज हुआ तो आनन-फानन में बिजली बोर्ड ने भी कईयों पर मामले दर्ज करा दिए लेकिन इतने दिन तक वह चुप्पी क्यों साधे रहा, इसे स्पष्ट नहीं किया जा सका. अलबत्ता यह जरूर हुआ कि तब के बिजली बोर्ड के अध्यक्ष स्वपन मुखर्जी ने एक रास्ता निकाला और यह घोषणा की कि जिन प्रतिष्ठानों या उपभोक्ताओं के मीटर टेंपर्ड हैं, वे स्वैच्छिक घोषणा करें. राज्य में उस समय करीब 28 लाख उपभोक्ता थे लेकिन 52 के करीब बड़े उपभोक्ताओं ने ही यह घोषणा की कि उनका मीटर टेंपर्ड है, बदला जाए. यहीं पर बड़ा खेला हुआ. जिन उपभोक्ताओं के टेंपर्ड मीटर जब्त किए गए थे, उन्होंने भी स्वैच्छिक घोषणा की, बहती गंगा में हाथ धोया और बोर्ड ने भी उन पर मेहरबानी की. जिस स्टील कंपनी के खिलाफ निगरानी कोषांग ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और जिसे तीन साल की सजा की संभावना के साथ 20 करोड़ के करीब जुर्माना भरना होता, उसने भी करीब दो माह बाद स्वैच्छिक घोषणा कर रास्ता निकाल लिया और मात्र एक करोड़ का जुर्माना भर मामले को रफा-दफा करवाने की कोशिश की लेकिन बात बड़ी थी. आनंद शंकर जैसे पुलिस अधिकारी सख्त छवि वाले थे, सो बात ऊपर तक पहुंची. महानिदेशक आनंद शंकर ने कई और बड़ी मछलियों को जाल में फांसना शुरू किया लेकिन तब तक उनका तबादला हो गया और इसके बाद 27 फरवरी 2009 को दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मनोज नाथ को विद्युत निगरानी कोषांग का महानिदेशक बनाया गया. मनोज नाथ ने कमान संभालते ही स्वैच्छिक घोषणा की फाइलों की पड़ताल की और पाया कि बिजली बोर्ड के तब के अध्यक्ष स्वपन मुखर्जी ने स्वैच्छिक घोषणा की आखिरी तिथि पांच जुलाई 2008 की तय सीमा गुजर जाने के बाद भी स्वैच्छिक घोषणा को स्वीकारा है और बड़े खेल के रास्ते खोले हैं. साथ ही यह भी कि बिजली के जिन चोरों को चोरी के दौरान टेंपर्ड मीटर के साथ पकड़ा गया था, उन्हें भी स्वैच्छिक घोषणा का लाभ देकर राज्य के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ चोरों को खुली छुट भी दी गई. मनोज नाथ ने बोर्ड के अध्यक्ष पर केस किया. अध्यक्ष ने स्वीकारा भी कि दादीजी स्टील को स्वैच्छिक घोषणा का लाभ नहीं मिलना चाहिए था लेकिन इसी बीच 'आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास' वाला खेल हुआ. जिस रोज महानिदेशक मनोज नाथ ने केस दर्ज कराया, उसी रोज अध्यक्ष ने भी केस दर्ज करा दिया कि उनसे महानिदेशक मनोज नाथ ने बिजली बोर्ड परिसर में, जहां विद्युत निगरानी कोषांग महानिदेशक का कार्यालय है, सुसज्जित कार्यालय की मांग की और ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया और फिर विद्वेषपूर्ण यह केस भी किया.

इससे मामले का रुख ही बदल गया. बिजली बोर्ड के अध्यक्ष ने बिजली चोरी के सार्वजनिक मामले को निजी दायरे में समेटने की कोशिश की. नतीजा यह हुआ कि पूर्व महानिदेशक आनंद शंकर द्वारा बिजली चोरी का मामला दर्ज करवाने और फिर बाद में महानिदेशक मनोज नाथ द्वारा स्वैच्छिक घोषणा के खेल से संबंधित मामला दर्ज करवाने का मामला अदालत में पहुंचा. पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि भारतीय विद्युत अधिनियम-2003 के तहत पुलिस को ऊर्जा चोरी से किया गया कदाचार दर्ज कराने का अधिकार ही नहीं है.

– शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

एक नज़र

संकल्प यात्रा का स्वागत

आचार्य तुलसी जन्मशताब्दी के अवसर पर पूरे देश में निकली अणुव्रत संकल्प यात्रा पिछले दिनों फॉरबिसगंज पहुंची. यात्रा आचार्य महाश्रमण की शिष्या समणी निर्देशिका ज्योतिप्रज्ञाजी एवं समणी मानसप्रज्ञाजी के नेतृत्व में कोलकाता से पहुंची. इस संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत स्थानीय श्री हरिहरनाथ गोशाला परिसर के समीप जैन धर्मावलंबियों एवं शहर के सभी वर्गों के लोगों द्वारा किया गया. समणी निर्देशिका द्वय के साथ ब्रह्मकुमारी प्रजापिता ईश्वरीय पाठशाला की फॉरबिसगंज इकाई की संचालिका रुक्मा दीदी ने पूरे शहरवासियों को इस शोभायात्रा के जरिए अहिंसा एवं नैतिकता का पालन करने का संदेश दिया. इस संकल्प यात्रा में आचार्य तुलसी एवं जैन धर्म से संबंधित वीडियो एवं ऑडियो से सुसज्जित रथ के जरिए लोगों को जागरूक किया गया. संकल्प यात्रा में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के सुरजमल घोषल, बछराज राखेचा, खेमचंद्र भंसाली, मूलचंद गोलछा, बच्छराज छाजेड़, महेन्द्र बैध, शांतिलाल चिंडालिया, निर्मल मरोठी, दीपक समदरिया, श्याम महेश्वरी, जयप्रकाश अग्रवाल, निवास गोयल, पप्पू डालमिया, विपुल छाजेड़, प्रदीप बैध, अशोक दुग्गड़, छोटू बैध, श्रीमती गुलाबचन्द सेठिया, सुखानी देवी, प्रभा सेठिया, विमला छाजेड़, इर्मिला जैन, प्रो. दिलीप अग्रवाल, बंटी राखेचा, जे.पी. घोड़ावत, जयकुमार अग्रवाल, सुशील अग्रवाल सहित हजारों की संख्या में महिलाएं एवं पुरूष शामिल थे. शोभा यात्रा का संचालन आलोक दुग्गड़ ने किया. समणी द्वय के द्वारा मिथिला पब्लिक स्कूल में बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें जीवन के गूढ़ महत्व को समझाया. विद्यालय के निदेशक विकास मिश्रा एवं विद्यालय के प्राचार्य पुतुल मिश्रा के नेतृत्व में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया. **- अजातशत्रु अग्रवाल/संतोष झा**

प्रतापपुर में मंत्री ने किया डैम का शिलान्यास

झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चतरा जिले का पहली बार दौरा किया. इस दौरान उन्होंने प्रतापपुर प्रखंड में दो करोड़ की लागत से बनने वाले डैम के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. इस दौरान मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आमलोगों से रूबरू हुए. इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं विधायक हूं और हमारी पार्टी गरीबों, अल्पसंख्यकों, किसान और युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है. जनहित को देखते हुए ढुलकी और गोलाई जलाशय का जीर्णोद्धार अवश्य किया जाएगा. यह किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है. मैं किसान की बेटी हूं और हमें जल संसाधन विभाग का प्रभार मिला है. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा नाम अन्नपूर्णा है और मैं लोगों को अन्न अवश्य दूंगी. इस मौके पर हंटरगंज पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष शंभू यादव ने मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा. इस मौके पर मंत्री ने कहा कि एक दैनिक मजदूर से भी कम वेतन एक पारा शिक्षक को मिलता है जो कहीं से उचित नहीं है. मैं पारा शिक्षकों के वेतन वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव बना रही हूं. इस मौके पर आयोजित सभा को चतरा के विधायक जर्नादन पासवान, कृष्णा यादव, चंद्रदेव यादव, प्रो. जैनेन्द्र कुमार सिंह आदि ने संबोधित किया. ■

- अमरेन्द्र प्रताप सिंह

बिहार में बिजली: क्या है हकीकत, क्या है फसाना!

पृष्ठ 17 का शेष

हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, बिजली बोर्ड इसे सिर आंखों पर लेकर लौट गया और तब से बिजली चोरी के मामले में 1992 से बिहार में स्थापित विद्युत निगरानी कोषांग नख-दंतविहीन संस्था बनकर रह गई है. यह सवाल हाईकोर्ट के फैसले पर का नहीं था. जानकार बताते हैं कि न्यायालय को जो सबूत और साक्ष्य उपलब्ध कराए गये थे, उनके आधार पर फैसला सही है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार सरकार के ही नोटिफिकेशन से दो दशक पहले जिस विद्युत निगरानी कोषांग का संचालन शुरू हुआ था और जिसने दो दशकों में कई मामलों में केस किए, कई मामलों को उजागर किया और कई केसों को इसके जरिए एक अंजाम तक पहुंचाया जाना था, उसे अचानक से अधिकारविहीन करने के फैसले को सरकार ने स्वीकार कैसे कर लिया? राज्य सरकार और बिजली बोर्ड ने इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया?

जानकारों से जब इसकी तफ्तीश की गई तो यह जानकारी मिली कि इस फैसले से स्टील कंपनी के 20 करोड़ रुपये के जुर्माने वाला मामला तो ठंडे बस्ते में गया ही, जिन 52 उपभोक्ताओं ने स्वैच्छिक घोषणा का लाभ उठाया था तो उसमें दस ऐसे भी थे, जो आदतन बिजली चोर रहे थे और उनसे मोटा राजस्व वसूला जाना था. दो और बड़े उपभोक्ताओं से भी करीब 160 करोड़ रुपये वसूले जाने थे, जिनपर 2005 में ही मामला दर्ज हुआ था लेकिन अब इस एक फैसले की आड़ में उक्त राजस्व उगाहने की बात कौन करे. जाहिर सी बात है, तब सहज सवाल उठता है कि क्या यह खेल सिर्फ बिजली बोर्ड का है या इसमें एक बड़ा कॉकस ही लगा हुआ है. पुलिस ने इस मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया. मनोज नाथ के बाद आए पुलिस अधिकारी ढोंढियाल ने भी कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और दो बड़े उपभोक्ताओं, जिनसे 160 करोड़ वसूले जाने हैं, के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट जरूर जाना चाहिए. सूत्र बताते हैं कि सरकार की ओर से भी बात आई कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. इस संदर्भ में 21 जुलाई 2011 को ही अभ्यावेदन भेजा गया था और इस आधार पर 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना चाहिए था.

बहरहाल ऊपर की बातें तो लॉस और चोरी की थी. लेकिन बिहार में बिजली और इसके झोल के कई किस्से हैं. सीपीएम नेता अरुण कहते हैं कि बिहार में पर यूनिट खपत देश में सबसे कम है. हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे विकास की रफ्तार क्या है? वे कहते हैं कि निजीकरण किया जा रहा है और ये कंपनियां अपने हिसाब से टैरिफ रेट तय करेंगी और होगा ये कि बहुतेरे लोगों की पहुंच से ही बिजली गायब हो जाएगी. अरुण की बातें सही भी हैं. 1948 के कानून में कहा गया था कि सस्ती, सुलभ व अबाधित ढंग से बिजली मुहैया कराया जाएगी. इसके अपने फायदे थे, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला, हरित क्रांति में योगदान रहा. लेकिन नवउदारवादी नीतियों के बाद से इस क्षेत्र को भी लाभ के लिए खोल दिया गया. केंद्र में 2003 में इसी के अनुरूप कानून बनाया गया और हर राज्य को इसे लागू करने को कहा गया. वैसे ट्रेड यूनियनों के विरोध की वजह से बिहार में निजीकरण का मामला साल दो साल पहले आया. और इसके बाद से नीजिकरण का विरोध जारी है. बिजली को लेकर विरोध का मामला कोई नया नहीं है. 27 साल पहले 1987 में भी भागलपुर में जबरदस्त विरोध हुआ था. वहां बुनकरों की बिजली काट दी गई थी. इस विरोध में एक पुलिस अधिकारी और दो बुनकरों की मौत भी हो गई थी. पिछले साल बुनकरों और बिहार सरकार के बीच समझौता हुआ था कि बुनकरों से पर एचपी 450 रुपये लिए जाएंगे. अब जबकि भागलपुर को निजी हाथों में दे दिया गया है तब ये कंपनियां सरकार और बुनकरों के बीच के करार को मानने को तैयार नहीं है. कंपनी का कहना है कि वो पर एचपी 26 सौ रुपये वसूल करेगी. इस सवाल को लेकर भागलपुर में बुनकर संगठित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में अपने साथ हुई वादाखिलाफी का हिसाब सरकार से चुकता करने के मूड में हैं. अरुण कहते हैं कि बिजली बिहार के साथ साथ पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगी. वह बड़ी समस्या है और यह नवउदारवादी नीतियों का दुष्परिणाम है. यह समस्या निजीकरण से और गहरी होगी और कृषि व छोटे उद्योगों को सबसे अधिक प्रभावित करेगी. फिलहाल बिहार को 1800 मेगावाट बिजली केंद्रिय सेक्टर से मिलती है और 100 मेगावाट का उत्पादन मुजफ्फरपुर के कांटी से होता है. साथ ही 300 मेगावाट ये खरीदती है. सीपीएम नेता अरुण मिश्र कहते हैं कि काम तो हुआ है लेकिन ये जितना दावा कर रहे हैं उतना नहीं हुआ है. वे कहते हैं कि अगले पांच साल में पांच हजार मेगावाट का कंजप्शन आएगा और इनके पास जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसे ठीक दोगुना करना होगा, जो संभव नहीं है. लेकिन बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव मुख्यमंत्री की ही बातों को दोहराते हैं. वे कहते हैं मुख्यमंत्री के किए गए वादे को 2015 तक पूरा कर दिया जाएगा. इस दिशा में पहला कदम बढ़ गया है और साल के अंत तक सभी जिले के मुख्यालय को अबाधित बिजली मिल जाएगी और गांवों को भी दस से बारह घंटे बिजली मिलने लगेगी. बिजेंद्र कहते हैं कि ट्रांसमिशन लॉस पिछले साल जहां 53.9 प्रतिशत था वहीं इस साल यह 42 प्रतिशत हो गया है. वे उम्मीद जताते हैं कि दो बिजली आपूर्ती कंपनियां फिलहाल 2,314 मेगावाट बिजली दे रही है. जून तक यह आंकड़ा तीन हजार मेगावाट का हो जाएगा. बताते चलें कि रीडिंग और बिलिंग का मामला बिहार में फ्रेंचाइजी के हाथों दे दिया गया है. भागलपुर और मुजफ्फरपुर के रीडिंग और बिलिंग को नीजी हाथों में सौंप दिया गया है. 23 और शहरों को फ्रेंचाइजी के हाथों सौंपने की कवायद चल रही है. इसके पीछे सरकाार का तर्क है कि इससे रेवेन्यू लॉस को कम किया जाएगा. नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कंपलशरी मीटर रिडिंग की बात कही है. लेकिन बावजूद इसके साउथ बिहार के लगभग साठ प्रतिशत और नार्थ बिहार के चालीस प्रतिशत उपभोक्ताओं के मीटर की रिडिंग नहीं की जा सकी है. पिदले दिनों यह मामला भी आया कि लगभग दो लाख लोगों को फर्जी बिल दिया गया है. जब से यह निजी हाथों में सौंपा गया है तब से विवादों में ही है. कई गांव ऐसे हैं जहां अभी बिजली के पोल ही लगाए गए हैं लेकिन इनके घरों में बिजली बिल दिया जा रहा है. इस बात को लेकर भी सूबे में विरोध देखने को मिल रहा है. सरकार को रेवेन्यू का घाटा तो सरकारी विभाग भी लगाते हैं. यह बात खुद ऊर्जा मंत्री भी स्वीकारते हैं. वे कहते हैं कि मुंशिपल डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने अब तक अपने बिजली के बकाये को नहीं चुकाया है.

बहरहाल निजीकरण के विरोध की लड़ाई बिजली कर्मियों के 17 संगठन लड़ रहे हैं. 2007 में इन संगठनों का सबसे बड़ा हड़ताल हुई थी और इसी हड़ताल का असर था कि लंबे समय तक सरकार निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी. इसके बाद 2012 में भी इन संगठनों ने हड़ताल की नोटिस दी थी लेकिन अंदरूनी कलह और बिखराव की वजह से इस आंदोलन की हवा निकल गई. इसके बाद ही सरकार ने साहस जुटाया और 1 नवंबर 2012 को बिजली बोर्ड को पांच कंपनियों में बांट दिया. बिजली कामगारों के आपसी बिखराव और एकता के अभाव को सरकार भांप चुकी है. यही वजह है कि उनके आंदोलन के दौरान हुए समझौते अभी तक लागू नहीं किए जा सके हैं. वैसे सवाल फिर से वही है कि क्या इतने खराब और जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 2015 तक बिजली सभी गांवों तक पहुंच जाएगी. बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन के चक्रधर प्रसाद सिंह कहते हैं कि नीतीश अपने किए वादे से हैं इसलिए वे अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं. वे कहते हैं कि वे बिजली को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं और सारा ठीकरा उसके माथे फोड़ देंगे. आने वाले दिनों में बिहार में बिजली इतनी मंहगी हो जाएगी कि गरीब आदमी के लिए उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोकसभा में युवा ही होंगे तारणहार

मनेंद्र कुमार/नंदकिशोर शर्मा

मुल्कराज आनंद | मनोहर कुमार यादव | चन्द्रमुखी देवी | डॉ. विवेकानन्द

लोकसभा चुनाव को लेकर जिले की राजनीति में रोज नए जोड़-घटाव शुरू हो गए है. कई नए दलों का जन्म हो गया है तो कई नए चेहरे टिकट पाने की फिराक में लगे हुए हैं. इन दिनों जिज्ञासा का विषय बना हुआ है कि क्या पार्टियां पुराने दिग्गजों पर ही भरोसा करेंगी या फिर नए चेहरों को भी मौका दे सकती हैं. इसी बीच में पार्टियां खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का आधार सहरसा जिले के सिमरीबख्तियारपुर एवं समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा के मतदाताओं की नब्ज को भी टटोलने में लगी हुई हैं. वहीं कई नई चेहरे अपनी-अपनी पार्टी से टिकट झटकने के प्रयास में हैं.

गौरतलब है कि खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें जिले के अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता हैं. यहां यादवों की अच्छी खासी संख्या है. लेकिन यदि माय समीकरण इस बार कारगर सिद्ध होता है तो राजद की नैया पार हो सकती है. लेकिन यदि किसी पार्टी ने मुस्लिम को प्रत्याशी बना दिया तो तीसरे नए प्रत्याशी का भी उदय हो सकता है. वैसे नदियों का मायका कहा जाने वाले खगड़िया में अति पिछड़े समुदायों के लोगों की भी संख्या प्रभावी है. वहीं उक्त समुदायों के लोगों के बीच किसी भी दल के द्वारा उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण खासी नाराजगी देखी जा रही है. जानकारों का मानना है कि आखिर में इस समुदाय के लोगों का रुझान जिस दल की ओर होगा, उसी की जीत सुनिश्चित है. बीते चुनाव में जदयू के दिनेश चंद्र यादव यहां से सांसद चुने गए. यादव राजग गठबंधन के उम्मीदवार थे लेकिन अलगाव के बाद से यह माना जा रहा है कि अब इस सीट को निकाल पाना जदयू के लिए आसान नहीं है. वजह यह है कि इनदिनों जिला जदयू आंतरिक कलह से जूझ रहा है. सत्ताधारी जदयू के निशाने पर जहां साथ रही भाजपा है, वहीं राजद, कांग्रेस, लोजपा के निशाने पर सूबे की सरकार है. इतना ही नहीं राजनीतिक तीरंदाजी के बीच सभी दल प्रदेश नेतृत्व के फैसले का इंतजार भी कर रहे हैं कि कौन पार्टी किसके साथ मिलकर चुनावी अखाड़े में ताल ठोकेगी. वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी के द्वारा कुशवाहा समुदाय से उम्मीदवार बनाने की चर्चा राजनीतिक गलियारे में की जा रही है.

यदि इस पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ा गया तो कई दलों का समीकरण बिगड़ जाएगा. इस पार्टी के सांस्कृतिक कला मंच के प्रदेश अध्यक्ष मुल्कराज आनंद के नाम की भी चर्चा है. उनके समर्थकों का कहना है कि यदि लोकसभा का उम्मीदवार वे होते हैं तो किसी भी प्रत्याशी के लिये परेशानी खड़ी हो जाएगी. आनंद हाल के वर्षों में क्षेत्र के सरोकार को लेकर काफी संघर्षरत रहे हैं. वहीं जिले के कांग्रेसियों का भी कहना है कि इस बार युवा को ही मौका मिलने जा रहा है. नगर सभापति मनोहर कुमार यादव को यदि कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है तो क्षेत्र में उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए लोकसभा चुनाव काफी संघर्षमय होगा. नगर परिषद के सभापति के रूप में किए गए उनके कार्यों की सराहना आज भी होती है. यह भी माना जाता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में महबूब अली कैसर की वजह से ही राजद के उम्मीदवार की जीत नहीं हो सकी थी. कहा जाता है कि कैसर की अपनी बिरादरी पर अच्छी पकड़ है. फिलहाल तो मनोहर यादव के द्वारा दावेदारी प्रस्तुत करने से बड़े-बड़े धनबली-बाहुबली के होश उड़ने प्रारंभ हो गए हैं.

भाजपा की बात की जाए तो उसके पास उम्मीदवारों की लंबी फेहरिस्त है. नरेंद्र मोदी की लहर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में भी हावी है. नमो की लहर में दमदार उम्मीदवार दिए जाने की चर्चा है. भाजपा किसको टिकट देकर भाग्य चमकाने का मौका देती है यह तो अन्तिम समय में तय होगा. वैसे खगड़िया विधानसभा की पूर्व विधायक चन्द्रमुखी देवी भी अन्दर ही अन्दर टिकट के प्रयास में लगी हुई हैं. वहीं जातीय समीकरण की बात की जाए तो चन्द्रमुखी देवी वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और खगड़िया लोकसभा में वैश्य मतदाता 3 लाख से भी अधिक हैं. यही वजह है कि उनकी दावेदारी अबतक प्रबल मानी जा रही है. वहीं स्वर्ण लोगों का कहना है कि यदि वैश्य समाज से सुयोग्य व कर्मठ उम्मीदवार होता है तो हम लोग भी उन्हीं को मदद करेंगे. खगड़िया जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने वाले तथा शहीद प्रभु नारायण मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पीटल के निदेशक डा.विवेकानन्द ने आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी पेश की है. उन्होंने दावेदारी पेश करते हुए कहा है कि मैंने अपना आवेदन पार्टी मुख्यालय को भेज दिया है जिसमें आवेदन के साथ-साथ आम जनता का हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव संलग्न है. पार्टी के प्रावधान के तहत 14 जनवरी से हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ कर दिया गया है और 15 फरवरी तक करीब एक लाख लोगों का हस्ताक्षर पार्टी मुख्यालय को भेज दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ अपनी सम्पत्ति का भी ब्यौरा भेज दिया है. वहीं आम आदमी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं. कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सभी दलों ने अपने-अपने मजबूत चुनावी खेवनहार के जरिए खगड़िया लोकसभा सीट पर अपना-अपना कब्जा जमाने के लिए एड़ी-चोटी एक कर दिया है. बावजूद इसके सभी दल के जिलास्तरीय नेता अपने-अपने आकाओं के निर्देश पर जिले से पंचायत स्तर पर कमर कसकर तैयारी में जुट गए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

दलित-अल्पसंख्यक छात्रों के हितों की अनदेखी

इन्तेजारुल हक

चम्पारण के बदहाल व जर्जर छात्रावासों के मुद्दे पर प्रशासनिक पदाधिकारी व राज-नेता खामोश क्यों हैं और इसे ठीक करने की चिंता किसी को क्यों नहीं होती? क्या चम्पारण के छात्रों को अब छात्रावास की जरूरत नहीं है या सरकार व विभाग की कोई और मजबूरी है? इस मुद्दे पर इन दिनों लम्बी बहस होने लगी है. साथ ही सरकार व विभागीय अधिकारियों के इस उदासीन रवैये पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

छात्रों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने व उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से चम्पारण के विभिन्न प्रखंडों में वर्षों पूर्व एक दर्जन अनुसूचित जाति के युवकों के लिए छात्रावास और अल्पसंख्यक छात्रावास बनवाए गए थे. आज ये सारे छात्रावास अपनी बदहाली पर रो रहे हैं. इन छात्रावासों को देखकर लगता है कि ये कभी भी अपना वजूद खो सकते हैं. उक्त छात्रावासों के जर्जर भवन व उनकी बदहाली की चिंता न तो सरकार को है और न ही विभागीय अधिकारियों को. ऐसा कहा जाने लगा है कि सुशासन की सरकार अनुसूचित जाति को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है और शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाती है किन्तु उक्त छात्रावासों की बेहतरी के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया है. जानकार बताते हैं कि पूर्वी चम्पारण जिले में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 13 छात्रावास हैं, लेकिन मात्र दो ही चालू हैं. 11 छात्रावासों के भवन करीब दस वर्षों से जर्जर हैं. इस कारण वे बंद है और वहां छात्र नहीं रहते. मोतिहारी नगर के चांदमारी मुहल्ले में स्थित दो छात्रावासों में ही छात्र रहते हैं किन्तु वहां भी संसाधनों का घोर अभाव है और उक्त दोनों छात्रावासों में रह कर अपनी पढ़ाई करने वाले छात्रों को अनेक तरह की समस्याओं से प्रतिदिन जूझना पड़ता है.

पूर्वी चम्पारण के अरेराज में स्थित सोमेश्वरनाथ हाई स्कूल, आदापुर मध्य विद्यालय, रामगढ़वा मध्य विद्यालय, घोड़ासहन में स्थित जेएलएनएस कालेज, मेहसी में स्थित तिरहुत उच्च विद्यालय, ढाका में स्थित उच्च विद्यालय, पकड़ीदयाल के चैता में स्थित जयमंगल हाई स्कूल, पताही में स्थित सिंघेश्वर हाई स्कूल, चिरैया में स्थित महादेव साह हाई स्कूल, चकिया में स्थित एसआरएपी कालेज व जहींरंगा में स्थित विद्यालय में अनुसूचित जाति छात्रावास वर्षों पूर्व बनाए गए थे जो आज सरकार की उपेक्षा के कारण दम तोड़ चुके हैं. इन छात्रावासों में 25-25 छात्रों के रहने की व्यवस्था थी. जानकार बताते हैं कि उक्त छात्रावासों का भवन जर्जर होता चला गया और भवन के ध्वस्त होने के बाद उक्त छात्रावासों के जीर्णोद्धार कराने की दिशा में विभागीय स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. सरकार व विभाग नए छात्रावासों के निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति तो दे रही है और नए-नए छात्रावास बन रहे हैं किन्तु इन बदहाल छात्रावासों की चिंता नहीं कर रही है. स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों द्वारा इसकी शिकायतें समय-

जर्जर छात्रावास

समय पर की जाती रहीं किन्तु नतीजा शून्य रहा. बताते चलें कि पूर्वी चम्पारण के ग्यारह प्रखण्डों में अनुसूचित जाति के लोगों में शिक्षा की अलख जगाने व आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उक्त छात्रावास बनाए गए थे. यही स्थिति जिला मुख्यालय के एनएच 28 पर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास की है. यहां रह कर अपनी पढ़ाई करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को अनेक तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है. यहां भी संसाधनों का घोर अभाव है और अधिकारी सबकुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं. कहने के लिए यहां विशाल भवन तो है किन्तु इसकी देखभाल नहीं हो रही है. इधर राजद के प्रदेश महसचिव डा. शमीम अहमद, जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे, राजद महिला सेल की जिलाध्यक्ष नसीमा खातुन व पूर्व विधान पार्षद रामजी शर्मा आदि लोगों ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया. इनलोगों का कहना है कि एक साजिश के तहत अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक समाज के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी : महिला शिक्षा पर लग रहा ग्रहण

सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा में महिला शिक्षा के विकास को लेकर तकरीबन साढ़े चार दशक पूर्व राम सेवक सिंह महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई. बिहार विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई के रूप में कॉलेज में शिक्षण कार्य शुरू हुआ. स्थापना के समय में जहां कुल 15 विषयों में पढ़ाई को लेकर 26 प्राध्यापकों का पद सृजित किया गया. वहीं वर्तमान में उक्त कॉलेज में प्राचार्य समेत महज आधा दर्जन प्राध्यापक ही रह गए हैं. ऐसे में राज्य सरकार की महिला शिक्षा के प्रति सजगता महज एक छलावा साबित होकर रह गई है...

वाल्मीकि कुमार

सरकारी नौकरी से लेकर राजनीति समेत अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए सूबे की सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है. शिक्षा के प्रति महिलाओं में जागरूकता लाने के लिहाज से सरकार ने मुख्यमंत्री साइकिल व पोशाक समेत अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन कराने में लगी है लेकिन महिलाओं के लिए उक्त योजना महज चंद कदमों की हम सफर ही साबित हो रही है. इसका कारण है कि इंटर से लेकर स्नातक व

छात्रावास में संचालित कार्यालय

उससे ऊपर की शिक्षा भगवान भरोसे ही है. वैसे तो लंबे अरसे से कॉलेजों में प्राध्यापकों की बहाली नहीं किए जाने के कारण अधिकांश पद रिक्त पड़े है लेकिन जो बचे भी हैं, उनका कॉलेज नौकरी से सेवा निवृत्त होने के समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. ऐसे हालात में अन्य कॉलेजों के समान महिला कॉलेज में भी फॉर्म भर कर परीक्षा में शामिल होने एवं प्रमाण पत्र लेने भर से ही मतलब रह गया है. अगर हालात ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में सीतामढ़ी की किसी भी महिला को कहीं भी समुचित शैक्षणिक सम्मान शायद ही मिल पाएगा. राज्य सरकार भले ही वोट की राजनीति की खातिर चाहे जितनी भी आरक्षण व सीट सुरक्षित कर दे, लेकिन इस बात में तनिक भी संकोच नहीं है कि महिला पर लगा अनपढ़ का कलंक उसकी जान नहीं छोड़ेगा. वर्ष 1968 में सीतामढ़ी के डुमरा में स्थापित राम सेवक सिंह महिला कॉलेज इस तथ्य का जीवंत उदाहरण बना है. करीब डेढ़ दशक पूर्व तक छात्राओं की चहल कदमी से गुलजार रहने वाले कॉलेज परिसर में अब अजीब सी वीरानी छायी रहती है. छात्राओं के लिए निर्मित जानकी छात्रावास का कमरा भी अब कॉलेज के कार्यालय संबंधी कार्य में उपयोग किया जाने लगा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज में पढ़ाई के लिए 15 विषयों की स्वीकृति प्रदान की गई थी. इनमें हिंदी में 3, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र व जीवविज्ञान में 2-2, अर्थशास्त्र, तर्क शास्त्र, संस्कृत, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित व वनस्पति विषय में 1-1 प्राध्यापक का पद स्वीकृत किया गया था. इसके अलावा मनोविज्ञान व गृह विज्ञान में भी 4-4 प्राध्यापकों की स्वीकृति मिली थी. लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, संस्कृत, रसायन शास्त्र, गृह विज्ञान व मनोविज्ञान में वर्षों से एक भी प्राध्यापक नहीं है. शेष प्राध्यापकों की संख्या का यह हाल है कि इतिहास, अर्थ शास्त्र, भौतिकी, गणित, जीवविज्ञान व वनस्पति में महज 1-1 प्राध्यापक बच गए हैं. इनमें वनस्पति की प्राचार्य भी शामिल हैं. दूसरी ओर गैर शिक्षण कार्य करने वाले कर्मियों का हाल भी बेहाल है. मजे की बात तो यह है कि कॉलेज में ढाई दर्जन ऐसे कर्मी भी कार्यरत हैं जो पिछले 32 साल से सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद में है. अब तक इन कर्मियों को नियमित भी नहीं किया जा सका है. कुल मिलाकर सीतामढ़ी जिले में महिलाओं के उच्च शिक्षा का एक मात्र केंद्र राम सेवक सिंह महिला कॉलेज का यही हाल है. सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि विभिन्न योजनाओं के तहत कॉलेज परिसर में भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. लेकिन पूर्व से निर्मित भवनों का रंग रोगन व मरम्मत वर्षों से नहीं हो रहा है. जनप्रतिनिधियों की सजगता का आलम है कि निर्माण कार्यों में भागीदारी देकर स्थानीय मीडिया की सुर्खियों में तो आते हैं, लेकिन कॉलेज में शिक्षण कार्य को गति दिलाने को लेकर कोई पहल करने से परहेज करते रहे हैं. नतीजा है कि अब महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र महज एक दिखावा बन कर रह गया है. अन्य कॉलेजों की तरह इस कॉलेज की छात्राओं का नेतृत्व कोई करने वाला संगठन नहीं है. कुछ संगठनों की नींव डालने की कवायद हाल के सालों में की गई थी जो केवल अखबारों की सुर्खियों तक ही सिमटा रहा. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव का समय आने के साथ ही एक बार फिर शहर व गांव की गलियों तक में शिक्षा के सर्वांगीण विकास की घोषणाएं गूंजने लगी हैं. लेकिन वह साइकिल व पोशाक राशि के वितरण से ऊपर भी उठेगा अथवा नहीं. इसका जवाब शायद ही कोई दे सके. फिलहाल जिले में महिलाओं को कॉलेज की पढ़ाई में हो रही परेशानी चर्चा का विषय बनी हुई है. महिला शिक्षा के विकास पर लग रहा ग्रहण छट पाएगा, इसकी संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है. जहां तक जनप्रतिनिधियों की सजगता का सवाल है तो सभी के लिए पार्टी का मिशन 2014 ही सर्वोपरि बना है. जनता की परेशानी उनके मिशन में कहीं भी अपना स्थान नहीं बना पा रही है. वैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी वोट मांगने वालों को शहर से लेकर गांव की गलियों तक कॉलेज की दुर्गति का जवाब मांगने को छात्र-छात्राएं तैयार होने लगे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
YEAR GUARANTY
WINNER OF NATIONAL AWARD
Contact : 9386595926, 9334115955

जाड़े में सावधानी आवश्यक
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
डॉ. सीताराम सिंह
ACOBA CAP/SYP/INJ
Carbo - XT
AREX
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से
प्रश्न : मेरे ससुर जी के आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है और वे ऑपरेशन से बचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में CINERARIA MARITIMA REPL डालना उचित होगा।
Breastriim Oil का सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से सीना का विकास आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आएंगी।
REPL प्लाजा, फेयरल, पटना - 801505
विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें 9304291051
किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें।
REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई
फर्नीचर का संसार
WOODLAND ग्रुप
स्टील फाईवर एवं लकड़ी फर्नीचर का अनोखा संगम
नोट : गिट्टी, बालू, छड़, सिमेंट, नीलकमल ब्राण्डेड फर्नीचर के आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेता
गोशाला रोड, खगड़िया
Ph.: 06244-222522, 9431231703,9431010123
गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर जिलेवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं
निवेदक
डॉ. विद्यानंद दास
अध्यक्ष शिक्षा समिति जिला परिषद
सह सचिव, आर्य कन्या उच्च विद्यालय, खगड़िया

चौथी दुनिया के पाठकों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
रजनीश कुमार (मुन्ना सर्राफ)

समस्त झारखण्ड-बिहारवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
दीपा भारती - प्रमुख, हंटरगंज चतरा
एस. सोरेन
किशोर कुमार
उमेश तिवारी
महादेव उरांव - साक्षियकी पदाधिकारी-हंटरगंज
रेणु देवी - मुखिया, पंचायत, पाण्डेयपुरा खुर्द-हंटरगंज
विनोद कुमार सिन्हा - करमा पंचायत हंटरगंज, चतरा
भोला प्रसाद - (प्रतिनिधि) पूर्व विधायक प्रतापपुर-चतरा
रीना देवी - मुखिया, प्रतापपुर पंचायत, चतरा
मो. जमील अंसारी - मुखिया, मीरपुर पंचायत, हंटरगंज (चतरा)
कालो देवी - मुखिया
सुरेन्द्र राम - चतरा विधानसभा-कांग्रेस प्रत्याशी
विपिन कुमार सिंह - शिक्षक संघ, हंटरगंज-चतरा
शंभु यादव - अध्यक्ष, पारा टीचर संघ हंटरगंज-चतरा
चन्द्रदेव यादव - मुखिया, पंचायत-डाहा-हंटरगंज, चतरा

समस्त झारखण्ड-बिहारवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई
केवल कृष्ण अग्रवाल - बी.डी.ओ. सह सी.ओ. हंटरगंज (चतरा)
अरुण कुमार सिंह - उप प्रमुख हंटरगंज चतरा
डॉ. सत्येन्द्र प्रसाद सिंह - सिविल सर्जन चतरा
सनोज सिंह - समाजसेवी हंटरगंज चतरा
मुकेश कुमार सिन्हा - जिला शिक्षा पदाधिकारी चतरा
इंदू देवी - प्रमुख- प्रतापपुर, प्रखंड-चतरा
ममता देवी - अध्यक्ष जिला परिषद चतरा
देवनन्दन साहु - जिला परिषद उपाध्यक्ष, चतरा
दुर्गा शंकर सिंह - लोकसभा उम्मीदवार, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता
सतीश चन्द्रा - अनुमंडलाधिकारी चतरा
बहाजुल हक - उपाध्यक्ष, नगर पार्षद, चतरा
यमुना साव - अध्यक्ष, नगर पार्षद, चतरा
जहूर आलम - बी.डी.ओ.- प्रतापपुर चतरा
श्यामाकान्त सिंह - वरिष्ठ भाजपा नेता हंटरगंज, चतरा

झाविमो ने चलाया धनसंग्रह अभियान

मंगलानंद मिश्र

झारखंड के ईमानदार नेताओं में से एक पूर्व मुख्यमंत्री व झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी की नेतृत्व वाली झारखंड विकास मोर्चा पार्टी धन की कमी से जूझ रही है. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धन संग्रह के साथ जनमत का भी संग्रह कर रहे हैं. रांची के रातू रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की. इस मौके पर मरांडी ने कहा कि मिशन 2014 में 14 सीटों पर पार्टी को विजयी बनाना है. आम लोगों के सहयोग से पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी. वे भय दिखाकर या कॉरपोरेट घरानों से पैसे लेकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वे जनता के सहयोग से इस मिशन को पूर करना चाहते हैं. श्री मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी काफी मजबूत है और पंचायत स्तर तक उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं. पार्टी में तीन तरह से लोग अपनी भूमिका निभा सकते हैं. एक वो जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, दूसरा पार्टी समर्थक और तीसरे सहयोगी. पार्टी में सभी वर्गों के लोग जुड़े हैं और इतने बड़े समूह के साथ बड़ा लक्ष्य उन्हें हासिल करना है. उन्होंने कहा कि राज्य में जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, आजसू आदि सभी दलों ने शासन किया. जनता ने सबको देखा अब एक बार उनकी पार्टी के शासन को भी देख लें. बाबूलाल मरांडी ने बताया कि राज्य की रेल परियोजना के लिए वे तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से फंड मांगने गए थे, यशवंत सिन्हा ने इसमें आनाकानी दिखाई थी. राज्य में पीजीआइसीएल सहित दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसके दम पर वो कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है. कार्यक्रम में पार्टी महासचिव व लोकसभा प्रभारी राजीव रंजन प्रसाद, लोकसभा प्रभारी अजय नाथ शाहदेव, महानगर अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा, उत्तम यादव, सुनिल बरियार, सुनिल गुप्ता, जीतेंद्र वर्मा, इंदू भूषण गुप्ता, दिलीप गुप्ता, संजय चौधरी, मंतोष सिंह, कमलेश यादव, आशीष गोप, अब्दुल कादिर, संतोष जायसवाल, नदीम इकबाल, कन्हैया महतो, संजय पांडे, मुन्ना आलम, गोविंदा पासवान, राजू वर्मा, आनंद भगत, मुकेश अग्रवाल, मुन्ना सिंह, नंदकिशोर सिंह, आकाश सिंह, नौशाद अंसारी, अमित सिंह, राजू साव, गुक्कू यादव, अंकित साव सहित कई लोग मौजूद थे. इधर, पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी खुद इस अभियान के लिए निकले. रातू रोड में चलाए गए इस अभियान में केवल व्यवसायी संघ ने 11 हजार रुपये, युवा मोर्चा के केंद्रीय सचिव उज्जवल शाहदेव व सिद्धेश्वर सिंह ने 5 हजार, सुबोध प्रसाद, दिनकर शहदेव ने एक-एक हजार व पूर्व डीएसपी व एथलीट बुधवा उरांव ने भी एक हजार रुपये का सहयोग पार्टी को दिया. बाबूलाल मरांडी ने बातचीत में बताया कि वे पिछले दिनों देवघर व दुमका के कार्यक्रम में शामिल होकर आए हैं. देवघर में 100 रिक्शा चालकों ने सहयोग दिया है. कार्यक्रम को बड़ी सफलता मिली है और बढ़ चढ़ कर लोग सहयोग कर रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

03 मार्च-09 मार्च 2014

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

राजनीतिक

चक्रव्यूह में उमा

रेनु शर्मा

भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमाभारती को उत्तराखंड का चुनाव प्रभारी बना कर पार्टी के दिग्गजों ने एक तीर से दो निशाना साधने का काम किया है. महिलाओं को सम्मान दिलाने की दम्भ भरने वाले नरेन्द्र मोदी राज सत्ता की मोह में धृतराष्ट्र की भूमिका में दिखे. उमा भारती की दिली इच्छा थी कि इस आम चुनाव में धर्मनगरी हरिद्धार से सांसद बन कर दिल्ली दरबार में नरेन्द्र मोदी के साथ कदमताल करें. दिल्ली की राजनीति के लिए उमा के उदय से पहले ही इनके विरोधी ग्रहण लगाने में कामयाब हो गये. यह कृत्य पहले उमा की मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री के पद से जिन दिग्गजों ने विदाई कराई थी, उन्हीं की राजनीतिक चक्रव्यूह में एक बार फिर उमा फंस गयीं. यह सब किसके फायदे के लिए किया गया है, यह जानकर राजनीतिक हल्के में लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं. मध्य प्रदेश की राजनीति में विदा होकर उमा को अग्नि-परीक्षा से गुजारते हुए उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड से विधानसभा का चुनाव लड़ कर उत्तर प्रदेश में माननीय बनीं. उमा ने अपनी राजनीतिक कौशल का परिचय पहले ही दे दिया है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मोदी के जनाधार को जन-जन तक पहुंचाने वाली उमा की अब पूरी मंशा थी कि हरिद्धार से वे सांसद बनें, जिसके लिए गंगा सेवा, धारीदेवी के बहाने वर्षों से उमा ने कभी हरिद्धार, कभी केदारनाथ, कभी श्रीनगर में पहुंच कर पार्टी का जनाधार मजबूत किया. हरिद्धार में जनता के साथ संत समाज में अपनी गहरी पकड़ बना कर नम्बर वन बनीं. संत समाज के दबाव के कारण उमा ने एक पखवाड़े पहले हरिद्धार से संसद का चुनाव लड़ने की मंशा प्रकट की थी. इस घोषणा से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को करारा झटका लगा था. उमा का मीडिया में बड़बोलापन इन्हीं को भारी पड़ा. हरिद्धार से राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत सांसद हैं और यह सीट अब रावत की परम्परागत पारिवारीक सीट के रूप में जानी जाती है, जिसे कांग्रेस के दिग्गज किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं. इस सीट पर जमीन से जुड़े नेता मदन कौशिक, उमा भारती चुनाव लड़तीं तो कांग्रेस को नाको चना चबाना पड़ता और इस सीट से कांग्रेस का हारना लगभग तय था. निशंक ने महाकुम्भ 2010 में कुम्भ घोटाले की जो शोहरत कमाई है, इसमें इनके चुनाव लड़ने की स्थिति में कांग्रेस का राह आसान होगा. ऐसा राजनीति के मर्मज्ञ मानते हैं. राजनीति में नेता एक-दूसरे का उपकार जो अपने दल से बाहर हट कर किया करते हैं. इसी के चलते प्रतिउपकार में डमी प्रत्याशी के रूप में निशंक भी सब करने को तैयार है. हरीश ने निशंक को डोईवाला सीट से चुनाव जीताने के लिए ऐन मौके पर डॉ. हरक सिंह रावत की दा-वेदारी को खारिज करा कर रूद्रप्रयाग भेज कर निशंक की राह आसान बानाया था, जो इन दिनों खासा चर्चा में रही. इसी उपकार के चलते हरीश की लाज बचाने के लिए भाजपा के दिग्गज भी अपनी राजनीतिक चाल में बदलाव कर एकाएक यू-टर्न लेकर उमा को ऐन मौके पर छटका कर कांग्रेस का राह आसान कर रहे हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में जनरल खंडूडी की ईमानदार छवि का लाभ भाजपा को दिलाने के लिए केन्द्रिय नेतृत्व ने खंडूडी है जरूरी, का नारा देकर चुनाव मैदान में उतरी थीं. इस नारे को इनके ईमानदारी के चलते जनता ने खूब पसंद किया. दल के गद्दारों को जो भ्रष्ट राजनीति के पोशकों को यह नारा नहीं भाया, जिसका परिणाम रहा कि भीतरघात करके जनरल खंडूडी को ही हरा दिया गया. यह बात वर्तमान में फिर किसी से छिपी नहीं है कि भाजपा के पीएम इन वेटिंग नरेन्द्र मोदी की पहली पसंद जनरल खंडूडी जी हैं. जनरल को मोदी जिस इज्जत की नज़र से देखते हैं और सम्मान देते हैं, वह कई मौके पर प्रकट भी हो चुका है. उमा को चुनाव मैदान से हटा कर इतने छोटे राज्य का प्रभारी बनाना इनके राह में रोड़ा अटकाना कहा जा रहा है. वह भी कांग्रेस के दिग्गज की लाज बचाने के लिए. निशंक को इसके बावजूद भी उम्मीद है कि 'बिल्ली के भाग्य से भी कभी-कभी शिखर टूटती है. ऐसी स्थिति में इनका भाग्योदय होगा. महाकुम्भ 2010 में जो घटिया काम निशंक सरकार ने कराया था, वह स्वयं इनके लिए भ्रष्टाचार की बानगी बना है, जो इनके चुनाव लड़ने की स्थिति में कांग्रेस का राह आसान करेगा. उमा के साथ जिस तरह एक बार फिर छल हुआ है, इससे संत समाज भी आहत है. मोदी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक-एक सीट पर मशक्कत करनी है. इसके पहले ही दिग्गजों का आपसी कलह भाजपा को किधर ले जाएगा, यह कहना कठिन है. भाजपा के दिग्गजों की बढ़ती कलह मोदी की डगर को कठिन बनाने की यह एक बानगी है. ■

मोदी-केजरीवाल का मुकाबला रोचक होगा

अजय कुमार

फागुनी बयार के बीच 02 मार्च, 2014 को उत्तर प्रदेश की सियासत में नई इबारत लिखी जाएगी. एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी झांसी से आगाज की गई 'विजय शंखनाद रैली' को लखनऊ में अंजाम तक पहुंचाएंगें, वहीं दिल्ली की फिजाओं से निकल कर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अपने 'खास' प्रत्याशियों के समर्थन में कानपुर में रैली करके लोकसभा चुनाव के लिये प्रचार का आगाज करेगें. उम्मीद है कि मोदी की लखनऊ रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के किसी जिले (संभवत: वाराणसी) से इनके चुनाव लड़ने की घोषणा हो सकती है. 'आप' ने उत्तर प्रदेश में करीब आधा दर्जन प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. सभी खास विरोधी दलों के नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अजीत सिंह, सलमान खुर्शीद के खिलाफ 'आप' ने प्रत्याशियों की घोषणा करके इन्हें अपने राजनीतिक 'रडार' पर ले लिया है. मोदी के यूपी से चुनाव लड़ने की अगर लखनऊ रैली में घोषणा होती है तो केजरीवाल इनके खिलाफ भी प्रत्याशी उतारने में देर नहीं करेंगे. केजरीवाल मीडिया से अक्सर पूछते ही रहते हैं कि मोदी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं. संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि दो मार्च को लखनऊ में मोदी की रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा कर सकती है. यह वह सीटें होंगी, जहां किसी तरह का कोई विवाद नहीं है.

बहरहाल, मोदी-केजरीवाल अपने संबोधन में क्या बोलेंगे, यह तो बहस का मुद्दा है ही. इसके अलावा राजनीतिक पंडितों की नजर दोनों की रैलियों की तुलना करने पर भी रहेगी. भाजपा नेता तो ताल ठोंक कर कर रहे हैं कि मोदी की रैली में करीब 16 लाख की भीड़ होगी. वहीं आप की कानपुर रैली के संयोजक कहते हैं कि हम कोई दावा नहीं करते हैं. हम आम आदमी हैं, लेकिन यह जरूर जोड़ा कि केजरीवाल की रैली मोदी से उन्नीस नहीं होगी. मुद्दों के हिसाब से भी केजरीवाल भारी पड़ेंगे. केजरीवाल ने जब कानपुर से यूपी में चुनाव प्रचार का श्रीगणेश करने की सोची तो भले ही इनके दिमाग में कुछ नहीं रहा होगा, लेकिन कहा यह जाने लगा कि 'आप' नेता भी टोटके की तरह कानपुर आये हैं. बात 2004 की है. कानपुर में रैली करके कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी. इस समय वह पीएम की दौड़ में दूर-दूर तक नहीं थे, लेकिन समीकरण ऐसे बने कि मनमोहन पीएम की कुर्सी पर पहुंच गये और दस वर्षों तक राज किया. इसके बाद अन्य नेताओं ने भी समय-समय पर कानपुर से ही अपनी चुनावी रैलियों का आगाज किया था. इस संबंध में जब 'आप' के नेताओं से पूछा गया तो इनका कहना था कि कांग्रेस-भाजपा के अपने कारण होंगे, लेकिन हमारा अभियान कानपुर से इसलिए शुरू हो रहा है, क्योंकि यह सरकार को सर्वाधिक टैक्स देने वाला सर्वाधिक बदहाल शहर है. नागरिक सुविधाओं की हालत पतली है. शहर में प्रदूषण चरम पर है. यहां मध्यवर्ग की बड़ी आबादी है. बेरोजगारों, मजदूरों व युवाओं की समस्याओं का अम्बार लगा हुआ है. कोई सुनने वाला नहीं है. यहां के नेताओं के हाथ कोयले की कालिख में रंगे हुए हैं.

2 मार्च को लखनऊ में मोदी की रैली रमाबाई स्थल पर होगी. कानपुर में केजरीवाल की रैली के स्थल की घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी. दिल्ली की सत्ता छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मन बना चुकी है. इसकी 'झाड़ू चलाओ, बेईमान भगाओ' यात्रा हर जिले में चल रही है. केजरीवाल की जनसभा वाले दिन इन यात्राओं को रैली स्थल की तरफ मोड़ दिया जाएगा, ताकि भीड़ का ग्राफ बढ़ाया जा सके. आम आदमी पार्टी की रैली की कानपुर नगर और कानपुर देहात दोनों जिलों में तैयारियां शुरू कर दी गई है. कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ने दो मार्च का दिन खास तौर पर चुना है. अभी तक सामजवादी पार्टी और बीजेपी एक ही दिन पर रैलियां आयोजित करते थे. इससे ऐसा माहौल बनने लगा था, जैसे यूपी में मुख्य चुनावी मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होना है. आप नेता इस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं. जिस दिन मोदी की रैली होगी, उस दिन आम आदमी पार्टी की रैली से अरविंद केजरीवाल और इनकी टीम को स्वत: प्रचार मिल जाएगा. इनकी रैली और बातों की तुलना मोदी से होगी. भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की मुहिम की हवा भी निकालने का प्रयास करेंगे. अरविंद केजरीवाल और आप के अन्य नेता नरेन्द्र मोदी पर अंबानी से चंदा लेकर हेलिकॉप्टर से सफर करने और बड़ी रैलियां करने का आरोप लगाते रहे हैं. हो सकता है कि इस दिन आप नेता भाजपा के पीएम पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी से पूछें कि क्या इनकी सरकार बनी तो रिलायंस ग्रुप के कर्ताधर्ता मुकेश अंबानी की कंपनी को गैस निकालने के लिए मनमोहन सरकार जितनी सहूलियत देंगे. अगर इनकी सरकार भी कॉरपोरेट घरानों के पैसे से बनेगी, तो वह यूपीए से अलग कैसे हो सकती है. मोदी की लखनऊ रैली की तैयारी के लिए यूपी भाजपा के प्रभारी अमित शाह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी, टिकट के दावेदार, आरएसएस के प्रचारक सभी एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. भाजपा ने युवाओं को ललकारा है कि वे मोदी की रैली की तैयारी में 'करो या मरो' की भावना से जुटें. युवा मोर्चा के प्रत्येक पदाधिकारी को जिले आबंटित कर कम से कम पांच दिन का दौरा करने को कहा गया है. दौरे के दौरान भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं को मोदी के फोटो वाली टी शर्टें और टोपियां पहनने को दी जाएंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

मुलायम की झप्पी से झूमे मुसलमान

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का इस्तकबाल कायम है. सपा राज में हुए दंगों से अल्पसंख्यक नाराज भले हो, लेकिन वह समाजवादी पार्टी के प्रति अपनी वफादारी बदलने के मूड में नहीं है. पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के अल्पसंख्यक वोटरों को आज भी यही लगता है कि इनके हित सपा के साथ ही सुरक्षित हैं. अगर ऐसा न होता तो हाल में ही मुलायम की सहारनपुर में हुई 'देश बचाओ, देश बनाओ' रैली जिसका नाम ऐन मौके पर बदल कर 'जलसा-ए-आम' कर दिया गया था, इसमें मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी नहीं करते. भीड़ में अल्पसंख्यकों की अच्छी-खासी भागीदारी देख कर मुलायम गदगद थे तो मंच पर विराजमान थे देवबंदी मसलक के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता और प्रसिद्ध धर्मगुरु जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी. मौलाना मदनी सियासत से दूर रहते हैं. इसीलिए वह सपा के मंच पर भी आने को राजी नहीं थे, लेकिन जब मुलायम की रैली का नाम बदल कर जलसा-ए-आम कर दिया गया तो मदनी नेताजी का आग्रह टाल न सके. मुलायम की सफल रैली से कांग्रेस, बसपा और रालोद नेताओं को सांप सूंघ गया है. तीनों दलों के नेता सपा से नाराज दिख रहे मुसलमानों को अपने पाले में खींचने के लिए तमाम दांवपेंच चल रहे थे. कहा जा सकता है कि मुलायम ने अपने चिरपरिचित अंदाज में झप्पी देकर मुसलमानों को अपने साथ झूमने को मजबूर कर दिया.

मुसलमान ही नहीं, गुर्जर वोटरों को भी लुभाने में भी मुलायम काफी हद तक सफल रहे. गुर्जरों के सर्वमान्य नेता यशपाल सिंह की मंच पर मौजूदगी हैरान करने वाली रही, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह कयास लगाए जा रहे थे कि सपा के बागी नेता रशीद मसूद की वापसी और इनके बेटे शाजान मसूद को लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने से खफा यशपाल बगावती तेवर अपनाए हुए हैं और

किसी भी समय पार्टी छोड़कर जा सकते हैं. रैली में सपा प्रमुख मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने लगातार इस बात का ध्यान रखा कि कहीं मौलाना मदनी और यशपाल सिंह अपने आप को उपेक्षित न महसूस करें. भीड़ के हिसाब से भी यह रैली कामयाब रही. मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पहली बार मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए थे. इनके ऊपर लगातार यह आरोप लग रहे थे कि दंगों के बाद वह एक बार भी पीड़ितों का दर्द बांटने नहीं आए थे, लेकिन जब मुलायम पहुंचे तो सभी की नाराजगी खत्म कर गए.

सहारनपुर की सभा में मुलायम ने अल्पसंख्यकों को काफी चालाकी के साथ लुभाया. मुलायम ने मुसलमानों को पुचकारा जरूर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा कि इनके श्रीमुख से निकले शब्दबाणों से गैर मुस्लिम वोटर नाराज न हो जाएं. किसी भी चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अहम भूमिका निभाता है. मुलायम ने जब खेती सिकुड़ने पर चिंता जताई तो किसानों को लगा कि इनका दर्द कोई तो बांटने वाला है. गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश में करीब 62 फीसद आबादी वाला पिछड़ा तबका किसानों का ही है. गन्ना यहां की मुख्य पैदावार ही नहीं है, बल्कि यहां गन्ने पर सियासत भी खूब होती है. मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, बागपत, मुजफ्फरनगर, बढ़ौत जैसे किसान बाहुल्य क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं को मुलायम से बेहतर शायद ही कोई समझ सकता है. पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी टिकैत सिंह के बाद मुलायम की यहां सबसे अधिक पैठ मानी जाती है. यहां तक कि चौधरी चरण सिंह के पुत्र और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह का भी प्रभाव मुलायम के समाने फीका दिखता है. अजित सिंह से किसानों का मोह भंग हो चुका है. महेंद्र सिंह टिकैत जैसे अब किसान नेता भी नहीं हैं, जिसके पीछे लामबंद होकर यहां के किसान चल सके. मुजफ्फरगनर दंगों के बाद जाट और गुर्जर किसान थोड़ा सपा से नाराज जरूर हुए थे, लेकिन मुलायम एक तरफ मुसलमानों के जख्मों पर मरहम लगा रहे थे तो दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सपा प्रवक्ता, मंत्री और गुर्जर नेता चौधरी राजेन्द्र सिंह के माध्यम से गुर्जरों को भी पटाने का प्रयास कर रहे थे, जिसका प्रभाव मुलायम की सहारपुर रैली में साफ दिखाई दिया.

बहरहाल, मुजफ्फरनगर की घटना के बाद मुस्लिम बाहुल्य जिलों मसलन सहारनपुर, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक हालात बदले हैं. सहारनपुर में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री की सभा में भारी तादाद में मुस्लिमों की मौजूदगी ने कई राजनीतिक संकेत दिए. उक्त जिलों में देवबंदी मुसलमानों की भारी तादाद है. मदनी की देवबंदी मुसलमानों में मजबूत पैठ है. दूसरे मुलायम ने सहारनपुर में इस बिरादरी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और धर्मगुरु रहे शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर मुसलमानों का दिल जीतने का काम किया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को साधने के लिए मुलायम हाल में ही लौटे वरिष्ठ नेता रशीद मसूद का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं. बेटे को लोकसभा का टिकट दिया गया है तो इसके एवज में मसूद पश्चिमी यूपी में सपा को मजबूत करने के लिए कसमें खा रहे हैं. देखना यह है कि मदनी और मसूद सपा के लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे.

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

देश भर के अर्थशास्त्रियों का कुंभ

सैयद शावेज़ फ़िरोज़

वर्तमान समय में जहां टेक्नोलॉजी का आयाम दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास की ओर अग्रसर भारत में भूख के कारण दम तोड़ने की शर्मनाक रिपोर्टें हमें शर्मसार कर रही हैं. इस गंभीर विषय पर गहन विचार-विमर्श और चर्चा-परिचर्चा के लिए भारत में खाद्य सुरक्षा, चुनौतियां एवं सम्भावनाएं पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. यह संगोष्ठी उत्तर प्रदेश के जनपद चन्दौली के मुग़लसराय स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्नात्कोत्तर महाविद्यालय में आयाजित किया गया, जिसमें देशभर से उमड़े अर्थशास्त्रियों का कुंभ जमा हुआ. इन्होंने जहां इस गंभीर मुद्दे पर अपनी चिंता ज़ाहिर की तो वहीं इससे निपटने के लिए सुझाव भी दिए.

भारत में खाद्य सुरक्षा, चुनौतियां एवं सम्भावनाएं पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो पी नाग ने कहा कि यह कॉलेज दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से है, जो काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी भी रहे हैं और इन्होंने ही नारा दिया था कि जय जवान, जय किसान. इनके समय से ही खाद्यान्न सुरक्षा की कमी को पूरा करने एवं हर जन को निवाला मिले, मिशन चला था, जो आज भी जारी है. एमएचआरडीए की शुरुआत भी इसी समय काल में की गई थी. स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी योजनाएं चलीं और सबकी सब असफ़ल रहीं. यह एक प्रश्न है? क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं बनती तो हैं, लेकिन क्रियान्वित ठीक ढंग से नहीं की जाती. कारण राजनीति की चादर आड़े आती है. हर किसी योजना पर राजनीति अपना प्रभाव छोड़ती है. कुलपति ने कहा जल का प्रबंधन, पानी को इकट्ठा करना, उपजाऊ भूमि की सुरक्षा, जमीन का शुद्धीकरण, मौसम बदलने पर वातावरण हवा और पानी के अनुरूप किसानों को सुविधाएं सुलभ कराना, सिंचाई और बीज की उप्लब्धता के साथ-साथ मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था करना इत्यादि अतिआवश्यक है. जब तक यह अनुपालन अमल में क्रियान्वित नहीं किया जाता, तब तक खाद्य सुरक्षा की बात करना बेमानी होगी. यह कहीं स्टोरेज एवं नए रिसर्च की भी आवश्यकता है. खाद्य है, लेकिन वितरण नहीं है. इस्टीमेट, कास्ट और मूल्य का नियंत्रण नहीं.

बतौर मुख्य वक्ता के अनुपस्थिति में आईआईटी रूढ़की विश्वविद्यालय के प्रो डीके नौरियाल ने अर्थशास्त्रियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश बढ़ता रहे, ग़रीब भूखा मरता रहे. यह कैसा विकास. कैसी खाद्य सुरक्षा. देश में पर्याप्त उत्पादन के बावजूद खाद्य सुरक्षा की कमी है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर जो फ़ोकस किया जाता है, इसका 49 प्रतिशत जनसंख्या पर वर्ल्ड लेंडर वेट एंड चिल्ड्रेन ऑफ़ वर्ल्ड से कहीं उपेक्षित है. इन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व में चाइल्ड ब्लास्टिंग पर दूसरे नम्बर पर आता है, जहां खाद्य सुरक्षा की कमी है. बच्चे भूखे मरते हुए कुपोषण के कागार पर पहुंचते हैं. इस दिशा में भी भारत का 38वां स्थान है. यही नहीं, नरेगा का अध्ययन करें तो भी 9.5 प्रतिशत से अधिक का ग्रोथ नहीं है, जबकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रभावी है. फ़िज़ीकल अवेलेबलिटी ऑफ़ फूड की दशा इतनी दयनीय है कि आज भारत के एफ़सीआई गोदामों में गेहूं पड़ा रहता है. लोगों तक नहीं पहुंचता है. नौरियाल ने एक अध्ययन रिपोर्ट का ताज़ा हवाला देते हुए बताया कि 85 करोड़ गेहूं डैमेज हो जाता है, जो एफ़सीआई के गोदामों में सबसे ज़्यादा बिहार और महाराष्ट्र में डम्प होता है. जब सवाल यह होता है कि 60 प्रतिशत नॉन आईडेन्टीफ़ाई लोगों तक कैसे पहुंचे. सब कुछ तो बढ़िया होता है, जब खाद्य सुरक्षा बिल लागू होता है. राष्ट्रीय कृषि योजनाएं चलती हैं, लेकिन समय से लागू नहीं हो पाती हैं. यही वजह है कि आज भी हमारे देश में अच्छी पैदावार, अच्छा उत्पादन, बेहतर आर्थिक नीति लागू होने के बावजूद भी खाद्य सुरक्षा की ढेर सारी कमियां व्याप्त हैं, जो एक चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमें इसकी सम्भावनाओं पर तलाश जारी रखनी होगी. सरकार को अपने इश्यूज़ को बढ़ाने पड़ेंगे.

इसके पूर्व अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ सुरेन्द्र मिश्रा ने विषय परिवर्तन करते हुए कहा कि नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई. इसके बाद भी सिंचाई के साधन विकसित नहीं, नहरें नहीं, यह सब देश को शर्मसार करने वाला तथ्य है. किसान मेहनत करता है, लेकिन समय से इसका मेहनताना नहीं मिल पाता है. अतिथियों का स्वागत करते हुए कॉलेज की प्राचार्या डॉ पुष्पा सिंह ने कहा कि विशिष्ट पर्व के समान है यह आयोजन. इसके माध्यम से कह रही हूं कि यदि खाद्य सुरक्षित नहीं है तो ग़रीबों को कैसे सुलभ हो इस पर सम्भावनाएं तलाशनी हैं. सेमिनार का उद्घाटन देश भर से आए वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के साथ विद्यापीठ के कुलपति प्रो पी नाग ने मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन कर किया. इस कार्यक्रम में दूसरे दिन भी भारत में खाद्य सुरक्षा, चुनौतियां एवं सम्भावनाएं पर विचार-विमर्श किया गया. पटना के एएन सिंह इंस्टीट्यूट के निदेशक डीएम दिवाकर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एक गंभीर विषय होते हुए भी आज राजनीति का विषय बन गई है. आज़ादी के बाद उत्पादन जब आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, तब पीडीएस के माध्यम से अनाज लोगों तक पहुंचाया गया. इन्होंने कहा कि रेवड़ियों की तरह आरटीआई, मनरेगा और अब खाद्य सुरक्षा का अधिकार बांटा जा रहा है. मुम्बई से आए प्रो घन्श्याम सिंह ने कहा कि भूखा व्यक्ति अच्छा होता है, लेकिन अर्द्ध भूखा व्यक्ति ख़तरनाक होता है और वर्तमान में अर्द्ध भूखा ही बनाने की कोशिश की जा रही है, जो ठीक नहीं है. जब तक राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी रहेगी. कोई भी परिवर्तन सम्भव दिखाई नहीं देता. अतिथियों का स्वागत डॉ अनिल यादव व धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्या पुष्पा सिंह ने किया.

इस मौके पर दोनों दिनों में पूर्वांचल समेत देशभर से काफ़ी तादाद में अर्थशास्त्रियों का जमावड़ा एलबीएस पीजी कॉलेज में लगा हुआ था, जिन्होंने उत्साह एवं जोश के साथ सेमिनार में भाग लिया. कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने भी इसमें विशेष रूचि दिखाई, जिसमें प्रमुख रूप से आगरा विश्व विद्यालय के कुलपति प्रो0 एम मुज़म्मिल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रो डॉ अशोक मित्तल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो प्र लाद कुमार, डीएस पीजी कॉलेज मीरज़ापुर के डॉ राजेश श्रीवास्तव, सकलडीहा पीजी कॉलेज के डॉ इन्द्रदेव सिंह, काशी विद्यापीठ के प्रो आरपी सेन, राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय के डॉ जेपी मिश्रा, मेरठ विश्वविद्यालय के के डॉ राजनाथ, जगतपुर पीजी कॉलेज के डॉ निरंजन सिंह, आज़मगढ़ के कौशलेन्द्र मिश्रा, रसड़ा के डॉ आरके उपाध्याय, सुधाकर महिला पीजी कॉलेज के डॉ पीएन दूबे, वाराणसी के डॉ परमहंस एवं डॉ विश्वनाथ कुमार इत्यादि योजक कॉलेज के डॉ अनिल यादव, डॉ इशरत जहां, डॉ आकाश गुप्ता, डॉ मंजुला, डॉ योगेन्द्र ओझा, डॉ गुलज़बीं अन्सारी, डॉ हरिशचन्द्र सिंह, डॉ वीजेन्द्र पांडेय, डॉ राजीव कुमार एवं प्रबन्धक राजेश कुमार तिवारी उपस्थित रहे. सेमिनार का संचालन डॉ श्याम कार्तिक मिश्र ने किया. ■

फर्जी डॉक्टर करता था नीली बत्ती का इस्तेमाल

प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

पीलीभीत में एक ऐसे डॉक्टर का खुलासा हुआ है, जो अपने को कई सालों से कैंसर रोग विशेषज्ञ बता रहा था. उस तथाकथित डॉक्टर का नाम सीपीएन सिंह है. यह डॉक्टर खुद को सीएमओ कहता था और गैरकानूनी तरीके से अपनी गाड़ी पर नीली बत्ती का इस्तेमाल करता था. पहली बार इस फर्जी डॉक्टर को यातायात प्रभारी जबर सिंह मलिक ने वाहनों की चैकिंग के दौरान पकड़ा. डॉक्टर नीली बत्ती लगे हुए लक्जरी सफारी गाड़ी में सवार होकर हूटर बचाते हुए जा रहा था, तभी उसकी तामझाम वाली गाड़ी पर जबर सिंह मलिक की नजर पड़ी. जबर सिंह ने उसे रुकने का इशारा किया. सफारी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर पुलिस की वर्दी में एक युवक गाड़ी चला रहा था. जबर सिंह के गाड़ी रुकवाने के सवाल पर वह ड्राइवर बोला कि आपने गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे की. उसने कहा कि यह गाड़ी सीएमओ

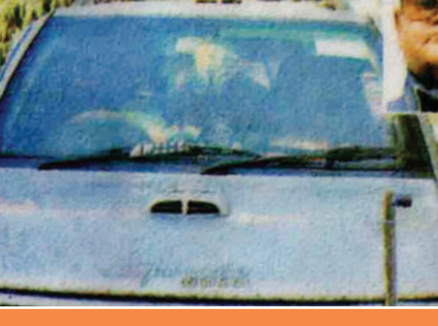

साहब की है और वह पीछे बैठे हुए हैं. ए.टी.एस.आई. ने जब गाड़ी के कागज मांगे तो वह इधर-उधर की बातें करने लगा. इससे टी.एस.आई. को शक हुआ कि एक सी.एम.ओ. स्तर का अधिकारी अपनी गाड़ी पर इतनी लाइटें नहीं लगवा सकता है. इन्होंने थाना सुनगढ़ी, एस.ओ. के पी सिंह को घटना की जानकारी दी. वाहन की तलाशी के दौरान गाड़ी में विजिटिंग कार्ड भारी मात्रा में बरामद हुए, जिन पर सुपर सर्जन सी एम ओ, कैंसर संस्थान, लखनऊ लिखा हुआ था, लेकिन डॉ सीपीएन सिंह की किसी भी धौंस में न आते हुए इन्हें गाड़ी सहित थाना सुनगढ़ी लाया गया, जहां पर वह सीएमओ से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके. बात खुलने पर पता चला कि वह फर्जी विजिटिंग कार्ड छपवाकर जिले व बाहर के अन्य जिलों में मौजूद प्राइवेट प्रैक्टिशनर और डॉक्टर्स से अपने को सीएमओ बताते हुए विगत कई वर्षों से अवैध धन उगाही के कार्य में लगे हुए थे. पुलिस ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर इन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया और इसी दिन शाम को इन्हें थाने से छोड़ भी दिया गया. जनचर्चा है कि पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार व सरकार में बैठे चन्द असरदार लोगों के दबाव में आकर डॉक्टर को इतने गंभीर आरोप में थाने से जमानत दे दी गई. वर्तमान में आवास विकास कालोनी पीलीभीत में अपनी प्राइवेट डिस्पेंसरी चला रहा है, जिस पर इसने अपने नाम के बड़े-बड़े बोर्ड भी लगवा रखे हैं. कैंसर रोग विशेषज्ञ वर्तमान सीएमओ राकेश तिवारी के संज्ञान में जब यह घटना आई थी तो इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी सख्त कार्रवाई डॉ सीपीएन सिंह के विरुद्ध नहीं की. जब इस बाबत सीएमओ राकेश तिवारी से जानकारी ली गई तो इन्होंने बताया कि जांच चल रही है. आखिर यह कैसी जांच है कि खुलेआम एक डॉक्टर नगर में कई वर्षों से अपने को कैंसर रोग विषेशज्ञ बताकर लोगों का आर्थिक व मानसिक शोषण करता आ रहा है और नीली बत्ती लगी सफारी गाड़ी में घूमता चला आ रहा था. सवाल यह उठता है कि आखिर किस अधिकारी, नेता, मंत्री या असरदार लोगों का इसके पीछे हाथ है. इस बात का खुलासा होना चाहिए. ■

उत्तराखंड कांग्रेस में आपसी अंतर्कलह

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में कांग्रेस का आपसी कलह हाईकमान द्वारा मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के एक पखवारे बाद ही अंदरूनी कलह सामने आने से कांग्रेस के मैनेजरों के माथे पर पसीना साफ झलकने लगा है. बहाना इस बार पोर्टफोलियो बंटवारे में हो रहे विलंब को मानें या फिर सत्ता के नए समीकरणों की पैदाइश को, कांग्रेस के भीतर पनप रहा असंतोष सार्वजनिक हो गया है. इस बार मोर्चा कांग्रेस के दिग्गज नेता वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने खोला है. तमाम कारणों से हरीश रावत से खफा डॉ. हरक ने सियासी हलकों में यह कह कर सरगर्मी पैदा कर दी कि मुख्यमंत्री कहें तो वह तत्काल मंत्री पद छोड़ देंगे. पोर्टफोलियो बंटवारे की हिमायत करते हुए हालांकि इन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का अधिकार है, विधायक तो जनता बनाती है. इस कलह को हवा देने में अग्रणीय भूमिका पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, सांसद सतपाल महाराज भी अपने अंदाज में निभाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं. हरीश रावत को आम चुनाव के चन्द दिनों पहले कांग्रेस हाईकमान को एक गोपनीय रिपोर्ट मिली कि बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो राज्य में पूरी तरह से साफ हो जाएगी. उत्तराखण्ड में पांच लोकसभा सीटें हैं. पिछले आम चुनाव में पांचों की पांचों सीटें कांग्रेस के पाले में चली गईं थीं. मुख्यमंत्री बन कर बहुगुणा राज में हुए उप चुनाव में मुख्यमंत्री पुत्र साकेत को चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इस हार का भी कारण कांग्रेस के दिग्गजों का आपसी कलह ही रहा. सूबे में सत्ता पर काबिज कांग्रेस के अंदरूनी कलह की परिणति अभी दो हफ्ते पहले सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के रूप में हुई. अब नए निजाम के साथ भी वही पुरानी कहानी दोहराई जाने लगी है. अंतर इतना है कि बस किरदार बदल गए हैं. पहले जो विरोधी खेमे में थे, वे बगलगीर हैं, जबकि पिछली सरकार में सत्ता की नजदीकी का लुत्फ उठा चुके अब पाले के दूसरी ओर खड़े नज़र आ रहे हैं. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने योजनाबद्ध तरीके से अब तक मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं किया है. वह इसे बजट सत्र तक खींचना चाहते हैं और इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं. इनकी टीम के सदस्यों को मुख्यमंत्री का यह रुख रास नहीं आ रहा है. इसका कारण यह कि

> **17 दिन बाद भी हरीश रावत ने मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे हैं. विपक्ष कह रहा है कि मंत्रियों के पास विभाग ही नहीं हैं तो वे विभागों से जुड़े जवाब किस हैसियत से दे रहे हैं. सत्ता पक्ष के दो विधायक भी इस पर सवाल उठा चुके हैं. पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत से जनता को जितनी उम्मीदें थीं, वह सब धरी की धरी रह गई हैं.**

बजट सत्र के तुरंत बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और फिर लोकसभा आम चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी. अगले कई महीनों तक मंत्रियों के हाथ बंधे रहेंगे.

मुख्यमंत्री के इस स्टैंड पर फिलहाल अन्य मंत्री तो चुप्पी साधे हुए हैं. अपनी बेबाकी एंव दबंगई के लिए जाने जाने वाले वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए मोर्चा खोल दिया है. कैबिनेट बैठक में सीएम विवेकाधीन कोष से स्वीकृत धनराशि जारी न किए जाने पर अपना असंतोष दर्ज करा चुके रावत ने यह बयान देकर मामले को तूल दे दिया. डॉ. हरक सिंह रावत की नाराजगी का एक बड़ा कारण पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ को बगैर इन्हें विश्वास में लिए राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना भी है. बकौल रावत, पिछली सरकार के दौरान कृषि मंत्री रहते हुए वह इसके अध्यक्ष बने. लिहाजा, बेहड़ की नियुक्ति से पहले इन्हें भी इस संबंध में विश्वास में लिया जाना चाहिए था. पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी कहा कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए मंत्रियों के विभाग जल्द बंट जाने चाहिए. इन्होंने कहा कि सभी मंत्री तजुर्बेकार हैं. वे दो वर्ष से कार्य कर रहे हैं. इन्हें पता है कि क्या समस्या है और क्या समाधान है. बहुगुणा के इस बयान के भी राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री हरीश रावत को एक पखवारे बाद भी अपने मंत्रियों के विभाग का बंटवारा न कर पाना सरकार के गले की फांस बन गया है. विपक्ष ने विभाग न बंटने को लेकर मंत्रियों में असंतोष का मुद्दा उठाया. भाजपा की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. प्रतिकात्मक यह अविश्वास का प्रस्ताव सरकार की सेहत पर कोई खास असर नहीं डाल सका. फिर भी राजनीति में एक संदेश तो दे ही गया. मंत्रियों के विभागों को लेकर विपक्ष पहले से ही विधानसभा में सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा है. अब निगमों के अध्यक्ष पद को लेकर मंत्री हरक सिंह की नाराजगी और विजय बहुगुणा व सतपाल महाराज की मुख्यमंत्री हरीश रावत को असंतोष दूर करने की नसीहत ने आग में घी डालने का काम किया, जिससे यह मुद्दा ज्यादा गरमाया.

17 दिन बाद भी हरीश रावत ने मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे हैं. विपक्ष कह रहा है कि मंत्रियों के पास विभाग ही नहीं हैं तो वे विभागों से जुड़े जवाब किस हैसियत से दे रहे हैं. सत्ता पक्ष के दो विधायक भी इस पर सवाल उठा चुके हैं. पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत से जनता को जितनी उम्मीदें थीं, वह सब धरी की धरी रह गई हैं. मुख्यमंत्री द्वारा 17 दिन बाद भी अपने मंत्रियों को विभाग न बांटने से जो संवैधानिक संकट राज्य में उत्पन्न हुआ है, वह इतिहास में पहली बार है. डाम कोठी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चेहरा बदलने से राज्य का भला नहीं होगा. इन्होंने कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी का कांग्रेसीकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार कांग्रेस भवन में लगाया जा रहा है तो हरिद्वार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक कांग्रेस नेता के आश्रम में ली जा रही है, जो किसी भी हालत में उचित नहीं है. निशंक ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस संसदीय परम्पराओं का कत्ल कर रही है. सदन की मान- मर्यादाओं को तार-तार कर रही है. इन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक अपने मंत्रियों को विभाग न बांटे जाने पर सरकार को विफल करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों पर विश्वास ही नहीं है और मंत्रियों का भी विश्वास मुख्यमंत्री से उठ रहा है. नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस की इस अंतर्कलह से प्रदेश का विकास बाधित हो रहा है. इन्होंने मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाए जाने की भी कड़ी निंदा की. साथ ही इसे पंचायत चुनाव से पूर्व जनता को कांग्रेस के पक्ष में लुभाने की कांग्रेस सरकार की अलोकतांत्रिक कोशिश करार दिया. नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी के एक पखवारे बाद भी मंत्रियों को विभाग न दिए जाने को विपक्ष ने सत्तारूढ़ कांग्रेस की आपसी खींचतान का उदाहरण बताया.

राजनीति के मर्मज्ञ मानते हैं कि इस कलह को कांग्रेस हाईकमान समय रहते नहीं रोक सकी तो आपदाग्रस्त राज्य में लक्ष्य के हाफ पर भी हरीश अपनी इज्जत नहीं बचा पाएंगे. कांग्रेस का साफ होना दिग्गजों का आपसी कलह ही कारण बनेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

इस बार बसपा मुस्लिम ब्रह्मास्त्र चलाएगी

दर्शन शर्मा

यूपी में सोशल इंजीनियरिंग के बल पर 2007 के विधानसभा चुनाव में जीत का स्वाद चख चुकी बसपा लोकसभा चुनाव में एक बार फिर ऐसा ही कुछ कमाल दिखाने की कोशिश कर रही है. ब्राह्मण कार्ड खेलने वाली बसपा की निगाह मुस्लिम वोट बैंक पर है. इसी के तहत मतदाताओं के मूड को भांपते हुए बसपा का मुस्लिम प्रेम बढ़ने लगा है. मुजफ्फरनगर और शामली सांप्रदायिक दंगों ने इसके इस प्रेम को और बढ़ा दिया है. इसी बिना पर बसपा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से करीब बीस से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटी है. बसपा को मालूम है कि मुजफ्फरनगर और शामली में हुए दंगों ने राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर डाला है. दंगे को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओ की भी

तीखी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं. इन्होंने सपा सरकार की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लगाने में गुरेज नहीं किया. इससे बसपा को अनुमान है कि मुस्लिमों की नाराजगी उत्तर प्रदेश में असर डालेगी. बसपा के दिग्गजों को यकीन है कि सपा का मुस्लिम मतदाता इससे दूर होता जा रहा है, जिसकी बदौलत सपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया था. बसपा को यह भी एहसास हो चला है कि लोकसभा चुनाव में यह मुस्लिम समाज कांग्रेस से भी नाराज है. महंगाई और भ्रष्टाचार ने इसकी कमर तोड़ दी है. वह कांग्रेस के विरुद्ध बह रही हवा को भी भांप चुका है. चार राज्यों में मिली पराजय के कारण कांग्रेस के वोट बैंक का स्तर काफी नीचे आ गया है. ऐसे में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का साथ देकर अपना वोट खराब करना नहीं चाहेगा. बसपा की सोच है कि प्रदेश में उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार वह मुस्लिम वोट को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है. यही कारण है कि बसपा के कार्यकर्ता और नेता चुनावी सभाओं में बसपा सरकार द्वारा मुस्लिम हित में किए गए पुराने कार्यों को गिनाने में भूल नहीं कर रहे हैं. इसी रणनीति के साथ ही इस बार बसपा लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में मुस्लिम प्रत्याशियों को खास तवज्जो दे रही है. राजनीति के जानकारों का मानना है कि बसपा लोकसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या पिछले चुनाव की अपेक्षा डेढ़ से दो गुना कर सकती है.

अब तक शांत दिखने वाली बसपा लोकसभा चुनाव में पूरा दमखम दिखाने को उतावली दिख रही है. दूसरे दलों की तरह वह भी एक-एक बूथ की गणना करने में लगी है. वैसे बसपा सुशुप्त ज्वालामुखी की तरह काम करने में माहिर मानी जाती है. कई बार ऐसे आंकड़े देखे गए, जो चौंकाने वाले साबित हुए थे. माना यह जा रहा है कि बसपा यूं ही हवा में तीर नहीं चला रही है. कहीं न कहीं इसकी मजबूती अंदरूनी तौर पर हो रही है. खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाली बसपा इस बार फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है. सपा की प्रबल विरोधी बसपा सियासी आंकड़ों का भी सहारा ले रही है. पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों पर जिन संभावित उम्मीदवारों के नाम तय कर रखे हैं, इनमें से सत्रह मुस्लिम हैं. इन नामों में सीतापुर से वर्तमान सांसद कैसरजहां, रायबरेली से परवेज, धौरहरा से दाऊद अहमद, गोंडा से अकबर अहमद डम्पी, अकबरपुर से अनिल वारसी, कैराना से कमर हसन, मुजफ्फरनगर से कादिर राणा, सम्भल से वर्तमान सांसद शफीकुर्रहमान बर्क, देवरिया से नियाज अहमद, मेरठ से खालिद एखलाक, कानपुर नगर से सलीम खां, फतेहपुर से अफजल सिद्दीकी, बदायूं से शाहिद, एटा से नूर मोहम्मद व रामपुर से अकबर हुसैन आदि के नाम प्रमुख माने जा रहे हैं. पार्टी नेता इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि बदले हालात में मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों की संख्या में और इजाफा हो सकता है. हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती इन इम्मीदवारों का चयन कर लिस्ट भी तैयार कर चुकी हैं, लेकिन इसे अधिकृत रूप से जारी करने से पहले इन्हें भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची का इंतजार है.

बहरहाल, मायावती सपा सरकार को अपने टारगेट पर लिए हुए हैं. वे कई बार सपा सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर चुकी हैं. वे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर संसद भवन परिसर तक में कह चुकी हैं. प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है और राज्यपाल और केन्द्र सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए. सपा सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए. मथुरा में एक बलात्कार पीड़ित महिला की हत्या पर पूछे गए प्रश्न पर इनका जवाब था कि बलात्कार पीड़ित महिला अपनी मां के साथ अपना बयान दर्ज कराने गई, लेकिन वह वहां नहीं पहुंच सकी. अपराधियों ने इस पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप एक महिला मारी गई तथा दूसरी जीवन और मौत से जूझती रही. हमारे भाइयों एवं बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं. निर्दोष मारे जा रहे हैं. मुरादाबाद में भी ऐसा ही हुआ. मुरादबाद में एक डॉक्टर के घर लूट हुई. प्रदेश में अराजकता व्याप्त है. कानून व्यवस्था चरमरा गई है. सपा के किसी मंत्री ने इन घटनाओं पर प्रतिक्रया व्यक्त नहीं की, लेकिन जब किसी मंत्री की भैंसें चोरी होती हैं या मंत्री से जुड़ी कोई छोटी-मोटी घटना होती है, तो पूरा तंत्र लग जाता है और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होती है. वहीं सपा प्रवक्ता का कहना है कि बसपा शासन में जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ, इससे जनता पूरी तरह परिचित है. सपा सरकार से जनता खुश है. इस सरकार ने मुफ्त दवाई, सिंचाई, पढ़ाई की बदौलत जनता का दिल जीत लिया है. ■

श्रावस्ती में दलों की अन्तर्कलह

राकेश चन्द्र श्रीवास्तव

भारत-नेपाल सीमा पर बसा श्रावस्ती में मिशन 2014 को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है. सभी राजनीतिक दल शतरंजी बिसात पर अपनी गोटें बिछाने में लगे हैं. भाजपा और कांग्रेस की उर्वरा भूमि रही श्रावस्ती में इन दलों में आपसी अन्तर्कलह जारी है. श्रावस्ती के तिलहर गांव में राहुल गांधी का 24 घंटे का प्रवास कांग्रेस सांसद की नदारदगी और उपेक्षा के चलते तेजाबी वर्षा में बदल गया है. बाहुबली अतीक अहमद की सपा से आमद होने के बाद शांति और सद्भाव के क्षेत्र में अनहोनी की प्रेतछाया पड़ने लगी है. बसपा ने पूर्व मन्त्री लालजी वर्मा को टिकट देकर अन्य दलों के समीकरण को गड़बड़ कर दिया है.

22 मई, 1997 को श्रावस्ती जनपद के सृजन के बाद यहां 2009 में श्रावस्ती लोकसभा का गठन होने के बाद पहली बार लोकसभा का चुनाव सम्पन्न हुआ. इस चुनाव में कांग्रेस के विनय कुमार पांडेय सांसद निर्वाचित हुए, जिन्होंने बसपा के रिजवान जहीर को हराया. सपा से श्रीमती रूबाब सईदा और भाजपा से सत्यदेव सिंह तीसरे और चौथे नम्बर पर रहें. श्रावस्ती में पहली बार हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराया, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में श्रावस्ती लोकसभा सीट से जुड़े पांचों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और श्रावस्ती से जुड़े भिनगा से इन्द्राणी वर्मा श्रावस्ती से हाजी रमजान, बलरामपुर से जगतराम पासवान तुलसीपुर से मसूद अहमद और गौसड़ी से एस.पी. यादव ने चुनाव जीतकर सपा का परचम लहराया और यहीं से कांग्रेस की लोकप्रियता पर ग्रहण लगना शुरू हो गया. 23 सितम्बर, 2009 को राहुल गांधी अचानक बिना किसी सूचना के श्रावस्ती के तिलहर नामक गांव आए और छेदी पासवान के घर भोजन कर गांव वालों के बीच पूरी रात गुजारी और विकास का वायदा भी किया, लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद आज तक क्षेत्रीय सांसद ने इस गांव की सुधि नहीं ली. क्षेत्र से बराबर नदारद रहने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं जनता में रोष व्याप्त है. यदि कांग्रेस आलाकमान इन्हें दोबारा चुनाव लड़ाता है तो इन्हें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे. वर्तमान सांसद के अलावा यहां से शरद त्रिवेदी और प्रदेश कांग्रेस महासचिव असलम रायनी भी टिकट की दौड़ में बताए जाते हैं.

श्रावस्ती में भाजपा संगठन की मजबूती के बाद भी नेताओं में ज्यादा अन्तर्कलह और सिरफुटौव्वल जारी है. बसपा से भाजपा में शामिल पूर्व मन्त्री दद्दन मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष राम फेरन पांडेय, सुभाष त्रिपाठी, अनुपमा जायसवाल, रमाकान्त तिवारी, पदमसेन चौधरी, शैलू सिंह, सत्यदेव सिंह, हनुमन्त सिंह, श्रावस्ती लोकसभा सीट से भाजपा के दावेदार बताए जा रहे हैं. भाजपा जिलाध्यक्ष को छोड़कर सभी नेता एक-दूसरे की टांग खींचने मे मशगूल हैं. भाजपा का गांव-गांव संगठन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के अति करीबी माने जाने वाले जिलाध्यक्ष राम फेरन पांडेय सबसे सशक्त प्रत्याशी साबित हो सकते हैं. अनुपमा जायसवाल की भी छवि साफ-सुथरी है. समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले यहां कद्दावर मुस्लिम नेता और पूर्व मन्त्री डॉ वकार अहमद शाह के बेटे मटेरा (बहराइच) विधायक यासर शाह को टिकट दिया और बाद में इनका टिकट काटकर तुलसीपुर के विधायक मसूद अहमद को टिकट दिया गया. यासर शाह को प्रदेश कबीना में राज्यमंत्री बनाकर मसूद अहमद का टिकट काटकर अब बाहुबली अतीक अहमद को श्रावस्ती लोकसभा से टिकट दिया गया है. अतीक अहमद ने क्षेत्र का दौरा करना भी शुरू कर दिया है. हालांकि जनता में खौफभरी खामोशी व्याप्त है. बसपा ने पूर्व मन्त्री लालजी वर्मा को श्रावस्ती लोकसभा का टिकट देकर सभी दलों के समीकरण को बिगाड़ दिया है. लालजी वर्मा यहां मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं.

सपा और बसपा ने हालांकि अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस और भाजपा ने अभी तक किसी को चुनाव लड़ाने की हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन देखना यह है कि कांग्रेस हाईकमान वर्तमान सासंद पर ही पुनः दांव लगाने की कोशिश करती है या किसी दूसरे प्रत्याशी को उतारकर कांग्रेस की नैय्या पार लगाने की कोशिश. श्रावस्ती लोकसभा के पांचो विधानसभा में सपा विधायकों के रहते क्या बाहुबली अतीक अहमद जनता के विश्वास पर खरे उतरते हैं. बसपा क्या यहां पहली बार परचम लहराने में सफल होती है या सिरफुटौव्वल और अन्तर्कलह से जूझ रही भाजपा एक सशक्त प्रत्याशी उतारकर नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की सार्थक पहल करती है. श्रावस्ती में सभी दल राजनीतिक द्राक्षावल्लरी में फंसे मिशन 2014 के अंगूर को खाने के लिए लालायित हैं. देखना यह है कि यह अंगूर किस दल के लिए मीठा साबित होता है. ■

पर्यटन व पुरातत्व के मकड़जाल में मणि पर्वत का सुंदरीकरण

राकेश कुमार यादव

पर्यटन व पुरातत्व विभाग के मकड़जाल में अयोध्या का प्रसिद्ध मणि पर्वत का सुन्दरीकरण उलझ कर रह गया है. मौजूदा सत्र में उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव (गृह) की कवायद भी रंग नहीं ला पा रही है. शासन के आदेश के बाद अगस्त माह में केवल टूटी बाउंड्रीवाल पर लीपापोती करके शासन के आदेश का पालन करा दिया गया. एक दशक पहले 80 लाख 77 हजार रुपये मणि पर्वत के जीर्णोद्धार के लिए अवमुक्त किया गया था. कागजों पर सारी धनराशि खर्च दिखा दी गई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा. पर्यटन विभाग और केन्द्रीय पुरातत्व विभाग की खींचतान का नतीजा यह निकला कि धर्मनगरी अयोध्या के पौराणिक महत्व के मणि पर्वत के जीर्णोद्धार का कार्य अधर में आज तक लटका हुआ है. यही नहीं, कार्यदायी संस्था ने टीले की सीढ़ियों के निर्माण के लिए इस तरह खुदाई शुरू कराई थी कि इस ऐतिहासिक स्थल का नामोनिशान वर्षा ऋतु में खत्म होने का खतरा उपस्थित हो गया था.

मणि पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 1997 में पर्यटन विभाग ने 80 लाख 47 हजार रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी थी. तत्कालीन लोकनिर्माण व पर्यटन मंत्री कलराज मिश्र ने जीर्णोद्धार कार्य का विधिवत उद्घाटन भी किया था. उद्घाटन के उपरान्त कार्यदायी संस्था निर्माण निगम ने कार्य आरम्भ कराया. सुन्दरीकरण का कार्य एक वर्ष तक चलता रहा. निर्माण के रूप में मणि पर्वत के आसपास सड़कों का निर्माण और रैन बसेरा बनवाया गया. निर्माण निगम ने मणि पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए नई सीढ़ी का निर्माण और विद्युतीकरण तथा पेयजल सुविधा के लिए स्वीकृत धन से कार्य शुरू किया. सीढ़ी निर्माण के लिए मणि पर्वत की मिट्टी की खुदाई शुरू कर दी गई. इसी बीच पुरातत्व विभाग ने आपत्ति दाखिल की. नतीजतन कार्यदायी संस्था को सभी निर्माण कार्य आधा-अधूरा छोड़ देना पड़ा. पुरातत्व विभाग का तर्क है कि मणि पर्वत फैजाबाद-अयोध्या की ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों में से एक है तथा पुरातत्व संरक्षण विभाग ने इसे संरक्षित घोषित किया है. इसलिए इस ऐतिहासिक स्थल पर कोई दूसरा विभाग हस्तक्षेप नहीं कर सकता. पुरातत्व विभाग का तर्क है कि दूसरे विभाग के मनमाने ढंग से की जा रही छेड़छाड़ मणि पर्वत का पुरातात्विक महत्व प्रभावित करेगा. इस आपत्ति के बाद चल रहा निर्माण पूरी तरह रोक दिया गया.

गौरतलब है कि सुन्दरीकरण कार्य रुकने के बावजूद पुरातत्व विभाग ने मणि पर्वत के संरक्षण के लिए आजतक कोई कार्रवाई नहीं किया है. नतीजतन जो निर्माण कार्य दस वर्ष पहले हुआ था, वह भी खंडहर में तब्दील होता जा रहा है. सीढ़ी बनाने के लिए खोदी गई मिट्टी के कारण वर्षा ऋतु में मिट्टी बैठने का खतरा और मंदिर के गिरने का भय उत्पन्न हो जाता है. दूसरी ओर बिजली की रोशनी के लिए लगाए गए खम्भों में अक्सर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है. रैन बसेरा वर्षों से बन्द पड़ा है और उद्घाटन के इंतजार में निरन्तर बदशक्ल हो रहा है. दो विभागों के आपसी तालमेल और जिला प्रशासन का सूझबूझ न होना मणि पर्वत के जीर्णोद्धार को आगे नहीं बढ़ा रहा है. दूसरी ओर सावन झूला मेला 2013 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव गृह ने फैजाबाद के जिलाधिकारी को मणि पर्वत की टूटी और जर्जर दीवाल तथा मंदिर पर चढ़ने के लिए बने स्लोप के धंस जाने आदि की तत्काल दुरुस्तीकरण कराए जाने का निर्देश दिया था. 27 जुलाई, 2013 की राजाज्ञा में प्रमुख सचिव गृह ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया था कि अयोध्या स्थित मणि पर्वत का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में पाया गया कि मणि पर्वत पर दर्शन के लिए चढ़ने वाले स्लोप के सपोर्ट में बनी दीवार गिर गई है. स्लोप के ऊपरी सिरे पर गर्भ गृह के पास निर्मित सीढ़ियों से जुड़ी सुरक्षा दीवाल झुक गई है, जो कभी भी गिर सकती है. स्लोप के एक साइड में कटान होने के कारण स्लोप धंस गया है. कहीं-कहीं मंदिर की दीवार भी धंसान के कारण क्रेक हो गई है, जिसे तत्काल ठीक कराया जाना अपरिहार्य है. इस सम्बन्ध में सुपरिन्टेंडिंग ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लखनऊ को मणि पर्वत के मरम्मत के लिए दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं.

> **गौरतलब हैं कि सुन्दरीकरण कार्य रुकने के बावजूद पुरातत्व विभाग ने मणि पर्वत के संरक्षण के लिए आजतक कोई कार्रवाई नहीं किया है. नतीजतन जो निर्माण कार्य दस वर्ष पहले हुआ था, वह भी खंडहर में तब्दील होता जा रहा है. सीढ़ी बनाने के लिए खोदी गई मिट्टी के कारण वर्षा ऋतु में मिट्टी बैठने का खतरा और मंदिर के गिरने का भय उत्पन्न हो जाता है. दूसरी ओर बिजली की रोशनी के लिए लगाए गए खम्भों में अक्सर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है.**

शासन के दिशा निर्देश के बाद जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग सक्रिय तो हुआ, लेकिन केवल सीढ़ियों से जुड़ी सुरक्षा दीवाल की मरम्मत कराकर कर्त्तव्यों की इतिश्री कर दी गई. उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफीसर ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सावन झूला मेला में मणि पर्वत पर अनुमानित 3 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ होती है. निरीक्षण में पाया गया है कि मणिपर्वत के शीर्ष पर स्थित मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन्हीं सीढ़ियों और स्लोप के माध्यम से आते जाते हैं. यदि इसे तत्काल ठीक नहीं कराया गया तो कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पुरातत्व विभाग द्वारा मणि पर्वत के रखरखाव, मरम्मत, सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण इस प्राचीन स्थल का दिन-प्रतिदिन क्षरण हो रहा है. फिलहाल पुरातत्व विभाग की अड़चन के कारण जर्जर मणि पर्वत और मंदिर का जीर्णोद्धार सम्भव नहीं दिखाई पड़ रहा है. मणि पर्वत मंदिर के महन्त रामचरन दास बताते हैं कि यदि इसी तरह दो बरसात और हुई और मंदिर व पर्वत उपेक्षित रहा तो इसका निशान मिट जाएगा. ■